

Policy

WATCH

Volume X, Issue 3
March 2021, New Delhi

Growth with Employment

In this issue

भारत की आजीविका
परिस्थिति २०२०
एवं परिणति २०३०



Image Courtesy: <https://www.theindiaforum.in/sites/default/files/field/image/2019/10/01/Ramkumar%20Radhakrishnan%2C%20Wikimedia-1569929663.jpeg>



RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

POLICY WATCH

Volume X, Issue 3
March 2021, New Delhi

5 भारत की आजीविका
परिस्थिति २०२०
एवं परिणति २०३०

Editorial

The Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies (RGICS) works on five themes:

1. Constitutional Values and Democratic Institutions
2. Growth with Employment
3. Governance and Development
4. Environment, Natural Resources and Sustainability
5. India's Place in the World.

Under the Growth with Employment theme, there are three sub-themes:

- a. Job Creation based on Natural Resource Regeneration and the Non-Farm Sector
- b. Innovation, Skills, and Entrepreneurship for MSMEs and Services
- c. Financial Inclusion and Innovation as a Driver of Inclusive Self-Employment

This issue of Policy Watch carries the overview chapter of the State of India's Livelihoods (SOIL) Report, 2020, which was edited by Vijay Mahajan, Director, RGICS. The SOIL Report is released every year at the Livelihoods India Summit organised annually by Access Development Services, New Delhi. This year the Summit was virtual and was held on 28 and 29th January.

In a break from the past, this year's SOIL Report focuses a lot more on the future and specifically identifies the livelihood challenges of this decade 2021-2030. In terms of numbers, about 12 crore new livelihoods need to be created in this decade to meet the projected increase in the labour force, and a lot of the incremental employment will have to be in the non-agriculture sector and away from rural areas. Thus the report recommends a focus on sectors such as agricultural services, construction, handicrafts and small-scale manufacturing, and services of both the proximate and those that can be remotely delivered digitally.

The report argues that even to sustain the existing level of employment in agriculture, massive investments are needed in regenerating natural resources – land water and forests. It also argues for a serious focus on improving the quality of school education and vocational training. The report estimates the investment requirements at about 10 percent of the GDP per annum and strongly argues that much of this should come from sources other than the government – household savings and private sector investments. The report offers an eightfold path towards inclusive, sustainable livelihoods and argues for the emergence of a multi-sector collaborative ecosystem approach.

As the English version of the full report is available on sale from Access Development Services, New Delhi, we are carrying just the Cover of the Report and the Overview Chapter and the Table of Contents of the Overview in English in this issue of Policy Watch. However, we are carrying the full Hindi translation of भारत की आजीविका परिस्थिति २०२० एवं परिणति २०३०

We look forward to your feedback.

Vijay Mahajan, Director,

Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies

STATE OF INDIA'S LIVELIHOODS

REPORT 2020



Edited By: Vijay Mahajan

An ACCESS Publication



Sustainable Livelihoods for All

The Challenge of This Decade and a Trajectory for Achieving the Goal

PERSPECTIVES

Vijay Mahajan

CONTENTS

I Overview of India's Livelihood Situation	I
1.1 GDP Growth – From Jobful to Jobless, then Job Losses, then COVID	I
1.2 Employment – Inadequate, Insecure and In-Decent	2
1.3 Agricultural “Employment” – 2/3rd Farmers Earned Less than What They Spent	3
1.4 Landless Agricultural Workers	4
1.5 The Informal Sector – Involuntary Shift from the Farm Sector	5
1.6 The Rural Employment Guarantee Program – Employment of the Last Resort	7
2 What DOGS India's Livelihoods?	9
2.1 Demographic Disappointment – Dividend Declared but Not Received	9
2.2 Occupational Aspirations – Govt Job or Any Job. If not, then Self-Employment	10
2.3 Geographic Mismatch – Workers in Bharat, Jobs in India	11
2.4 Sectoral and Firm Level Perverse Incentives Discourage Employing Labour	12
3 Livelihood Challenges for This Decade	17
3.1 Ensuring Livelihoods for All by 2030	17
3.2 Promoting Growth in Employment for the Neglected Demographic Segments	18
3.3 Enhancing Spatial Spread of Employment Opportunities	21
3.4 Targeting High Growth Sectors for Generating Employment	22
4 Perhaps the GODS Can Help	25
4.1 Greening of India Will Generate Sustainable Livelihoods	25
4.2 Opportunities of New Skilled Jobs in High Growth Sectors	32
4.3 Digital Services Livelihoods for GenNext and Women	36
4.4 Spatial Redistribution of Livelihoods - Districts as Growth Centres	38
5 The Eightfold Path to Sustainable Livelihoods for All by 2030	40
5.1 Transform Agriculture from Subsistence to Sustainability	40
5.2 Practice the Three Rs for the Greening of India	41
5.3 Make School Education, Skill and Entrepreneurship Training More Effective	42
5.4 Finance the Trajectory of Inclusive Livelihoods Using Multiple Sources	43
5.5 Depend on Yourself, Not on the Government: Self-Help is Atma Nirbhar	44
5.6 Organise – Being Atma Nirbhar Does Not Mean Being Alone	45
5.7 Develop Samarth Zillas around Smart Cities	46
5.8 Catalyse a Collaborative Ecosystem for Generating Livelihoods for All	47
6 Last and Final Call to Action	48

भारत की आजीविका परिस्थिति, २०२० एवं परिणति, २०३०

विजय महाजन
राजीव गाँधी इंस्टिट्यूट फॉर कंटेम्पोररी स्टडीज

प्रकाशित : मार्च २०२१, नई दिल्ली

एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज
द्वारा प्रायोजित
लाइवलीहुड्स इंडिया २०२१
के लिये

विषय-सूची

1	भारत की आजीविका परिस्थिति का अवलोकन	1
1.1	बीस साल में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बहुत बढ़ा, रोज़गार बहुत कम	1
1.2	रोज़गार - अपर्याप्त, असुरक्षित और अनुचित	3
1.3	कृषि आजीविका है या मजबूरी? दो तिहाई किसानों ने खर्चे से कम कमाया	5
1.4	भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति	7
1.5	ग्रामीण कृषि से शहरी अनियमित रोज़गार की ओर अनैच्छिक पलायन	9
1.6	ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम - अंतिम आश्रय	12
2	भारत की आजीविका स्थिति क्या है? 15	
2.1	युवा बाहुल्य जनसँख्या - वरदान या निराशाजनक बोझ?	15
2.2	आकांक्षाएँ - सरकारी रोज़गार या कोई भी रोज़गार। और यदि नहीं, तो स्वरोज़गार	17
2.3	भौगोलिक असंतुलन - गांव में श्रमिक और शहर में रोज़गार	18
2.4	विकृत प्रोत्साहन उद्यमियों को श्रमगहन तकनीक उपयोग करने से हतोत्साहित करते हैं	20
3	इस दशक के लिए आजीविका चुनौतियाँ	27
3.1	2030 तक सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करना	27
3.2	उपेक्षित जन खंडों के लिए रोज़गार में वृद्धि को बढ़ावा देना	29
3.3	रोज़गार के अवसरों का ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों में बढ़ाना	33
3.4	रोज़गार बढ़ाने के लिए उच्च वृद्धि उप-क्षेत्रों को लक्षित करना	35

4	सबके लिए सतत रोज़गार - चार प्रमुख रणनीतियां	39
4.1	देश को पुनः हरियाली पूर्वक करने से सतत आजीविका का संवर्धन होगा.....	39
4.2	तीव्र विकास आर्थिक उपक्षेत्रों में नए कौशल वाले रोज़गार अवसर.....	48
4.3	डिजिटल सेवाओं में युवाओं व और महिलाओं के लिए आजीविका.....	54
4.4	आजीविका के स्थानिक पुनर्वितरण - विकास केंद्र के रूप में जिले	56
5	2030 तक सभी के लिए सतत आजीविका के लिए अष्टसूत्रीय मार्ग	59
5.1	कृषि को निर्वाह मात्र से सतत रोज़गार बनाना आवश्यक है	59
5.2	देश को पुनः हरियाली पूर्वक करने के लिए तीन कदम	61
5.3	स्कूल शिक्षा, कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना	62
5.4	समावेशी आजीविका संवर्धन के लिए एकाधिक वित्तीय स्रोतों का उपयोग	63
5.5	अपने आप पर निर्भर, सरकार पर नहीं: स्वयं सहायता ही आत्म निर्भरता है.....	66
5.6	संगठित हों - आत्म निर्भर होने का मतलब अकेले होना नहीं है.....	67
5.7	स्मार्ट सिटी के साथ साथ समर्थ जिलें विकसित करना आवश्यक है	69
5.8	सभी के लिए आजीविका के लिए सहयोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ानी आवश्यक है.....	70
6	आजीविका संवर्धन के लिए अंतिम पुकार	72
7	उद्धरण	73
8	टिप्पणियां	75

आयतों की सूची

आयत 1: अनौपचारिक रोज़गार.....	14
आयत 2: स्वरोज़गार के लिए सामाजिक सुरक्षा और कार्य परिस्थिति का क्या अर्थ है?	12
आयत 3: मनरेगा - दुनिया का सबसे बड़ा रोज़गार गारंटी कार्यक्रम	14
आयत 4: नीमराना, राजस्थान में जापानी विनिर्माण कंपनियों के लिए समूह	25
आयत 5: भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन द्वारा प्राकृतिक संसाधन पुनर्निर्माण	40
आयत 6: अपने गाँव में लौटे प्रवासी मज़दूरों का अपनी ज़मीन और जल संसाधनों को फिर से वापस जुटाना	42
आयत 7: आंध्र और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा	44
आयत 8: लघु उत्पादकों का समर्थन करने के लिए कृषि विविधीकरण में सरकार के प्रयास	44
आयत 9: दुनिया का पहला सहकारी सौर ऊर्जा	46
आयत 10: बायोगैस के उत्पादन के लिए काउडंग (गोबर) बेचकर छोटे किसानों को सक्षम बनाना	46
आयत 11: आयातित प्लास्टिक कचरे के पुनर्प्रसंस्करण में आजीविका	47
आयत 12: बेंगलोर नगर-निगम में बेकार वस्तुओं के पुनर्प्रसंस्करण द्वारा आजीविका निर्माण	47
आयत 13: गुवाहाटी : डिजिटल नॉर्थ ईस्ट 2022 का उभरता टेक्नीकल हब	55
आयत 14: इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन विश्लेषण पटल (ETAAL) पोर्टल	56
आयत 15: नव गुरुकुल - पिरामिड के आधार पर डिजिटल प्रतिभा का पोषण करने का प्रयास	56
आयत 16: बचत, ऋण और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए स्व-सहायता समूह आंदोलन	66
आयत 17: अंगूर बिना डिस्टिल्ड (जूस) के खट्टा हो सकता है, महाग्राप्स बनाम सुला वाइन यार्ड्स	67

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: 2000 से भारत की जीडीपी और रोज़गार वृद्धि दर	2
तालिका 2: 2017-18 इंडस्ट्रीज का वार्षिक सर्वेक्षण	21
तालिका 3: 2021-30 के लिए लिंग द्वारा लक्षित रोज़गार वृद्धि	29
तालिका 4: आयु समूहों द्वारा लक्षित रोज़गार वृद्धि	31
तालिका 5: लक्षित रोज़गार वृद्धि - स्व-नियोजित, नियमित या अनियमित श्रमिक	32
तालिका 6: कौशल स्तर द्वारा लक्षित रोज़गार वृद्धि	33
तालिका 7 : ग्रामीण-शहरी लगातार क्रम में स्थान के आधार पर रोज़गार वृद्धि	34
तालिका 8: सेक्टरों द्वारा लक्षित रोज़गार वृद्धि	36
अनुमानित 11 करोड़ 12 करोड़ नई आजीविका इन 10 उप-क्षेत्रों से आएगी:	38
तालिका 9: भारत में क्लस्टर (समूह)	57
तालिका 10: 2030 तक सभी के लिए आजीविका के लिए निधि की अनुमानित आवश्यकता और संभावित स्रोत	64

1 भारत की आजीविका परिस्थिति का अवलोकन

आजीविका एक व्यक्ति की सामाजिक पहचान होती है, जो उसके या उसकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके रोज़गार और आय का उत्पादन करती है। भारत जैसे देश में, जहाँ बढ़ती आबादी के लिए रोज़गार का स्तर अपर्याप्त है, इस लिये अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की जरूरत है, और इस तरह से बढ़ाने की जरूरत है कि जिससे आजीविका उत्पन्न हो। इस प्रकार, हम इस अवलोकन को पहली बार अर्थव्यवस्था और इसकी विकास दर को यह देखते हुए शुरू करते हैं, कि क्या यह पर्याप्त आजीविका पैदा कर रहा है। हम यह भी जाँचते हैं कि मजदूरी के स्तर, काम करने की स्थिति, और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से ये “आजीविका” कैसे हैं। आगे हम 2030 में श्रम शक्ति में वृद्धि की संभावना रखते हैं और इसलिए आने वाले दशक 2021-2030 में नई आजीविका की आवश्यकता है। इसके लिये उन्हें कार्यान्वित करने के लिए चार अति महत्वपूर्ण रणनीतियों, और अष्टसूत्रीय मार्ग का सुझाव दिया गया है।

1.1 बीस साल में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बहुत बढ़ा, रोज़गार बहुत कम



क्रय शक्ति समानता (PPP) की भारत की सकल घरेलू उत्पाद की समायोजित वार्षिक वृद्धि दर (CGAR) वर्ष 2000 से 2010 के दौरान 9.52 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। हालाँकि, इसके आगे के दशक में, क्रय शक्ति समानता सकल घरेलू उत्पाद का समायोजित वार्षिक वृद्धि दर केवल 5.34 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जोकि 2015 में सालाना 10.26 प्रतिशत से 7.99 प्रतिशत के बीच रही थी, और फिर 2020 में यह -10.28 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी थी। यह COVID महामारी, और अर्थव्यवस्था, पर पडने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम था। क्रय शक्ति समत के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद दो दशक में 7.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष था। इसके विपरीत, रोज़गार का सीएजीआर 2000-10 में 2.84 प्रतिशत था, जोकि 2011-2020 में -0.85 प्रतिशत प्रति वर्ष पर नकारात्मक स्तर के रूप में दर्ज किया गया था। तालिका - 1, नीचे जीडीपी बनाम रोज़गार वृद्धि दर के रुझानों का सारांश प्रस्तुत करती है :

तालिका 1: 2000 से 2020 भारत की जीडीपी और रोज़गार वृद्धि दर

वर्ष :	जीडीपी (बिलियन यूएस \$ PPP में)	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (यूएस \$ PPP में)	विश्व जीडीपी पीपीपी की हिस्सेदारी (% में)	जीडीपी बढ़त (वास्तविक)	रोज़गार (करोड़ में)	रोज़गार वृद्धि दर प्रति वर्ष प्रतिशत में
2000	▲2,077.9	▲2,018	▼4.16%	▲4.0%	35.0 ⁱ	GDP का 20 वर्ष का CAGR 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष जबकि रोज़गार का CAGR केवल 0.98 प्रतिशत प्रति वर्ष था
2005	▲3,238.3	▲2,901	▲4.77%	▲9.3%	▲45.8 ⁱⁱ	
2010	▲5,160.8	▲4,181.2	▲5.76%	▲10.26%	46.3 ⁱⁱⁱ	
2015	▲7,159.7	▲5,464.8	▲6.44%	▲7.99%	44.3 ^{iv}	
2020	▼8,681.3	▼6,283.5	▼6.66%	▼-7.7% (est) ^v	▼42.5	

स्रोत: PLFS आँकड़ों के लिए IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) 2020, MOSPI (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) 2019 और रोज़गार के लिए CMIE (भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र)। CAGRs (सालाना चक्रवृद्धि बढ़ोतरी दर) की गणना लेखक द्वारा की जाती है।

2012 में, योजना आयोग ने स्वीकार किया, कि "रोज़गार लचीलापन में दशक की पहले छमाही वर्ष 1999–2000 से 2004–05 में 0.44 प्रतिशत की कमी आई है, दूसरी छमाही 2004–05 से 2009-10 के दौरान 0.01 प्रतिशत कम होकर, "वित्त वर्ष 2015-16 में रोज़गार में 0.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2014-15 में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आँकड़े भारत में RBI के (KLEMS) डेटाबेस के अनुसार हैं। कोविड महामारी ने 2020 में इस प्रवृत्ति को गंभीर रूप से और बढ़ा दिया है।

हमारा अनुमान है कि 2000-2020 की अवधि में रोज़गार का सीएजीआर प्रति वर्ष 0.98 प्रतिशत था, जबकि जीडीपी का सीएजीआर उसी अवधि में 7.5 प्रतिशत था। इस प्रकार इस दशक में, 2021-30, हमें केवल जीडीपी के लिये ही नहीं, बल्कि आजीविका के विकास के लिए भी काम करना होगा।

1.2 रोज़गार - अपर्याप्त, असुरक्षित और अनुचित



1.2.1 कुल मिलाकर रोज़गार का अनुमान

श्रम शक्ति बल में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो काम करने वाले और (कार्यबल कहलाते हैं) काम करने के लिये हमेशा सक्षम और तैयार रहते हैं, लेकिन वो ही बेरोज़गार हैं। भारत में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (NSSO) ने 2011-12 में पाँच वर्षीय-रोज़गार और बेरोज़गारी सर्वेक्षण (EUS) का आयोजन किया था। भारत सरकार ने 2015 से EUS को बंद कर दिया और 2017 से **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** का शुभारंभ किया। जून 2017- जून 2018 की अवधि के लिए PLFS की पहली वार्षिक रिपोर्ट जून 2019 में जारी की गई थी। जुलाई 2018 से जून 2019 तक के सर्वेक्षण के आधार पर दूसरी रिपोर्ट जून 2020 में जारी की गई थी। हालाँकि PLFS की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के बीच में आई थी, क्योंकि यह एक साल पहले की अवधि को कवर करती थी, इसमें लॉकडाउन के बीच की स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

अन्य स्रोतों से, विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र से बेरोज़गारी की रिपोर्ट *सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE)* का उपयोग करते हुए, हम 31 दिसंबर 2020 को एक तस्वीर बनाने में सक्षम हुए थे। PLFS 2018-19 से, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए 37.5 प्रतिशत LFPR को लागू करना, 2020 की समाप्ति पर 15 वर्ष की आयु और 109.5 करोड़ से अधिक की अनुमानित भारतीय आबादी के लिए, हमने गणना की कि श्रम शक्ति 2021 की शुरुआत में 52 करोड़ थी। इनमें से, CMIE की रिपोर्ट के औसत के अनुसार, 2020 के अंत में

यह 9.15 प्रतिशत थी यानि 4.76 करोड़ व्यक्ति बेरोज़गार थे। 2021 की शुरुआत में, भारत में 52 करोड़ लोग रोज़गार से जुड़े हुए थे, जिसमें से 47.2 करोड़ लोगों के पास ही रोज़गार उपलब्ध था, और लिंग और आयु के आधार पर 4.76 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए थे।

श्रमिक शक्ति में कार्यरत ग्रामीण / शहरी, और पुरुष / महिलाओं के शेयरों के संदर्भ में, PLFS 2018-19 के अनुसार, लगभग 55.1 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष, और 19.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ थीं, और 56.7 प्रतिशत शहरी पुरुष, एवं 16.1 प्रतिशत शहरी महिलाएँ रोज़गार करते थे। जैसा कि उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर देखा जा सकता है, कि महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) पुरुष LFPR की तुलना में बहुत कम थी। महिला श्रम भागीदारी दर LFPR निम्न-आय वाले देशों के साथ-साथ अति मध्यम और अधिक आमदनी वाली अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादा है, जोकि निम्न-मध्यम-आय वाले देशों में अपेक्षाकृत कम है, जो राष्ट्रीय आय और महिला LFPR के बीच यू-आकार का संबंध बनाती है। यह निष्कर्ष (गोल्डिन 1995 मैममेन और पैक्ससन 2000) की रिपोर्ट पर आधारित है। 2005 के बाद से भारत में महिला LFPR में गिरावट इस यू-आकार के घुमाव (मेहरोत्रा और सिन्हा, 2017 और रेगी 2019) के अनुरूप है।

श्रम भागीदारी दर (LFPR) के लिए आयु का विवरण PLFS आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 से उपलब्ध है। उस वर्ष, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में, LFPR श्रम भागीदारी दर 49.8 प्रतिशत था। काम करने की उम्र (15-59 वर्ष) जनसंख्या श्रम भागीदारी दर (LFPR) 49.8 प्रतिशत थी। हालाँकि, 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में, LFPR केवल 38.2 प्रतिशत था, जो काम करने वाली आबादी की तुलना में बहुत कम था, जिसका संकेत यह था, कि अधिकांश कामकाजी उम्र के युवा "शिक्षा, रोज़गार या प्रशिक्षण में (एनईईटी), प्राप्त नहीं थे फिर भी वे अभी तक काम की तलाश में नहीं थे।

क्षेत्रवार रोज़गार का विवरण (PLFS) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 से भी है। और उस डेटा से यह देखा जा सकता है, कि खेतों में फसलों की खेती करने में 37.14 प्रतिशत और पशुपालन में (6.55) श्रम बल का योगदान था, जिससे खेती का 43.69 प्रतिशत श्रम बल के साथ सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में (12.13) प्रतिशत, निर्माण के क्षेत्र में (11.68) प्रतिशत, थोक और खुदरा व्यापार के क्षेत्र में (10.09) प्रतिशत, परिवहन और भंडारण क्षेत्र में (4.93) प्रतिशत, और शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में केवल (3.78) प्रतिशत लोग कार्यरत थे इससे यह ज्ञात होता है, कि खेती और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े लोगों से अधिक, अगले पाँच सबसे बड़े रोज़गार क्षेत्र थे।

1.3 कृषि आजीविका है या मजबूरी? दो तिहाई किसानों ने खर्च से कम कमाया



इस अध्याय को लिखते समय किसानों का विरोध काफ़ी जोरों पर है। विडंबना यह है कि मीडिया में, भारत के कृषि परिवारों का राज्यों में समग्र विरोध बहुत कम दिखाई दिया है। यहाँ हम उस अंतर को भरने का प्रयास करते हैं, जिसमें से इस तरह के डेटा का उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण का 70 वां दौर, जो 2013 में, भारत में कृषि परिवारों के प्रमुख संकेतक (एनएसएसओ, 2015) के रूप में था। हालाँकि यह सात साल पुराना है, हालाँकि यह भारत के फार्म हाउसों पर सबसे आधिकारिक डेटा स्रोत है।

भारत में 2013 में 9 करोड़ से अधिक किसान परिवार थे। लगभग दो-तिहाई किसान परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम यानि (2.5 एकड़) भूमि थी, और केवल 10 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) से अधिक भूमि का मालिकाना हक था। और उच्च जातियों के किसानों के पास बड़ी भूमि जोतों का आनुपातिक हिस्सा था।

जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, जिनकी आबादी लगभग 45 प्रतिशत थी, उनकी भी लगभग सभी आकारों में भूमि के अनुपात में हिस्सेदारी कायम रही। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, आड़ी-तिरछी एवं ढलान वाली कम भूमि का स्वामित्व था। इस प्रकार, निचली जाति और निचली भूमि के स्वामित्व ने आबादी के कुछ क्षेत्रों को निचले पायदान पर रखने के लिए उन्होंने एक-दूसरे को मजबूत बनाया।

औसतन भारतीय किसान परिवारों ने जुलाई से दिसंबर की अवधि में लगभग 50 प्रतिशत सिंचाई के साथ केवल 0.94 हेक्टेयर खेती की, और जनवरी से जून की अवधि में, यह 0.78 हेक्टेयर खेती की थी, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत सिंचाई के साथ की थी। 9 करोड़ किसान परिवारों में से, लगभग 7.8 करोड़ किसानों ने जुलाई से दिसंबर की अवधि

में केवल एक ही फसल उगाई थी। इनमें से 4.5 करोड़ ने केवल धान उगाया था। और धान उगाने किसानों में से केवल 41 प्रतिशत ने अपने धान को बेच दिया, और इनमें से भी लगभग 60 प्रतिशत किसान परिवारों ने इसे वहाँ के स्थानीय निजी व्यापारियों को बेचा था।

स्थानीय निजी व्यापारियों को अपनी बिक्री का उच्च हिस्सा जैसे - गेहूँ, सोयाबीन, अरहर और कपास आदि को छोड़कर अन्य सभी फसलों के लिए सही निर्णय था, जिसकी मंडियों (कृषि उपज बाजार यार्ड) में यथोचित उच्च बिक्री थी। और गन्ना किसानों ने अपने गन्ने को बड़े पैमाने पर चीनी मिलों को बेच दिया। एमएसपी पर बिक्री मुख्य रूप से धान और गेहूँ की फसलों के लिए होती थी, और अन्य एमएसपी अधिसूचित फसलों के लिए, कुल बिक्री का 2 प्रतिशत से कम एमएसपी पर होता था। बहुत कम किसान इन फसलों के अलावा अन्य फसलों को उगाते हैं।

एक किसान परिवार की खेती लागत संरचना से पता चला, कि खरीदी गयी निवेश वस्तुओं का मूल्य लगभग 50 प्रतिशत था, जबकि पशु श्रम कुल लागत का 1.5 प्रतिशत था। और केवल 7 प्रतिशत किसानों को आधिकारिक स्रोतों (जैसे - कर्मचारी, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों) आदि से कृषि विस्तार का ज्ञान मिला।

1.3.1 आय, व्यय, ऋणग्रस्तता और सहायक सब्सिडी

सबसे महत्वपूर्ण खोज यह थी कि औसत मासिक घरेलू आय 6426 रुपये थी, जबकि 2013 में मासिक खर्च 6223 रुपये था। हालाँकि, 6.2 करोड़ किसान परिवारों के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि थी और लगभग दो तिहाई किसान परिवारों का मासिक व्यय, उनकी मासिक आय से अधिक था। 52 प्रतिशत किसान परिवारों ने कहा कि उन पर कोई ना कोई ऋण बकाया है। इनमें से 60 फीसदी किसानों ने बैंकों, और सहकारी समितियों, से कर्ज लिया हुआ है, और 25 फीसदी ने स्थानीय साहूकारों से कर्ज लिया है।

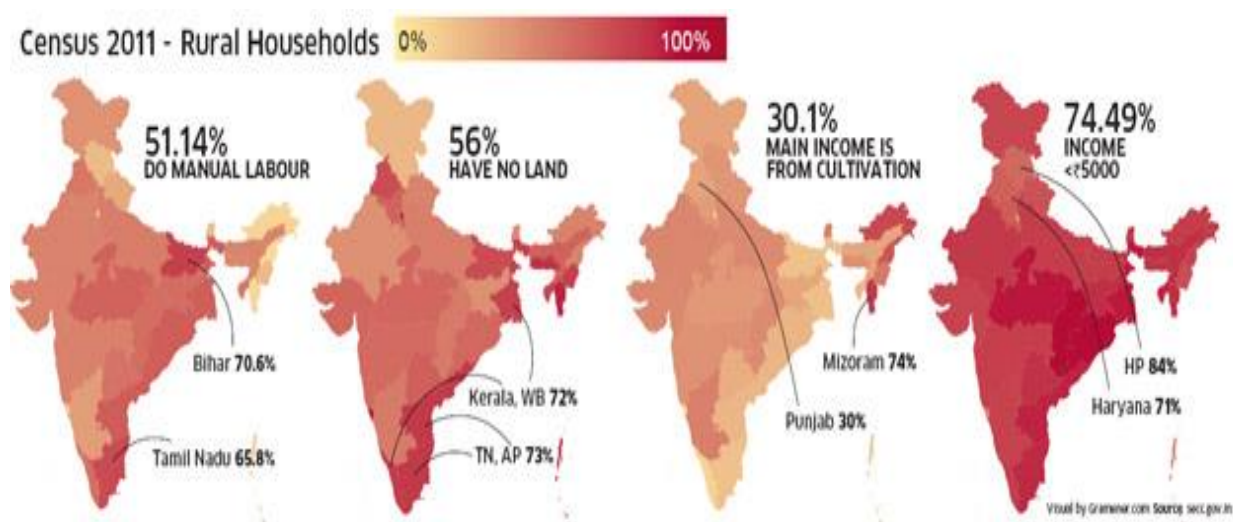
2013 में एक अखिल भारतीय स्तर पर औसतन, 47,000 रुपये की बकाया राशि 74,676 रुपये की औसत वार्षिक आय का लगभग 2 / 3rd थी। हालाँकि, केरल की आय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आय के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता का स्तर बहुत अधिक था। तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, व्यापक रूप से कृषि में रासायनिक खाददानों के उपयोग की तीव्रता को दर्शाते हैं।

लगभग 57 प्रतिशत किसान परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न देने में सक्षम थे। 2013 में केवल 44 प्रतिशत लोगों के पास ही मनरेगा जॉब कार्ड थे, जिससे वे कमजोर लोग मजदूरी करने में सक्षम बन सके।

1.4 भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति

सामाजिक-आर्थिक और जाति की जनगणना 2011 ने हमें यह बताया है, कि भारत में 56 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कोई कृषि भूमि नहीं है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में 72 प्रतिशत से भी अधिक परिवार भूमिहीन हैं। जिसे नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है।

जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण किसान परिवार :



स्रोत : <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/half-of-rural-india-still-doesnt-own-agricultural-land-secc-2011/articleshow/48062767.cms>

चित्र में दर्शाये गये आँकड़ों के परिणामस्वरूप, लगभग 51 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण आय के लिए ज्यादातर खेतों पर मैन्युअल श्रम पर निर्भर करते हैं।

इनमें भी बिहार में 71 प्रतिशत और तमिलनाडु में 66 प्रतिशत भूमिहीन श्रमिकों का अनुपात सबसे अधिक था। हालाँकि, दोनों राज्यों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है।

बिहार में ज्यादातर श्रमिक कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के रूप में लगे हुए थे, जबकि तमिलनाडु में वे मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे, जो कि अधिक विविध अर्थव्यवस्था के कारण था। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2018-19 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 44,652 रुपये प्रति वर्ष थी, वहीं इसी अवधि में तमिलनाडु में यह आय प्रति व्यक्ति 215,784 रुपये प्रतिवर्ष थी, यानि लगभग पाँच गुना अधिक थी। इसका अर्थ है कि भूमिहीनता अपने आप में गरीबी का मुख्य कारण नहीं है, यह भूमिहीनता है जो कृषि से अलग भी आजीविका के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती है।

बिहार और पूर्वी उत्तर-प्रदेश के श्रमिक, दक्षिणी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ-साथ मप्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र से अपने घर के गाँवों में कम से कम रोज़गार प्राप्त कर पाए। इस प्रकार वे तेजी से काम की तलाश में

शहरों की ओर पलायन करने लगे, और यही वह है, जो अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि को पूरा करता है, जिसके लिये हम दूसरी ओर आगे बढ़ते हैं।



1.5 ग्रामीण कृषि से शहरी अनियमित रोज़गार की ओर अनैच्छिक पलायन



हम वर्तमान में अनौपचारिक रूप से रोज़गार पर एक वैचारिक ढाँचे के नीचे मौजूद हैं, जैसा कि श्रम सांख्यिकी विदों के पंद्रहवें अंतराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है

आयत 2. अनौपचारिक रोज़गार

उत्पादन इकाईयों के प्रकार	रोज़गार स्थिति :								
	स्वयं खाता कर्मी		नियोक्ता		पारिवारिक श्रमिकों का योगदान	कर्मचारी		उत्पादकों की सहकारी समितियों के सदस्य	
	अनौपचारिक	औपचारिक	अनौपचारिक	औपचारिक	अनौपचारिक	अनौपचारिक	औपचारिक	अनौपचारिक	औपचारिक
औपचारिक क्षेत्र के उद्यम	NA	FJ	NA	FJ	1	2	FJ	NA	FJ
अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम	3	NA	4	NA	5	6	7	8	NA
परिवार	9	NA	NA	NA	NA	10	FJ	NA	NA
NA - का मतलब परिभाषा के कारण संभव श्रेणी नहीं है।									

FJ का अर्थ है औपचारिक रोज़गार - चाहे औपचारिक उद्यम में, या अनौपचारिक उद्यम में, घरेलू उद्यम में, औपचारिक उद्यम के साथ संबंध के कारण, जैसे कि आउटसोर्सिंग।
अनौपचारिक रोज़गार सेल 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 हैं।
अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार सेल 3 से 8 हैं।
अनौपचारिक क्षेत्र के बाहर अनौपचारिक रोज़गार सेल 1, 2, 9 और 10 हैं, 2 का एक उदाहरण कार्यालयों में हाउसकीपिंग वर्कर हैं जबकि 9 पीस-रेट होम बेस्ड वर्कर्स (घर आधारित श्रमिक) हैं।
भुगतान किए गए घरेलू श्रमिकों को नियोजित करने वाले परिवारों को बाहर करता है।
स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI)-2019 की वार्षिक रिपोर्ट, और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के 2017-18, के सर्वे पर आधारित

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, (PLFS) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18, भारत में, गैर-कृषि क्षेत्रों में 68.4 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए थे।

1.5.1 महिला पुरुष अनुपात

गैर-कृषि क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों की अनौपचारिक क्षेत्र में 71.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, और गैर-कृषि क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 54.8 प्रतिशत थी। यह तथ्य महिलाओं के कारण था, कि जब महिला काम करती थीं, तब महिलाओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल होना पड़ता था, जहाँ उनके कार्यवाहक होने की संभावना अधिक होती थी।

1.5.2 नियमित, अनियमित, स्व-रोज़गार

ग्रामीण परिवारों, जिनके पास स्वरोज़गार से आमदनी का 52.2 प्रतिशत हिस्से के रूप में एक बड़ा स्रोत था। नियमित वेतन आय से आय के प्रमुख स्रोत वाले घर 12.7 प्रतिशत थे, और 2017-18 के दौरान अनियमित श्रम में परिवारों का कुल प्रतिशत 25 प्रतिशत था। शहरी क्षेत्रों में, स्व-रोज़गार में परिवारों का हिस्सा 32.4 प्रतिशत था, नियमित वेतन / वेतन आय वाले परिवारों की हिस्सेदारी 41.4 प्रतिशत थी जबकि अनियमित श्रम में 11.8 प्रतिशत थे। जैसा कि देखा जा सकता है, कि शहरी क्षेत्र में लोगों को नियमित वेतन अर्जित करने के लिए बहुत अधिक अवसर प्रदान किये गये थे।

1.5.3 स्व-नियोजित श्रमिक

अनौपचारिक श्रमिकों का अधिकांश हिस्सा स्व-नियोजित था। 2017-18 के दौरान, लगभग 52.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में स्वरोज़गार आय का बड़ा स्रोत था। आमदनी के लिहाज से, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कामगारों में से 57 प्रतिशत कर्मचारी स्व-नियोजित थे, जिनमें पुरुषों की औसत आय लगभग 8500 रुपये से 9700 रुपये प्रति माह के बीच थी, और महिलाओं की औसत आय लगभग 3900 रुपये से 4300 रुपये के बीच थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में, जहाँ सभी श्रमिकों का कुल 38 प्रतिशत स्वयं-नियोजित था, और उसमें पुरुषों की औसत सकल कमाई लगभग 16,000 रुपये प्रति माह थी। और महिलाओं की मासिक आय लगभग 6500 रुपये से 7500 रुपये के बीच थी। यह आय 2017- 18 के आँकड़ों पर आधारित है। स्वरोज़गार के माध्यम से ग्रामीण और शहरी पुरुषों की कमाई के बीच लगभग 76 प्रतिशत का एक बड़ा अंतर है, जो ग्रामीण प्रवासियों को शहरी क्षेत्र में आने के लिये आकर्षित करता है।

1.5.4 नियमित कामगार

नियमित वेतन / वेतन अर्जन से आय के प्रमुख स्रोत वाले ग्रामीण परिवारों का हिस्सा 12.7 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के बीच प्रति माह 13,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये प्रति माह और महिलाओं के बीच 8,500 से 10,000 रुपये प्रति माह तक की कमाई होती है। शहरी क्षेत्रों में, नियमित वेतन / वेतन आय वाले परिवारों का हिस्सा 41.4 प्रतिशत था। नियमित वेतन / वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच की कमाई पुरुषों के बीच 17,000 रुपये से 18,000 रुपये और 2017-18 में महिलाओं के बीच 14,000 रुपये से 15,000 रुपये तक थी। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों के अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मासिक मजदूरी के बीच लगभग 30 प्रतिशत का एक बड़ा अंतर होने के कारण भी ग्रामीण श्रमिकों के शहरी क्षेत्र में खींचतान का एक प्रमुख कारण है।

1.5.5 अनियमित कामगार

2017-18 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से 11.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों से 25 प्रतिशत परिवार अनियमित श्रम में थे। प्रति दिन कमाई के संदर्भ में, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा जैसे सार्वजनिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगे अनियमित श्रम में पुरुषों के लिये 253 रुपये से 282 रुपये प्रति दिन (6955 रुपये प्रति माह तक) और महिलाओं के लिये 166 रुपये से 179 रुपये प्रति दिन (4511 रुपये प्रति माह) तक है। अनियमित श्रम द्वारा प्रति दिन शहरी औसत कमाई 314 रुपये से लेकर 335 रुपये तक पुरुषों के लिये (8435 रुपये) प्रति माह और 186 से 201 रुपये तक महिलाओं के लिये लगभग (5030 रुपये) प्रति माह के बीच है। ग्रामीण क्षेत्रों में 94 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 104 प्रतिशत का अंतर, नियमित कर्मचारियों और अनियमित श्रमिकों के वेतन के बीच में है, एवं कार्यकाल की अधिक असुरक्षा और अनुलाभों की कमी के अलावा, अनियमित कार्य की तुलना में नियमित रोजगार के लिए खोज करने के लिए आग्रह करता है। रोजगार तलाशने वाले श्रमिक अक्सर स्वरोजगार को एक अस्थायी विकल्प के रूप में चुनते हैं, लेकिन यह उनमें से अधिकांश के लिए आजीवन का विकल्प बन जाता है।

1.5.6 अनुलाभ और कार्य परिस्थिति में कमियां

आइए हम अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक लाभों और कामकाजी स्थितियों को संक्षेप में देखते हैं। 49.6 प्रतिशत, नियमित वेतन / वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये भी, को कोई सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिला है। इस प्रकार पूरे वर्ष के अंतर्गत एक बार भी कोई छुट्टी नहीं मिली, मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं, कोई (क्रेच) शिशु देखभाल के लिये अवकाश नहीं, कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य और जीवन के लिए कोई जोखिम कवर नहीं, न ही कोई भविष्य निधि / पेंशन आदि। काम की परिस्थितियों के कारण व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए थोड़ी चिंता दिखाई, परन्तु प्राथमिक चिकित्सा जैसी सभी सुविधाएँ गायब थीं। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र की लगभग 95 प्रतिशत महिला श्रमिकों को काम के स्थान पर दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों का सामना करना पड़ता है। यह आधार ह्यूमन राइट्स (मानव अधिकार आयोग) के एक अध्ययन पर आधारित है।

भारत सरकार ने 2020 में कई श्रम कानूनों में संशोधन किया है, और इनको श्रम कानूनों का नाम दिया है, यह चार प्रकार के श्रम कानूनों हैं : (1) मजदूरी कानूनों , (2) औद्योगिक संबंधों पर कानूनों , (3) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर कानूनों , और (4) कामकाजी परिस्थितियों और श्रम की सुरक्षा पर कानूनों । परन्तु इनसे यह संभावना नहीं है, कि ये किसी भी तरह से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे (आयत 2 देखें)।

आयत 2: स्वरोज़गार के लिए सामाजिक सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों का क्या मतलब है?

“.. भारत के सभी उद्यमों में 97 प्रतिशत से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं... और अधिकांश पारिवारिक उद्यमों में पाँच से कम मजदूर काम करते हैं... यहाँ श्रम वचनबद्धता, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध, सुरक्षा, काम करने की स्थिति आदि का निर्माण किया जाता है। सामाजिक, पारिवारिक, जातीय, पारस्परिक संबंध, जातिवाद और विश्वास के संबंधों की रूपरेखा का अपनापन देखने को मिलता है। राज्य का अधिकार इस संदर्भ में पहले से ही न्यूनतम है और आगे भी ऐसा ही रहेगा... ..इस संदर्भ में सुरक्षा के श्रम कानूनों की कल्पना कैसे करें? देश को सभी प्रकार के अनौपचारिक श्रमिकों का पता लगाने उन्हें पहचानने और सामाजिक सुरक्षा उपायों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य और स्थानीय स्तर पर एक मजबूत संस्थागत बुनियादी ढाँचा बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में, यह आधारभूत संरचना मौजूद नहीं है.....इस खंड में नीति और कार्यक्रमों के अध्याय” में प्रो अशोक सरकार ।

औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार की अपर्याप्तता के कारण भारत में न केवल अनौपचारिक क्षेत्र में अपने श्रमिकों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत हिस्सा था, लेकिन 2011-12 में बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत थी। और उसी वर्ष, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का हिस्सा भी लगभग 22 प्रतिशत था। इस प्रकार बहुत से कामकाजी व्यक्ति गरीबी रेखा को पार करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए कुछ गारंटीशुदा रोज़गार की आवश्यकता थी, भले ही वह उनके लिये सिर्फ जीवित रहने के लिये ही मजदूरी प्रदान करता हो

1.6 ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम - अंतिम आश्रय



ग्रामीण भारत में रोज़गार की सख्त आवश्यकता को देखते हुए, सार्वजनिक कार्यों में मजदूरी रोज़गार उत्पन्न करने के लिए राज्य की प्रतिक्रियाओं का एक लंबा इतिहास रह है। ऐतिहासिक समय में राजा अन्न का भंडार रखते थे, और लोगों को काम के बदले भोजन देते थे। ब्रिटिश शासन काल में भारत में, "अकाल कार्य" शुरू करना जिला प्रशासकों के काम का एक सामान्य हिस्सा था। आजादी के बाद के भोजन का विचार काम में आता रहा। 1973 की गर्मियों में प्रमुख सूखे के दौरान रोज़गार गारंटी योजना (ईजीएस) शुरू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था। इसके बाद जनता सरकार ने 1977 में अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम के लिए एक (भोजन) आहार योजना की स्थापना की।

इस योजना को 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (NREP) के रूप में फिर से शुरू किया गया था। उसके पश्चात ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था, ताकि प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक साल के अन्दर 100 दिनों तक के रोज़गार की गारंटी प्रदान की जा सके। और वर्ष और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए एक मजबूत आधार बनाया जा सके। 15 अगस्त 2001 को, एक नया वेतन रोज़गार कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (SGRY) को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पेश किया गया था। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि सत्ता में पार्टी की परवाह किए बिना विभिन्न सरकारों द्वारा श्रमिक उत्थान के कार्यक्रम जारी रहे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा, राष्ट्रीय सलाहकार समिति में कई सामाजिक श्रमिकों की सलाह पर बनाया गया था। पहले के रोज़गार कार्यक्रमों के विपरीत, MGNREGA ने कानूनी तौर पर एक वर्ष में 100 दिनों के कार्य भुगतान के लिए ग्रामीण आबादी के अधिकार को सुनिश्चित किया था। योजना में भागीदारी माँग के आधार पर होती थी। आवेदन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर और उनके गाँव के 5 किमी के दायरे में काम उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया था। और यदि कोई काम नहीं दिया जा सकता है, तो एक निर्दिष्ट बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

मनरेगा ने अकुशल कार्यों को प्राथमिकता दी और श्रम बचत मशीनरी के उपयोग को प्रोत्साहित किया। यह भी निर्दिष्ट किया गया, कि कार्यक्रम की सामग्री ग्राम पंचायत स्तर पर औसत कुल लागत का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए उदाहरण के लिये (आयत 3 में देखें)। इस अधिनियम ने ठेकेदारों के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया था, और पंचायती राज संस्थाओं को इसे लागू करने के लिए पूर्ण रूप सशक्त किया था। इसके अलावा, अधिनियम ने महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई भागीदारी दर निर्धारित की, और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी की भागीदारी भी निर्धारित करने पर जोर दिया था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया, कि किए जाने वाले कार्यों का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय रूप से तय किया जाना है।

आयत 3: मनरेगा - दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम

मनरेगा के तहत सार्वजनिक कार्यों की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGS) 2006 में शुरू की गई थी। संचयी रूप से, 2006 के बाद से, MGNREGS के तहत कार्यक्रम ने 3130.25 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस सृजित किए हैं, जिसमें कुल व्यय 627,153 करोड़ है, जो कि दुनिया में नंबर एक सार्वजनिक कार्य रोजगार कार्यक्रम की रैंक अर्जित करता है। संचयी रूप से, 2006 से, MGNREGS के तहत कार्यक्रम ने 3130.25 करोड़ लोगों के काम का सृजन किया है, जिसमें कुल व्यय 627,153 करोड़ है, जो कि दुनिया में नंबर एक सार्वजनिक कार्य रोजगार कार्यक्रम की रैंक अर्जित करता है।

MNREGS पोर्टल के अनुसार, कि 2019-20 में पूरे वर्ष के लिए 68,278 करोड़ रुपये, जबकि 31 दिसंबर 2020 तक, MGNREGS के तहत 2020-21 में 82,678 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसमें से 59,670 करोड़ रुपये वेतन के रूप में, और सामग्री पर लगभग 25.4 प्रतिशत और प्रशासन पर 3.1 प्रतिशत खर्च किया गया था।

31 दिसंबर 2020 तक, MNREGS के तहत 14.21 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड जारी किए गए थे और इन जॉब कार्डों में 18.98 करोड़ सक्रिय श्रमिक कार्य कर रहे थे। MNREGS के 1,202,827 काम चल रहे थे, यानि 31 दिसंबर 2020 को एक करोड़ से अधिक कार्य स्थलों पर काम चल रहा था

इस प्रकार हम देखते हैं कि MNREGS ने COVID मंदी के दौरान भी बड़े पैमाने पर ग्रामीण लोगों की पीड़ा को काफी हद तक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालाँकि फिर भी कई ऐसे जरूरतमंद क्षेत्र थे, जहाँ 2020 में भी MNREGS कवरेज कम था, खासकर यूपी और बिहार में।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2017-18 के अनुसार, मनरेगा सार्वजनिक कार्यों में लगे अनियमित श्रमिकों द्वारा प्रति दिन की औसत मजदूरी 2017-18 के दौरान पुरुषों में 141 से 171 रुपये और महिलाओं में 131 से 165 रुपये के बीच थी। हालाँकि महामारी के बीच में, सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी दर को बढ़ाकर 200 रुपये प्रति दिन कर दिया। भारत सरकार ने बजट में मूल आवंटन में 61,000 करोड़ रुपये का इजाफा किया और बजट में 40,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी भी की है। इसी दौरान मनरेगा के तहत लगभग 50 लाख से अधिक नए जॉब कार्ड भी जारी किए गए, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी श्रमिक अपने घर गाँवों में लौट आए थे, और नौ करोड़ से अधिक व्यक्तियों को MNREGS के तहत अक्टूबर 2020 तक काम मिला, जो कि MGNREG अधिनियम को बनने के बाद से अब तक का सबसे अधिक था।

2 भारत की आजीविका स्थिति क्या है?

हमने भारत में आजीविका की समस्या के पीछे चार प्रमुख कारणों की पहचान की है। जिनमें जनसांख्यिकी, व्यावसायिक स्थिति, भूगोल और क्षेत्रीय नीतियाँ हैं, जो आजीविका के खिलाफ हैं। हम इनमें से प्रत्येक को नीचे एक-एक करके निपटाते हैं।

2.1 युवा बाहुल्य जनसँख्या - वरदान या निराशाजनक बोझ?



Image Courtesy: <https://www.washingtonpost.com/world/2019/02/01/indias-job-crisis-is-worse-than-people-thought-its-government-tried-squelch-data/>

एक राष्ट्र अपने इतिहास में जनसांख्यिकीय लाभांश - युवा बाहुल्य जनसँख्या - वाली अवस्था में केवल एक बार आता है जब युवा जनसँख्या उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम करने की उम्र तक पहुँच जाता है। और यदि वे सभी काम करते हैं, तो श्रमिकों के लिए आश्रितों का अनुपात कम हो जाता है, और यह समग्र विकास की समृद्धि को बढ़ाता है। इसके बजाय, भारत में, हमारे पास पिछले दो दशकों में कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं की एक बड़ी आबादी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश रोज़गार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। जनगणना के अनुसार 2001 में 15 साल से कम उम्र की आबादी लगभग 36.4 करोड़ थी। वे सभी 2020 तक कामकाजी उम्र में प्रवेश कर चुके थे, और अगर हम 38.2 प्रतिशत के श्रम शक्ति की भागीदारी दर (LFPR) को लागू करते हैं, तो एक बड़ा 13.9 करोड़ व्यक्ति श्रम बल में शामिल हो जायेंगे।

जैसा कि हमने पहले खंड में रोज़गार डेटा से देखा है, 2001-2020 की अवधि में, रोज़गार 35 करोड़ से 37.66 करोड़ हो गया, 2.66 करोड़ की वृद्धि हुई, जो युवा श्रम शक्ति की आबादी में केवल 19 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसलिए, जब तक युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, वे अपने घर के सदस्यों की कमाई पर निर्भर रहे। और इस तरह इसने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को कम किया है और लाखों लोगों को गरीबी में रखा है। जैसा कि लेखक ने हाल ही में एक वेबिनार में कहा है।

“अब अगर आप 21 साल के हो गये हैं, तो परिवार कहता है, कोई समस्या नहीं है, पुरुष / महिला अभी भी अध्ययन कर रहा है। और अगर 26 साल की उम्र में भी आप बेरोज़गार हैं, तो यह पारिवारिक के लिये समस्या बन जाती है। और यदि 31 साल की उम्र में भी प अभी भी कार्यरत नहीं हैं, तो यह एक सामाजिक समस्या बन जाती है। इस तरह के निराश युवा कम आत्मसम्मान, अवसाद, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग, और हिंसा आदि के शिकार हो सकते हैं।

उन्हें असामाजिक ताकतों द्वारा आसानी से बहकाया जा सकता है और अपराध, दंगों और आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2000 के बाद से युवाओं के लिए आजीविका की अपर्याप्तता के कारण भारतीय स्थिति में इन सामाजिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।

2030 तक, भारत का निर्भरता अनुपात केवल 0.4 से अधिक होने का अनुमान है। सीधे शब्दों में कहें, तो पाँच सदस्यों के औसत घर में, दो सदस्य काम कर रहे होंगे, और अन्य तीन सदस्य उनकी कमाई पर निर्भर होंगे। लेकिन यह इस धारणा पर आधारित है कि उन दो घरों में स्थिर आधार पर पारिश्रमिक आजीविका होगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश पर एक अध्ययन में दो दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं: "एक," भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश - युवा बाहुल्य जनसंख्या - की खिड़की 2005-06 से 2055-56 तक पाँच दशकों के लिए उपलब्ध है, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक लंबी है। दूसरा, और अधिक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह जनसांख्यिकीय लाभांश विंडो अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या मापदंडों के अंतर व्यवहार के कारण अलग-अलग समय पर उपलब्ध है।"

उपरोक्त पहला तथ्य हमें याद दिलाना चाहिए। कि बड़ी संख्या में पारिश्रमिक, सम्मानजनक और स्थिर आजीविका उत्पन्न करने के लिए हमें जल्दी करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा बाहुल्य जनसंख्या अवसर की खिड़की का एक तिहाई भाग हम पहले ही खो चुके हैं।

दूसरा तथ्य इसके लिए एक शक्तिशाली तर्क है। प्रवासियों को सकारात्मक तरीके से देखना और प्रवासी कामगारों के लिए एक गरिमापूर्ण कार्य और जीवन का अनुभव सुनिश्चित करना।

2.2 आकांक्षाएँ - सरकारी रोज़गार या कोई भी रोज़गार। और यदि नहीं, तो स्वरोज़गार



आजीविका की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक है, नियमित, वेतन वाली रोज़गार पाने के लिए भारतीय श्रमिकों की आकांक्षा, मुख्यतः एक सरकारी रोज़गार। यह चलन उस काल (औपनिवेशिक काल) में शुरू हुआ, जब अंग्रेजों को राज चलाने के लिए क्लर्कों और अन्य पदाधिकारियों की एक सेना की आवश्यकता होती थी। प्रचलित मजदूरी दर की तुलना में, सरकारी नौकरों का वेतन कहीं अधिक था। यहाँ तक कि अवकाश, भविष्य निधि और पेंशन जैसे शब्द भी इन नौकरियों की बदौलत ही भारतीय शब्दावली में आए। और आजादी के बाद यह चलन बेरोकटोक जारी रहा, क्योंकि भारत ने एक राष्ट्र का निर्माण किया था और इसके साथ ही नौकरशाही का बोझ बढ़ा। पिछले दो दशकों में सरकारी रोज़गार में मंदी के बावजूद, भारतीय समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया उन कहानियों से भरे हुए हैं, जहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोग कुछ नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। एक उच्च मामले का वर्णन नीचे किया गया है जहाँ आवेदक को रोज़गार का अनुपात 6250 पर 1 था।

[2015 में] पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी सहित 23 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में 368 चपरासी के पदों के लिए आवेदन किया था। तो इसके बाद अफरातफरी मच गई। कि उच्च शिक्षित लोगों को इस रोज़गार के लिए आवेदन करने की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि यह पद केवल प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्राप्त और साइकिल चलाना जानने वालों के लिये ही थी? एक और मामले ने 24 लाख आवेदकों को आवेदन करने के लिये आकर्षित किया, जिसमें आवेदक और को नौकरियों का अनुपात 171 पर 1 था।

22 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय एक बयान जारी कर कहा, कि "रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 1.4 लाख रिक्तियों के लिए तीन केंद्रीय रोज़गार अधिसूचनाएँ जारी की

हैं जिसके आधार पर इन रोज़गार रिक्तियों के लिये, 2 करोड़ 40 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है

इसके विपरीत, स्व-नियोजित होने की आकांक्षा व्यापक रूप से जनता के बीच नहीं पाई जाती है।

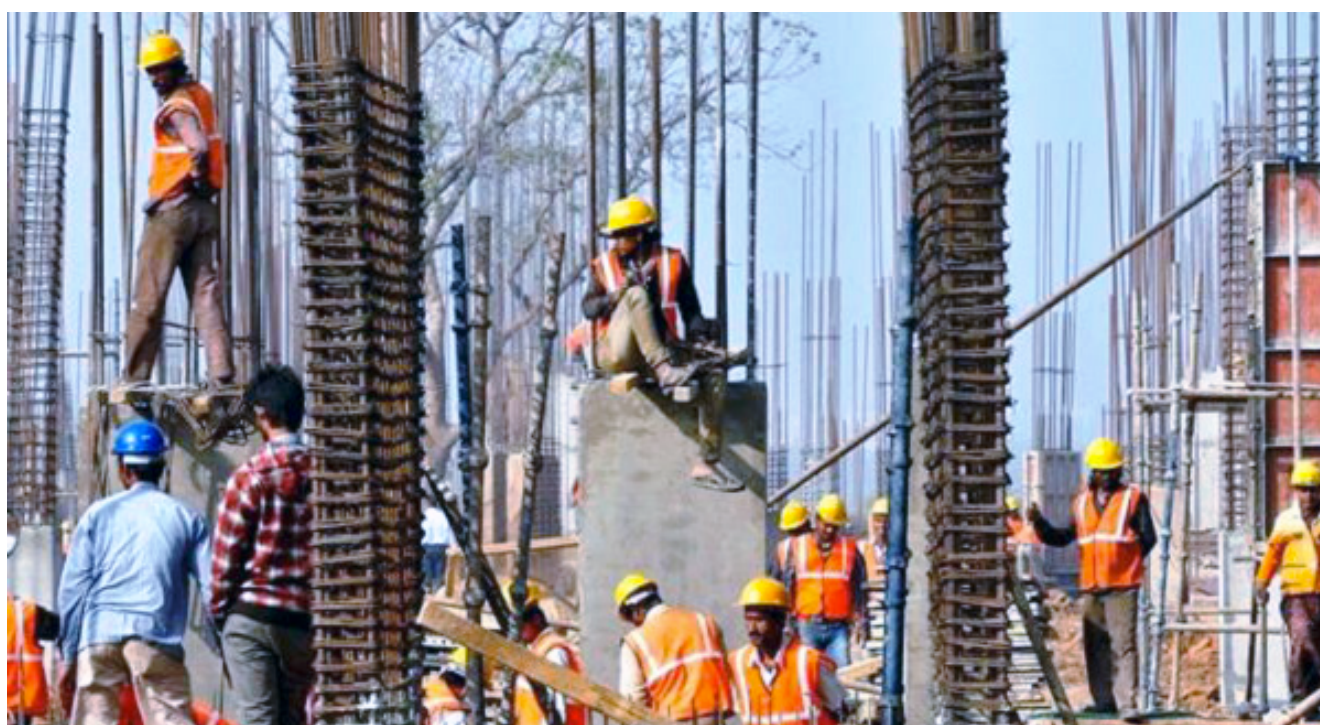
जैसा कि पटारा आदि ने अपने अध्याय में इस खंड में समावेशी प्रवेश की पूर्वता पर रिपोर्ट दी है

“उत्तर प्रदेश में ग्रामीण समुदायों के साथ लेखकों की एक टीम द्वारा 2017 में एक-से-एक संवाद करने से पता चला, कि लगभग 1500 की आबादी वाले एक गाँव में, केवल 14 व्यक्तियों ने एक साथ एक उद्यम स्थापित करने के बारे में सोचा, और उनमें से केवल 6 लोगों द्वारा ही मिलकर एक संयुक्त उद्यम की शुरुआत कर पाए थे। (वर्मा एट अल, 2017)।” के अनुसार)

1500 की आबादी में से केवल 14 लोगों द्वारा एक साथ उद्यमलगाने के बारे में सोचना, यह सूक्ष्म उदाहरण है, यानि 1 प्रतिशत से थोड़ा कम, यहाँ तक कि एक उद्यम स्थापित करने की सोच भी, गंभीर रूप से समस्याग्रस्त है, क्योंकि एक सरकारी रोज़गार या एक निजी क्षेत्र की रोज़गार भी, पक्की नौकरी (नियमित) होने जा रही हैं। एनएसएस की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 के दौरान भारत में 6.34 करोड़ उद्यम होने के बावजूद भी लोगों ने निजी उद्यमों में रोज़गार करना पसंद क्यों नहीं किया। जबकि इनमें से अधिकांश भाग छोटे और अनौपचारिक थे, जो आमतौर पर मालिक के घर के परिसर के भीतर या उसके आस-पास ही स्थित होते थे।

राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) घरों में चलने वाले उद्यमों के लिए "स्वयं के उद्यम" शब्द का उपयोग करता है, और इनमें सभी उद्यमों के लगभग 84 प्रतिशत श्रमिक काम करते हैं। 2015-16 में अपने स्वयं के उद्यमों का औसत सकल मूल्य 7,980 रुपये प्रति माह था। इस तरह के कम (जीवीए) सकल मूल्य संगृहीत के साथ, सूक्ष्म उद्योग (माइक्रो-एंटरप्राइजिज) सबसे अच्छा स्वरोज़गार पैदा कर सकते हैं। वे दूसरों को रोज़गार नहीं दे सकते। एनएसएसओ द्वारा नौकरियों के लिये बड़े उद्यमों को "प्रतिष्ठान" कहा जाता है, जहाँ औसत (जीवीए) कुल वेतनमान करीब 53,425 प्रति माह तक होता है। परन्तु फिर भी लोग सरकारी रोज़गार की तलाश करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर 1.5 सेक्शन में देखा है, कि इन नौकरियों को सरकारी नौकरियों की अपेक्षा कम पसंद किया जाता है, जहाँ वेतन अधिक होता है, और कार्यकाल की सुरक्षा होती है।

2.3 भौगोलिक असंतुलन - गांव में श्रमिक और शहर में रोज़गार



ग्रामीण भारत में रहने वाली जनसंख्या का हिस्सा जो 1960 में 82 प्रतिशत था, वह 2020 में घटकर 65.5 प्रतिशत हो गया है, यानि 16.5 प्रतिशत कम हो गया है और अभी 2030 तक इसके लगभग 60 प्रतिशत तक नीचे जाने का अनुमान है। साथ ही, पशुपालन जैसी कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, जैसे- मत्स्य पालन, और वानिकी, जो ग्रामीण भारत के लिए एक प्रमुख आजीविका थे, ने भी रोज़गार में गिरावट दिखाई है, जिसने (PLFS) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में केवल 44.15 प्रतिशत श्रमिकों को रोज़गार दिया दिखाया है।

2.3.1 गैर-कृषि आजीविका संवर्धन अपर्याप्त था

राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), 2005 में बताया कि 2003 में किसानों पर एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें पाया गया, कि 40 प्रतिशत से अधिक किसान कृषि कार्यों से बाहर निकलना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, कि पिछले दो दशकों में 4 करोड़ से अधिक किसानों ने कृषि से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की है। यह चीन में एक बड़े पैमाने पर हुआ है - जब 1979 से 1989 में 10 करोड़ से अधिक लोगों को कृषि कार्य से टाउनशिप और ग्राम उद्यमों (टीवीई) में स्थानांतरण किया गया था। (ज़ियोलन फू और बालासुब्रमण्यम 2002) के अनुसार, 1999 तक टाउनशिप और ग्राम उद्यम, (TVE) चीन की 18 प्रतिशत श्रमिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे और चीन के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 61 प्रतिशत तक का उत्पादन करते थे, जिसकी कीमत लगभग USD 3867 बिलियन थी।

भारत को भी ऐसा करने की जरूरत थी, लेकिन हमने उस नीति को नहीं चुना। ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के हमारे विचार, खादी ग्राम, और बाद में हथकरघा और हस्तशिल्प तक ही सीमित रहे। कुमारप्पा और गांधीजी ने आत्मनिर्भर गांवों के लिए आधार के रूप में जो प्रस्ताव दिया था, वह इस बात से मुक्त हो गया है। इसलिए, गैर-कृषि क्षेत्र की वृद्धि, विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिये अवशोषित करने के लिए अपर्याप्त है। (फिशर और महाजन, 1996) के अनुसार।

उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों से भी कृषि प्रसंस्करण काफ़ी हद तक कम हो गया है, उदाहरण के लिए, सोयाबीन क्षेत्र में, जहाँ अधिकांश प्रसंस्करण इकाइयाँ - कोटा, इंदौर और देवास जैसे शहरों में स्थापित हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में संसाधन, मार्केट, बेहतर कन्विक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे की बेहतर उपलब्धता होने के कारण यह अपरिहार्य था। इन कारणों ने शहरी क्षेत्रों में बड़ी इकाइयाँ स्थापित करने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कम लागत ने शहरी इकाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित समूहों में कुछ हथकरघा और हस्तकला इकाइयों को छोड़कर बाकी जारी नहीं रह सकते थे। ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का हिस्सा, जैसे - मरम्मत, खुदरा व्यापार, परिवहन और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी अनुमानित सेवाएँ जो निरंतर जारी थीं।

2.3.2 आजीविका की तलाश में ग्रामीण से शहरी प्रवास के परिणाम

चूँकि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त आजीविका नहीं है, और न ही ग्रामीण कृषि गतिविधियों में विविधता लाने के कोई अवसर हैं, इस कारण बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन हुआ। भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार भारत

में आंतरिक प्रवासियों की संख्या 45 करोड़ थी। यह 2001 की जनगणना में दर्ज 30.9 करोड़ से 45 प्रतिशत की अधिक वृद्धि है। यह 2001 से 2011 तक 17.64 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। 2001 से आंतरिक प्रवासियों की आबादी 30 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 37 प्रतिशत हो गई। इनमें से अधिकांश अन्य राज्यों में काम करने के लिए चले गए। पलायन करने वालों का एक बड़ा हिस्सा लगभग (62 प्रतिशत) राज्य के अपने जिले के अन्दर ही था। परन्तु लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा राज्य के भीतर अन्य जिलों में पलायन कर गया था।

हालाँकि पलायन करने वालों का केवल 12 प्रतिशत हिस्सा अंतर-राज्य था, लेकिन उस संख्या ने भी 5.4 करोड़ व्यक्तियों के लिए काम का प्रावधान किया।

इस प्रवास का अधिकांश हिस्सा अपरिचित स्थानों अक्सर अपने गृह राज्य के बाहर व्यतीत होता था, जहाँ रियायती खाद्यान्न जैसे अनुदान प्राप्त करने में कठिनाई होती है, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की समस्या सामने आती थी। गंतव्य स्थान पर आमतौर पर आवास का प्रबंध अव्यवस्थित और अस्थायी होता था, जिसमें पानी, स्वच्छता और खाना पकाने के लिए बदलाव की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे भी बदतर तो यह था कि, इस तथ्य के कारण कि कई प्रवासी गंतव्य राज्यों की भाषा नहीं बोल सकते थे, इसलिये वे ठेकेदारों और एजेंटों की दया पर निर्भर रहते थे, जो उन्हें वहाँ काम के लिये लाते थे, वे उनसे ही नकद अग्रिम की पेशकश करते थे।

इस बड़े प्रवास का एक मुख्य कारण राज्यों में उत्पादन और रोजगार के विकास में लगातार असमानता का होना है। संजीव कुमार और फाल्गुनी पट्टनायक के एक अध्ययन (2020), के अनुसार, भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य दोनों वर्गों (उत्पादन और रोजगार) के क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित हुए हैं, जबकि मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य इस वर्ग में पिछड़ गए हैं। बिहार से पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश से मुंबई, ओडिशा से गुजरात के सूरत और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर तमिलनाडु और केरल तक के स्थानों की ओर बाढ़ मुख्य कारण रहा है।

पिछले कुछ महीनों में COVID महामारी के दौरान शहरों से अपने घर गांवों में काम करने के स्थानों से हाल के रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है परन्तु हम यहाँ इस बात को नहीं दोहराएंगे, सिवाय यह कहने के, कि यह महाकाव्य अनुपात की एक भयंकर त्रासदी थी, जो हमारे समाज लिए एक बदनुमा धब्बा था। हमें अब एक दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है, जिससे कि इसे दोबारा से भारत के इतिहास में दोहराया न जा सके।

2.4 विकृत प्रोत्साहन उद्यमियों को श्रमगहन तकनीक उपयोग करने से हतोत्साहित करते हैं



फर्म या उद्यम किसी भी आर्थिक क्षेत्र के मुख्य घटक हैं, और वे स्वाभाविक रूप से अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करते हैं, जो बाजार की प्रतिस्पर्धा और नियामक बाधाओं के अधीन हैं। एक उद्यम को अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए, उत्पादन के कारणों के सापेक्ष मूल्य - भूमि, श्रम और पूँजी - प्रौद्योगिकी की पसंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई कल्पना करेगा, कि एक अतिरिक्त श्रम और पूँजीगत लघु अर्थव्यवस्था में, उद्यम की प्रवृत्ति उत्पादन तकनीकों का चयन करने के लिए होगी, जो अधिक श्रम और कम पूँजी के लिये जमीन पर काम करते हैं। हालाँकि, व्यवहार में, ऐसा नहीं हम पाते हैं कि दशकों के बाद, भारतीय उद्योगों ने अपनी सापेक्ष कीमतों की तुलना में अधिक पूँजी गहन और अधिक श्रम बचत उत्पादन तकनीकों का उपयोग किया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं।

2.4.1 श्रम कानूनों ने बड़े उद्यमों को पूँजी प्रधान तकनीक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है

एक सामान्य व्याख्या यह भी है, कि श्रम कानूनों में अधिकता होने की वजह से नियोक्ताओं के लिए बाजार की स्थिति के जवाब में लचीला होना भी मुश्किल हो जाता है - एक बार जब वे एक श्रमिक को अपने पास काम पर रखते हैं, और तब भी जब बाजार में माँग कम होती है, वे आसानी से अपने श्रमिक को जाने भी नहीं दे सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया हुई है। बड़ी संख्या में बड़े उद्यम तब श्रम बचत प्रौद्योगिकी, उपकरण और मशीनरी में निवेश का विकल्प चुनते हैं। यह निवेश अपेक्षाकृत सस्ते संस्थागत वित्त के लिए आसान था, और इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2 में देखा जा सकता है, कि सबसे बड़े कारखानों ने नियोजित सभी पूँजी का केवल एक चौथाई हिस्से का ही इस्तेमाल किया है, और अभी तक कारखानों में कुल श्रमिकों के केवल बारहवें हिस्से के श्रमिक ही कार्यरत हैं, जो कारखानों द्वारा जोड़े गए सभी तरह की मूल्यों के केवल आठवें हिस्से के लिए ही जिम्मेदार हैं।

तालिका 2: 2017-18 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

मुख्य श्रमिकों की संख्या :	0-19	20-99	100-499	500-4999	कम से कम 5000
कुल कारखानों का :	47.1%	33.8%	14.3%	4.4%	0.3%
निश्चित पूँजी का उपयोग	3.5%	8.2%	19.6%	44.7%	24.1%
काम में लगे हुए लोग :	5.0%	18.4%	32.1%	35.9%	8.6%
किया गया उत्पादन :	4.1%	15.3%	25.8%	40.1%	14.6%
शुद्ध वर्धित मूल्य :	2.2%	11.7%	25.0%	47.5%	13.6%

स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (2017-18); (पीआरएस) एक गैर-लाभकारी संगठन

हालाँकि, अधिकांश छोटे उद्यमों, को पूँजी की कमी के कारण अधिक श्रम सघन उत्पादन तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। हालाँकि, वे कम मजदूरी का भुगतान करके, किसी भी तरह का लाभ नहीं देने और काम में कमी करने और जोखिम में कमी लाने या काम करने की स्थिति में सुधार करके श्रम लागत को बचाने की कोशिश करते हैं।

पहले भी छोटे उद्यमों में श्रम कानूनों को लागू करना कठिन था। हाल ही में लागू किए गए चार श्रम कानूनों प्रवर्तन को और भी अधिक कठिन बनाते हैं, क्योंकि श्रमिकों की संख्या के मामले में प्रयोग लागू करने की सीमा को और बढ़ा दिया गया है और अधिकारियों द्वारा साइट पर दौरा करने को कठिन बना दिया गया है, जिससे दौरा करने से पहले उसके लिये आंतरिक अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। अधिकांश अनुपालन (इजाजत) को स्वयं-रिपोर्टिंग, स्वयं-प्रमाणन के आधार पर नियोक्ताओं के लिए आसान बनाया गया है। इस तथ्य के साथ कि अधिकांश अनौपचारिक श्रमिक संगठित ट्रेड यूनियनों के सदस्य नहीं हैं, इसलिये उन्हें नियोक्ताओं की दया पर छोड़ दिया जाता है।

2.4.2 अनौपचारिक और प्रवासी श्रमिकों पर नए श्रम कानूनों का प्रभाव

सिविल सोसाइटी पत्रिका द्वारा पूछे जाने पर, "क्या आपको लगता है कि नए श्रम संहिता से रोज़गार में सुधार होगा जैसा कि उद्योग कहता है?", आजिविका ब्यूरो के संस्थापक राजीव खंडेलवाल ने कहा, "स्पष्ट रूप से, नहीं।

क्या उद्योग इस बात से खुश है कि अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विनियमन के दायरे से बाहर रखा जा रहा है - और यूनियनों को लगभग निरर्थक बनाकर औद्योगिक कार्रवाई की क्षमता को बदलकर, इस औपचारिककरण का क्या मतलब है। और वास्तव में यह भी बहुत ही विरोधाभासी कथन है, कि इस प्रवासी संकट के समय में ही ये कानूनों पारित किए गए हैं। इस समय हमें मज़दूर समर्थक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता थी। कोइस मौलिक श्रमिक संरक्षण को दूर कर रहे हैं। वैसे भी श्रम कानूनों को बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं किया जाता है। वे औद्योगिक विकास के रास्ते में नहीं आते हैं। उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए कानूनों एक और अधिक धोखा देने वाला संकेत हैं और वे जो कुछ भी करते हैं उसे श्रम के साथ जारी रखते हैं, वो भी अधिक प्रभाव के साथ।

2.4.3 कौशल और उद्यम विकास के लिए प्रयासों को फिर से करने की आवश्यकता है

अनौपचारिक क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों का अनुपात अधिक है। अधिकांश श्रमिकों ने अक्सर पुराने श्रमिकों से अपने काम से संबंधित न्यूनतम आवश्यक कौशल सीखे, जो उनके जानकार या दोस्त थे। उस्ताद (निपुण श्रमिक, प्रशिक्षक) से शागिर्द (प्रशिक्षु) तक कौशल हस्तांतरण के लिए कुछ अर्ध-औपचारिक प्रथाएँ थीं। भारत में औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का अनुपात, चीन के 24 प्रतिशत, जर्मनी के 75 प्रतिशत, और दक्षिण कोरिया के 96 प्रतिशत की तुलना में 4.7 प्रतिशत है। इसके जवाब में, भारत सरकार ने कौशल विकास के लिए एक नया इको-सिस्टम बनाया, जिसकी शुरुआत 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण से हुई। 2010 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई, और एक राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क अपनाया गया। जिसमें बहुत सारे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन इनके रोज़गार पर प्रभाव बहुत सीमित थे, जिस कारण आंशिक रूप से भी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नौकरियाँ पैदा नहीं हो रही थीं।

भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर शोध / पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी (PRICE), 2016 के सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारी कौशल स्तर 1 (अकुशल, बस दिनचर्या में लगे हुए, मैनुअल कार्य) में आते हैं, 56 प्रतिशत कर्मचारियों को कौशल स्तर 2 में वर्गीकृत किया गया है, जो (मशीनरी और

उपकरण का उपयोग करने में सक्षम) हैं। लगभग 11 प्रतिशत आबादी को कौशल स्तर 3 (स्तर 2 कौशल के अलावा कुछ लेखन और संख्यात्मक कौशल) में वर्गीकृत किया गया है, जबकि कौशल स्तर 4 के श्रमिक (पेशेवर कौशल) केवल 3 प्रतिशत थे। कौशल स्तर -1 के आधे से अधिक व्यक्ति 15-35 वर्ष आयु के समूह में थे, जबकि इस समूह ने अन्य प्रकार के कौशल स्तर के लिए लगभग 40 प्रतिशत का गठन किया है। इसका मतलब युवा श्रमिक कम कुशल थे। कौशल स्तर ,4के एक तिहाई से अधिक व्यक्ति वर्ष आयु वर्ग के थे। 45-36साथ ही शहरी क्षेत्रों में कौशल स्तर प्रतिशत 26 के मात्र 2 व्यक्ति हैं।

केवल 13 प्रतिशत कौशल स्तर 1 के श्रमिक नियमित वेतनभोगी कर्मचारी थे। इसके विपरीत, कौशल स्तर 4 के 60 प्रतिशत ने नियमित वेतन अर्जित किया। इससे कोई सोचता है, कि यह उनके कौशल विकास में युवाओं के परिवारों द्वारा निवेश के लिए एक महान प्रोत्साहन होगा। इसके विपरीत, कौशल विकास में अधिकांश पेशेवर शिकायत करते हैं, कि उन्हें युवा लोगों को कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिये दाखिला लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भले ही ये प्रशिक्षण मुफ्त में या अत्यधिक सब्सिडी में दिये जाते हों। ऐसा क्यों है? इसका जवाब तब मिलता है, जब कोई उन युवा लोगों से बात करता है, जो कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाये।

इस कारण शायद ही उन्हें कोई रोज़गार मिल पाये, जो उनकी वेतन आकांक्षाओं (जरूरतों) को पूरा करती है। यह युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है, इसके लिए वे अकेले खुद इसको महसूस करते हैं। बदले में, यह कौशल प्रदाता को कम से कम न्यूनतम इनपुट देता है, जिससे उन्हें कौशल प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी कार्यक्रम द्वारा भुगतान किया जा सके। इसलिए, पूरा कौशल क्षेत्र एक दलदल में चला गया है।

इसलिए स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, इसमें उद्यमिता के विचार को जोड़ा गया, और कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, और कौशल पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। विकास और उद्यमिता कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। चूँकि स्व-रोज़गार के लिए क्रेडिट ऋण की आवश्यकता होती है, इसलिए सूक्ष्म-उद्यमियों को ऋण बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई गई थी।

2.4.4 ऋण पहुँच तो बढ़ी, लेकिन रोज़गार पर प्रभाव कम पड़ा

अन्य क्षेत्रीय नीतियाँ आजीविका के खिलाफ हैं। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की प्रदर्शन क्षमता को सीमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक वित्त तक पहुँच है। क्रेडिट का अंतर माँग और आपूर्ति दोनों कारकों के कारण होता है। **माँग पक्ष**, कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऋण प्राप्त करने के लिए वित्तीय दस्तावेज और अनुप्रासंगिक आवश्यकताओं के कारण ऋण का उपयोग नहीं कर सकते हैं; एवं उच्च ब्याज दर, और ऋण के लिये कई अन्य लोगों के बीच लंबी अनुमोदन प्रक्रियाएँ भी इसमें बाधक हैं। **आपूर्ति पक्ष**, बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उच्च जोखिम वाले और उच्च लागत वाले ग्राहकों के रूप में मानते हैं, इसलिये ये कारक बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऋण देने से रोकते हैं और बड़ी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं।

भारत सरकार में 1950 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्तमान सरकार ने अप्रैल 2015 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) योजना शुरू की, गैर-कृषि आय-उत्पादक ऋण देने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा 10 लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है। इस योजना में ऋण की तीन श्रेणियाँ हैं - शिशु, किशोर और तरुण, पहले ऋण के लिए 50,000/- रुपये तक, दूसरा 50,000/- रुपये से 5,00,000/- रुपये और तीसरा 5,00,000/- रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। PMMY ने MSMEs के लिए असुरक्षित ऋण की पेशकश की, जो मौजूदा व्यवसायों में निवेश के लिए ऋण की आवश्यकता है, साथ ही नए स्टार्ट-अप के लिए भी। ऋण का एक बड़ा हिस्सा, सबसे छोटी श्रेणी का था, जो 50,000/- रुपये से कम था। 2015 में PMMY की शुरुआत से लेकर 2019 के अंत तक PMMY में 21.13 करोड़ लोन दिए गए और वितरित राशि 10.59 लाख करोड़ रुपये थी।

हालाँकि, रोज़गार सृजन पर इन ऋणों का प्रभाव बहुत सीमित था। योजना के रोलआउट के बाद पहले 33 महीनों को शामिल (कवर) करते हुए, 2018 में 97,000 PMMY उधारकर्ताओं को कवर करने वाला श्रम मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से अनुमानित किया गया कि अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 के दौरान 1.12 करोड़ अतिरिक्त आजीविकाएँ सृजित की गईं। इनमें से 51.06 लाख स्व-नियोजित या कामकाजी मालिक और उनके परिवार के सदस्य थे जबकि 60.94 लाख कर्मचारी या वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी थे। उद्यमीओं में से केवल 29 प्रतिशत ने किसी नए रोज़गार सृजन की सूचना दी थी। इनमें से शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों के तहत ऋण के लिए नया रोज़गार सृजन प्रतिशत क्रमशः 66, 19 और 15 प्रतिशत था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाँच में से केवल एक उद्यमी (20.6%) ऋण का नए रोज़गार लगाने में उपयोग किया, जबकि शेष उद्यमीओं ने अपने मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए ही PMMY लोन का उपयोग किया था।

पहले तीन वर्षों के दौरान, PMMY के तहत 8.94 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए थे। तीन श्रेणियों के तहत प्रदान किए गए ऋण के कारण 1.12 करोड़ नए रोज़गार सृजित हुए। बनाई गई अतिरिक्त आजीविकाएँ की संख्या के आधार पर वितरित किये गये ऋण की कुल राशि का विभाजन करते हुए, एक निष्कर्ष यह निकाला गया, कि PMMY के तहत प्रत्येक अतिरिक्त रोज़गार के निर्माण के लिए लगभग 8 लाख रुपये का ऋण दिया गया था। इसके अलावा उद्यमी ने स्वयं की पूँजी भी लगायी होगी जिसका अनुमान नहीं है परन्तु हम समझ सकते हैं की एक आजीविका के सृजन में कम से कम 12 लाख रुपये की लागत रही।

2.4.5 अर्थव्यवस्था को खोलना आजीविका के प्रकार में बदलाव का कारण बना

एक क्षेत्रीय नीति का एक और उदाहरण जो आजीविका के विरुद्ध है, वह व्यापार नीति है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत अपने दायित्वों का पालन करते हुए, भारत को शुल्क कम करना पड़ा है, और आयात के लिए अपने घरेलू बाजारों को खोलना पड़ा है। इसके बदले में, भारत ने विश्व बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है, विशेषकर सेवाओं में। इसके चलते सॉफ्टवेयर के भारतीय निर्यात में काफ़ी उछाल आया और अन्य आईटी सक्षम सेवाएँ जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, 2003-04 में 12.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 99 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई।

UNCTAD (2008) के अध्ययन में पाया गया कि "2003-04 से 2006-07 तक निर्यात में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था के 46 उप-सेक्टरों में रोज़गार की सीमा बढ़ गई ..2003-04 की अवधि में निर्यात में भी वृद्धि हुई। 2006-07 में 2.6 करोड़ लोगों का रोज़गार प्रति वर्ष बढ़ा। कृषि में भी 0.6 करोड़ लोगों का अतिरिक्त रोज़गार उत्पन्न हुआ, जिसमें गरीबों की अधिक संख्या है।"

हालाँकि, उसी समय, चीन और पूर्वी एशियाई देशों में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात से घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में भारी गिरावट आई, और इसमें आजीविका का नुकसान हुआ। इसलिए, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए और भारतीय व्यापारिक उद्यमों के लिए एक वरदान क्या था, यह विनिर्माण उद्यमों और उनके श्रमिकों के लिए एक निकला।

गोल्डर (2009) के अनुसार, "बारह उद्योग - वनस्पति और पशु तेल और वसा का निर्माण; कटलरी, हाथ-उपकरण और सामान्य हार्डवेयर; बिजली के लैंप और प्रकाश उपकरण; रेडियो, टेलीविजन, और ध्वनि और वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण; कपड़ा फाइबर की तैयारी और कटाई ... प्रतिवर्ष 5 से 10 प्रतिशत की दर से रोज़गार में गिरावट का अनुभव रहा है...

सरकार ने इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने की कोशिश की। इसने विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आमंत्रित किया था, जो न केवल पूँजी लाया, बल्कि प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुँच और उच्च कौशल नौकरियों का सृजन किया। (नीचे आयत 4 देखें)।

आयत 4: नीमराना, राजस्थान में जापानी विनिर्माण कंपनियों के लिए समूह

इंडो-जापानी उद्यम के रूप में मारुति उद्योग लिमिटेड की सफलता ने लगभग 1000 जापानी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये आकर्षित किया, जिनमें से कई मोटर वाहन उद्यम और उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण में शामिल हैं। नीमराना दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में, 1200 एकड़ क्षेत्रफल में राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम (RIICO) और जापान बाहरी व्यापार संगठन (JETRO) की पहल के साथ 2014 में स्थापित किया गया था। (मोटोहशि, 2015 के अनुसार)

2020 तक, वहाँ 50 से अधिक बड़े जापानी कंपनी के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, 2020 तक 100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश यहाँ किया गया था, और यहाँ पर होटलों और रेस्तरां जैसी सहायक सेवाओं में लगभग 150,000 नौकरियाँ पैदा हुई हैं। एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और एनआईआईटी जैसे कई निजी विश्वविद्यालयों ने यहाँ अपने शैक्षिक केंद्र स्थापित किये हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) के हिस्से के रूप में, एक कंटेनर हब और भारत के सबसे बड़े शुष्क बंदरगाहों में से एक यहाँ स्थापित किया जा रहा है।

फिर भी, ऐसे उदाहरणों पर आंशिक रूप से ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वे उद्योग जो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने 2011-20 के दशक में रोज़गार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे सरकार पर सुरक्षात्मक टैरिफ लगाने का दबाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। हालाँकि यह इन उद्योगों में रोज़गार की रक्षा करने के लिए अस्थिर रूप से किया गया था, लेकिन लंबे तक होने के कारण यह इन उद्योगों को कम प्रतिस्पर्धी बना देता है, जिससे उन्हें अचानक बंद होने के रूप में और फिर से आयात करने के लिए असुरक्षित बना दिया जाता है। भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने बढ़ाने के लिए 2020 में भारत सरकार ने 10 प्रमुख

क्षेत्रों में 145,980 करोड़ रुपये के उत्पादन के साथ उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। हालाँकि, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर रहकर, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जनसंख्या का कुल 30 प्रतिशत है, भारत कहता है कि वह निर्यात करना चाहता है लेकिन आयात करना नहीं चाहता। जबकि यह संभव नहीं है, क्योंकि एक तरह से खुलने जैसी कोई बात नहीं हो सकती है।



3 इस दशक के लिए आजीविका चुनौतियाँ

इस खंड में, हम आगामी 2021-30 के दशक में 12 करोड़ नई आजीविका पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था की मात्रात्मक व्यवहार्यता को देख रहे हैं। लेखक ने इन संख्याओं की गणना की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जनसांख्यिकी और श्रम अर्थशास्त्री इसका अधिक सटीक अनुमान लगाने में सक्षम हैं। हालाँकि, हम ऐसा करने की सख्त आवश्यकता के कारण का प्रारंभिक प्रयास कर रहे हैं।

3.1 2030 तक सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करना



सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए भारत को 2021-2030 के दशक में कितनी आजीविका (नौकरियाँ) उत्पन्न करने की आवश्यकता है? यह इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, कि श्रमिकों की भागीदारी दर में वृद्धि दर के लिए किस संख्या को माना जाता है। चूँकि अधिक संख्या में बेरोजगारी ने COVID को काफी हद बढ़ा दिया है, इसलिए उनके कामकाजी जीवन (बेरोजगारी) से अधिक से अधिक लोग निराश हो गए हैं और पूरी तरह से श्रमिक, कार्यों से बाहर हो गए हैं। हालाँकि, हमें यकीन है, COVID महामारी के कारण बढ़े हुए आर्थिक तनाव के साथ भी, श्रम शक्ति की भागीदारी दर (LFPR) में गिरावट को काफी कम किया जा सकता है, क्योंकि घरेलू आय को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक महिलाएँ और युवा (रोज़गार) के लिये आगे आ सकते हैं। और उसी समय, श्रम बल में वृद्धि पिछले दशक की तुलना में कम होगी, क्योंकि 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 1991-2001 के दशक में 21.15 प्रतिशत से घटकर 17.64 प्रतिशत रह गई थी। और 2001-2011 के दशक में पैदा हुए बच्चे 2021-2030 के दशक में श्रम बल में प्रवेश कर रहे होंगे।

इन दो विरोधाभासी रुझानों को याद करते हुए, हम यह मानते हैं, कि श्रम बल की वृद्धि दो दशक पहले की जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाएगी। इस प्रकार, हम यह कहते हैं कि श्रम बल 2021 में 51.97 करोड़ से बढ़कर 2030 में 61.14 करोड़ हो जाएगा, मतलब 9.17 करोड़ व्यक्तियों के लिये रोज़गार की शुद्ध वृद्धि होगी। (लेखक की गणना, जांच के लिए उपलब्ध)

यदि हम इसके बजाय यह धारणा बनाते हैं, कि श्रम बल 2000-2020 की अवधि के समान वार्षिक (CAGR) चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा, जो कि प्रति वर्ष 1.17 प्रतिशत था, तो 2030 तक श्रम बल बढ़कर 58.39 करोड़ हो जाएगा, तो 6.41 करोड़ की शुद्ध वृद्धि होगी।

(CMIE) भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक बेरोजगारों की अनुमानित संख्या लगभग 4.73 करोड़ थी। तो, 2021 की शुरुआत में कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 47.1 करोड़ होगी, अब 2030 में कार्यबल की गणना करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी समय कुछ बेरोजगारी होना तय होता है। इस तरह हम 2030 में 61.14 करोड़ श्रम बल के लिये 3 प्रतिशत बेरोजगारी की आधार दर को मानते हैं इसका मतलब 2030 में 1.83 करोड़ बेरोजगार होंगे। इस प्रकार, हम 2030 में कर्मचारियों की संख्या 59.31 करोड़ होने का अनुमान लगाते हैं,

यदि हम जनसंख्या आधारित (CAGR) चक्रवृद्धि वार्षिक की वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत या 56.64 करोड़ मान लें, या हम 1.17 प्रतिशत के 2000-2020 (CAGR) चक्रवृद्धि वार्षिक की वृद्धि दर भी मान सकते हैं। हमें यह विश्वास है कि इससे श्रम शक्ति भागीदारी दर ऊपर जाएगी, आंशिक रूप से महिला (LFPR) श्रम शक्ति की भागीदारी दर ऊपर जाएगी और आंशिक रूप से युवाओं पर कमाने का दबाव भी बढ़ेगा। इसलिए, हमारा मानना है कि भारत को 2021-30 के दशक में 12 करोड़ नई आजीविकाएँ सृजित करने की आवश्यकता होगी।

हम आजीविका संकट के पहले के चार पहलुओं के साथ जारी रखते हैं, और इसे 12 करोड़ नई आजीविका की कुल संख्या में लागू करते हैं, अर्थात् आजीविका का जनसांख्यिकीय वितरण, श्रमिकों की व्यावसायिक स्थिति, भौगोलिक वितरण और क्षेत्रीय विकास आधारित आजीविका।

जनसंख्या की दृष्टि से : ये आजीविका मुख्य रूप से महिलाओं और युवा श्रमिकों (15 से 29 वर्ष) के लिए आवश्यक हैं, (LFPR) श्रम शक्ति की भागीदारी दर 2018 में औसत से कम था। युवा (LFPR) श्रम शक्ति की भागीदारी दर 38.2 प्रतिशत थी, जो कुल कामकाजी उम्र (15-59 वर्ष) की आबादी के लिए 49.8 प्रतिशत (LFPR) से बहुत कम था।

व्यावसायिक स्थिति की दृष्टि से : इन आजीविका का अधिकांश हिस्सा या तो स्वरोजगार या अनियमित और अनुबंध श्रमिकों के रूप में होगा। हालाँकि औपचारिक क्षेत्र में स्थिर, आजीवन आजीविका 2030 में भी एक प्रमुख अनुपात होने की संभावना नहीं है, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा लाभ, और औपचारिक नौकरियों में नहीं उन लोगों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

भौगोलिक दृष्टि से : ये आजीविका शहरी क्षेत्रों में भी होनी चाहिए, केवल महानगरों में ही नहीं। इन आजीविका को दूसरे शहरों, जिला मुख्यालयों, और छोटे शहरों में भी होना चाहिए। हमें जिला स्तरीय रोजगार योजनाओं के बारे में सोचना चाहिए।

आर्थिक उप क्षेत्र की दृष्टि से: इन आजीविकाओं को कृषि-प्रसंस्करण, शिल्प और विनिर्माण, व्यापार और परिवहन, और भंडारण से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक सेवाओं, तक सभी प्रकार की सेवाओं के निर्माण, आवास और छोटे बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सूक्ष्म-उद्यम स्थापित करने होंगे।

3.2 उपेक्षित जन खंडों के लिए रोज़गार में वृद्धि को बढ़ावा देना



इस खंड में, हम देखते हैं कि महिलाओं और युवाओं के लिए रोज़गार की कितनी आवश्यकता है।

3.2.1 महिला श्रमिकों के लिए रोज़गार

इसी तरह महिला श्रमिकों के लिए रोज़गार की वृद्धि पुरुषों की तुलना में अधिक होनी चाहिए। हमने इस दशक में 20 से 30 प्रतिशत तक श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी के बारे में एक आकांक्षात्मक लक्ष्य दिया है। इसके लिये (नीचे तालिका 6 देखें)। इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में अगले भाग में बताया गया है। इसके लिए कई लिंग विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

तालिका 3: 2021-30 के लिए लिंग द्वारा लक्षित रोज़गार वृद्धि

विवरण :	विश्व बैंक डेटा बैंक, 2020		वर्ष 2030-31 के लिए अनुमान		2020-31 में वृद्धि
	% प्रतिशत में	करोड़ में	2030-31	करोड़ में	करोड़ में
पुरुष श्रमिक	80.1%	37..6	70.0%	41.52	3.76
महिला श्रमिक	19.9%	9.38	30.0%	17.79	8.41
श्रमिकों की कुल संख्या	100.0%	47..14	100.0%	59.31	12.17

स्रोत : 2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर २०३० के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों पर आधारित लेखक की गणना

कोई अनुमान नहीं लगाया गया क्योंकि ट्रांस श्रमिकों पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उनका उल्लेख किया जाता है क्योंकि उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 2011 में जनगणना कार्यालय ने 4.9 लाख ट्रांस व्यक्तियों का अनुमान लगाया है। हम 2021 की जनगणना का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि अगर उनकी संख्या लगभग दस लाख है, तो उन सभी के लिए सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आनुपातिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

3.2.2 विकलांग व्यक्ति

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ यानि (2.21 प्रतिशत) विकलांग व्यक्ति थे। विकलांग लोगों के लिए रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र के अनुसार, विकलांग लोगों की जो वास्तविक संख्या जनगणना में सामने आई है, हालाँकि, उससे कहीं अधिक है, 5 से 15 प्रतिशत आबादी तक का अनुमान है।

हालाँकि विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम को 1995 में अपनाया गया था, लेकिन विकलांग लोगों के लिये औसत रोज़गार दर अनुपात से कम थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) की 2011 की रिपोर्ट 'पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड द इंडिया लेबर मार्केट: चुनौतियाँ और अवसर' ने कहा कि भारत में 73.6 प्रतिशत विकलांग अभी भी श्रम बल के बाहर हैं। इनमें से मानसिक विकलांग, विकलांग महिलाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोग उपेक्षित लोग थे।”

विकलांग व्यक्तियों के रोज़गार के लिए, आकांक्षात्मक लक्ष्य इसीलिए एक श्रमिक आबादी के अनुपात में शेष जनसंख्या के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है, कि आने वाले दशक में लगभग 1.2 करोड़ विकलांगों को काम मिलना चाहिए। यह कुल वृद्धिशील आजीविका का लगभग 10 प्रतिशत है। यह स्पष्ट रूप से थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि विकलांगों के लिए 6 करोड़ आजीविका का लक्ष्य अपनाना शायद अधिक यथार्थवादी है।

3.2.3 युवाओं के लिए रोज़गार

हमें न केवल कुल 12 करोड़ आजीविका पैदा करने के बारे में चिंता करनी है, बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करना है, कि युवा श्रमिकों (15-29 वर्ष की आयु) के लिए आजीविका का विकास 30 से 64 वर्ष की आयु में श्रमिकों के लिए तेजी से बढ़ने चाहिये। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा, कि 15 से कम उम्र के लोगों की संख्या, बाल श्रम, और 64 से ऊपर के लोग अपने निर्वाह के लिए काम कर रहे हैं।

तदनुसार, हमने युवा आयु के श्रमिकों के लिए रोज़गार में 8.33 करोड़ की उच्च वृद्धि के लिए कुछ आकांक्षात्मक लक्ष्य (नीचे दी गई तालिका 7 देखें) और वास्तव में 4.74 करोड़ गैर-कामकाजी आयु के व्यक्तियों के रोज़गार में गिरावट दर्ज की है। यह देखते हुए, कि भारत के 78 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों को कोई पेंशन नहीं मिलती है, हमें उस प्रणाली को अलग से स्थापित करना होगा। इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में आगे बताया गया है।

तालिका 4: आयु समूहों द्वारा लक्षित रोज़गार वृद्धि

विवरण	2017-18 का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण% 2020 तक लागू			2030-31 के लिए लक्ष्य और अनुमान		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
युवा श्रमिक (15 से 29 वर्ष)	21.6%	34.1%	26.6%	28.6%	45.6%	34.0%
सामान्य उम्र के श्रमिक (30-64 वर्ष)	70.2%	57.7%	67.2%	73.2%	55.2%	67.5%
15 से कम और 64 वर्ष से अधिक के श्रमिक	8.2%	8.2%	6.2%	-1.8%	-0.8%	-1.5%
श्रमिकों की कुल संख्या करोड़ में	339.0	132.4	471.4	404.6	188.5	593.1
युवा श्रमिक (15 से 29 वर्ष)	73.2	45.1	125.4	115.7	86.0	201.7
सामान्य उम्र के श्रमिक (30-64 वर्ष)	238.0	76.4	316.8	296.2	104.1	400.2
15 से कम और 64 वर्ष से अधिक के श्रमिक	27.8	10.9	29.2	-7.3	-1.5	-8.8
2030 तक नियोजित किए जाने वाले अतिरिक्त युवा श्रमिक			करोड़	4.25	4.08	8.33
2030 तक नियोजित किए जाने वाले सामान्य आयु के श्रमिक			करोड़	5.82	2.77	8.59
2030 तक 15 से कम और 64 वर्ष से अधिक के श्रमिकों को कम किया जायेगा			करोड़	-3.51	-1.24	-4.74

स्रोत : 2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) डेटा का उपयोग करते हुए, 2030 के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों पर आधारित लेखक की गणना

3.2.4 - स्व-नियोजित, नियमित या अनियमित श्रमिकों की रोज़गार स्थिति

स्व-नियोजित श्रमिकों के लिए और नियमित वेतन / वेतनभोगी श्रमिकों के लिए नौकरियों की वृद्धि दर अधिक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आने वाले दशक में मध्यम-आय की स्थिति में परिवर्तन कर देती है। हमने इस दशक में आने वाले कार्यबल (श्रम) में उनके हिस्से के रूप में केवल 2020 के स्तर से थोड़ा अधिक दिया है। हमने अनियमित श्रमिकों की हिस्सेदारी में गिरावट का लक्ष्य भी रखा है, हालाँकि उनकी पूर्ण संख्या में मामूली वृद्धि होगी। (इस के लिये निचे देखो)। इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में अगले भाग में बताया गया है।

तालिका 5: - स्व-नियोजित, नियमित या अनियमित श्रमिक

विवरण :	2017-18 का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण% 2020 तक लागू			2030-31 के लिए लक्ष्य और अनुमान		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
स्व-रोज़गार	57.8%	38.3%	26.6%	60.0%	40.0%	53.6%
नियमित वेतन / वेतनभोगी कर्मचारी	13.3%	47.0%	67.2%	15.0%	48.0%	25.5%
अनौपचारिक श्रमिक	28.9%	14.7%	6.2%	25.0%	12.0%	20.9%
श्रमिकों की कुल संख्या करोड़ में	33.90	13.24	47.14	40.46	18.85	59.31
स्व- नियोजित श्रमिक करोड़ में	19.60	5.07	12.54	2.43	7.54	31.82
नियमित वेतन / वेतनभोगी करोड़ में	4.50	6.22	31.68	6.07	9.05	15.12
अनौपचारिक श्रमिक करोड़ में	9.80	1.95	2.92	10.12	22.6	12.38
2030 तक स्व-नियोजित होने वाले श्रमिकों की बढ़ोतरी करोड़ में				4.68	2.47	7.15
2030 तक नियमित श्रमिकों की बढ़ोतरी करोड़ में				1.56	2.83	4.39
2030 तक अनियमित श्रमिकों की बढ़ोतरी करोड़ में				0.32	0.32	0.63

स्रोत : 2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) डेटा का उपयोग करते हुए, 2030 के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों पर आधारित लेखक की गणना

3.2.5 कौशल स्तर द्वारा रोज़गार

कौशल स्तर 2, और 3 सामान्य श्रमिकों के लिये और स्तर 4 पेशेवर श्रमिकों के लिए नौकरियों में अधिक वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आने वाले दशक में मध्यम-आय वाले श्रमिकों के लिये परिवर्तन के समय की स्थिति बना रही है। इसके परिणामस्वरूप हमने 2020 तक इन तीन स्तरों के लिए कुछ लक्ष्य सुझाए हैं। इसके विपरीत भी हम स्तर 1 के श्रमिकों की हिस्सेदारी में गिरावट की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास केवल मैनुअल और नियमित कौशल है, विशेष रूप से क्योंकि इन नौकरियों के स्वचालन और बनावटी ज्ञान के कारण समाप्त होने की संभावना है। (नीचे तालिका में देखें) कौशल स्तर 1 के श्रमिकों को 58.4 करोड़ से कम करने का प्रस्ताव है और स्नातक स्तर, पर ज्यादातर कौशल स्तर 2 के श्रमिकों की संख्या 2030 तक 9.19 करोड़ तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कौशल स्तर 3 और स्तर 4 के श्रमिकों की संख्या क्रमशः 6.68 करोड़ और 2.14 करोड़ तक बढ़ाने की आवश्यकता है। कुशल श्रमिकों की संख्या में इस दशक के लिए 18.0 करोड़ की वृद्धि करना राष्ट्रीय कौशल का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में अगले भाग में बताया गया है।

तालिका 6: कौशल स्तर द्वारा लक्षित रोज़गार वृद्धि

विवरण:	2017-18 तक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण:% 2020 लागू किया	2030-31 के लिए लक्ष्य और अनुमान	2021-30 में बढ़ोतरी करोड़ में
कौशल स्तर 1 के श्रमिकों का प्रतिशत	30.0%	14.0%	
कौशल स्तर 2 के श्रमिकों का प्रतिशत	56.0%	60.0%	
कौशल स्तर 3 के श्रमिकों का प्रतिशत	11.0%	20.0%	
कौशल स्तर 4 के श्रमिकों का प्रतिशत	3.0%	6.0%	
श्रमिकों की कुल संख्या	47.14	59.31	
कौशल स्तर 1 के श्रमिक	14.14	8.30	-5.84
कौशल स्तर 2 के	26.40	35.59	9.19
कौशल स्तर 3 के श्रमिक	5.19	11.86	6.68
कौशल स्तर 4 के श्रमिक	1.41	3.56	2.14

स्रोत : 2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) डेटा का उपयोग करते हुए, 2030 के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों पर आधारित लेखक की गणना

3.3 रोज़गार के अवसरों का ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों में बढ़ाना

हमें न केवल 12 करोड़ से अधिक आजीविका पैदा करने की एक नई योजना बनानी होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा, कि ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों और जिला मुख्यालय स्तर नौकरियों में वृद्धि महानगरों की तुलना में अधिक हो। COVID लॉकडाउन के दौरान COVID प्रवासियों से सबक सीखते हुए, हम एक आकांक्षात्मक लक्ष्य की अनुशंसा करते हैं, ताकि 2030 तक, कार्यबल का 25 प्रतिशत छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों में उपलब्ध हो, जोकि अभी केवल 14.8 प्रतिशत है। विस्तृत संख्या नीचे दी गई है। हमें छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों में श्रमिकों की संख्या 7.9 करोड़ बढ़ानी चाहिये, इसलिये हमें आजीविका के स्थनीय वितरण में सुधार करने के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए रणनीति बनाने का काम हमने अगले भाग में किया है।

तालिका 7 : ग्रामीण-शहरी लगातार क्रम में स्थान और लक्ष्य के आधार पर रोज़गार वृद्धि

विवरण	2017-18 की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) % 2020 तक लागू		वर्ष 2030-31 तक के लिए अनुमान		2020-31 तक में वृद्धि
	% में	करोड़ में	2030-31	करोड़ में	करोड़ में
ग्रामीण श्रमिक	71.9%	33.90	60%	35.59	16.8
छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों में श्रमिक	14.8%	6.95	25%	14.83	78.7
महानगरों और बड़े शहरों में काम करने वाले श्रमिक	13.3%	6.28	15%	8.90	26.1
श्रमिकों की कुल संख्या करोड़ में	100.0%	47.14	100%	59.311	121.7

स्रोत : 2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हुए, 2030 के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों पर आधारित लेखक की गणना

3.3.1 रोज़गार वृद्धि में अंतर-राज्यीय असमानताओं को संबोधित करना

हमने पहले खंड 1.3 में रोज़गार वृद्धि में अंतर-राज्य असमानताओं के बारे में भी इंगित किया था। हमें इस लगातार पैटर्न को समाप्त करना होगा। हम इसके लिए किसी भी मात्रात्मक लक्ष्य को निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए सरकारी धन के अंतर-राज्य संसाधन आवंटन में बहुत अधिक विलंब होता है।

इसे मान्यता देने के लिये सरकार ने 2010-11 में “पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना” (BGREI) कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए सात राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और असम शामिल थे। इसे बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का हिस्सा बनाया गया।

एक अन्य तरीका जिसके द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित किया जा सकता है, और वह है, अवसंरचना में निवेश। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने 1995 में स्थापित रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIDF) के तहत मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों, पुलों और सिंचाई पर कुल 378,384 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अगला कदम सूक्ष्म उद्यमों और उसके लिए निवेश करना है। यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY बैंक ऋण के माध्यम से राज्यों में प्रदान किया जा सकता है।

इसके अलावा छोटे उद्यमों के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे सात पिछड़े राज्यों में उद्यमों को पूँजी प्रदान करने के लिए समृद्ध निधि की स्थापना की। एकीकृत पर्वतीय पहल द्वारा आयोजित सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन के दौरान पहाड़ी राज्यों के लिए लेखक द्वारा एक समान निधि का सुझाव दिया गया था।

3.4 रोज़गार बढ़ाने के लिए उच्च वृद्धि उप- क्षेत्रों को लक्षित करना



क्षेत्रीय रूप से हमें यह सुनिश्चित करना होगा, कि प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी और खनन क्षेत्र में रोज़गार की वृद्धि दर कम है, जबकि यह विनिर्माण और निर्माण जैसे क्षेत्र में अधिक है, और उन सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं में अधिक है, जिनमें अनौपचारिक श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है।

रोज़गार में उपकरण संबन्धित ग्रोथ के लक्ष्य नीचे दिखाए गए हैं, और जबकि उपकरण संबन्धित एक्सपर्ट्स अधिक सटीक लक्ष्य बना सकते हैं, यहाँ पर हमने माँग और निवेश में अधिक वृद्धि के दृष्टिकोण से व्यापक संभवता के लिए इनकी जाँच की है।

तालिका 8: आर्थिक उप-क्षेत्रों अनुसार लक्षित रोज़गार वृद्धि

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी उप-क्षेत्र का विवरण	2020-21 में कुल श्रमिक करोड़ में	2020-21 के % के रूप में इस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में श्रमिक	2021-30 में ग्रामीण श्रमिकों का लक्ष्य विकास दर % में सालाना	2021-30 में शहरी श्रमिकों का लक्ष्य विकास दर % में सालाना	2030-31 ग्रामीण श्रमिक करोड़ में	2030-31 में शहरी श्रमिकों की संख्या करोड़ में	2030-31 में कुल श्रमिक करोड़ में	2030-31 में कितने % श्रमिक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अनुसार
फसल की खेती	18.49	39.2%	1.0	1.0	19.86	0.57	20.42	34.4%
पशुपालन	2.51	5.3%	3.0	1.0	3.10	0.223	33.22	5.6%
वानिकी और मछली पालन	0.175	0.4%	3.0	1.0	0.177	0.048	0.225	0.4%
खनन और उत्खनन	0.195	0.4%	3.0	2.0	0.176	0.078	0.254	0.4%
विनिर्माण	5.205	11.0%	3.0	4.0	3.312	4.057	7.369	12.4%
निर्माण	5.501	11.7%	3.0	4.0	5.547	2.033	7.580	12.8%
बिजली, और गैस	0.158	0.3%	1.0	3.0	0.084	0.110	0.194	0.3%
जल आपूर्ति, और सीवरेज	0.114	0.2%	1.0	3.0	0.047	0.096	0.143	0.2%
थोक और खुदरा व्यापार, मोटर वाहन मरम्मत	4.833	10.3%	2.0	4.0	2.74	3.83	6.57	11.1%
परिवहन और भंडारण	2.357	5.0%	2.0	4.0	1.54	1.62	3.16	5.3%
शिक्षा	1.793	3.8%	2.0	4.0	1.20	1.20	2.40	4.0%
अन्य सेवाएं	0.896	1.9%	2.0	4.0	0.52	0.70	1.22	2.1%
आवास और खाद्य सेवाएँ	0.875	1.9%	3.0	4.0	0.54	0.70	1.24	2.1%
लोक प्रशासन, और रक्षा	0.766	1.6%	2.0	2.0	0.426	0.508	0.934	1.6%

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी उप-क्षेत्र का विवरण	2020-21 में कुल श्रमिक करोड़ में	2020-21 के % के रूप में इस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में श्रमिक	2021-30 में ग्रामीण श्रमिकों का लक्ष्य विकास दर % में सालाना	2021-30 में शहरी श्रमिकों का लक्ष्य विकास दर % में सालाना	2030-31 ग्रामीण श्रमिक करोड़ में	2030-31 में शहरी श्रमिकों की संख्या करोड़ में	2030-31 में कुल श्रमिक करोड़ में	2030-31 में कितने % श्रमिक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अनुसार
स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य	0.579	1.2%	3.0	3.0	0.289	0.489	0.778	1.3%
प्रशासनिक	0.574	1.2%	2.0	3.0	0.266	0.478	0.744	1.3%
घरेलू सेवाएं	0.506	1.1%	1.0	3.0	0.168	0.476	0.643	1.1%
वित्तीय सेवाएँ	0.507	1.1%	2.0	3.0	0.185	0.478	0.663	1.1%
सूचना और संचार	0.480	1.0%	2.0	3.0	0.094	0.542	0.636	1.1%
व्यवसायी सेवाएँ	0.399	0.8%	2.0	3.0	0.111	0.415	0.525	0.9%
मनोरंजन	0.130	0.3%	2.0	3.0	0.064	0.103	0.168	0.3%
रियल एस्टेट सर्विसेज	0.097	0.2%	2.0	3.0	0.028	0.100	0.128	0.2%
कुल	47.14	100.0%	NA	NA	40.46	18.85	59.31	100.0%

स्रोत : 2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हुए, 2030 के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों पर आधारित लेखक की गणना



अनुमानित 12 करोड़ नई आजीविकाओं में से लगभग 11 करोड़ इन दस उप-क्षेत्रों से आएगी:

	तीव्र विकास आर्थिक उपक्षेत्र -	इस उप-क्षेत्र में 2021-31 में श्रमिकों की संख्या में अनुमानित वृद्धि (करोड़)
1	विनिर्माण	2.164
2	निर्माण	2.079
3	फसल की खेती (नीचे टिप्पणी देखें)	1.934
4	संपूर्ण बिक्री और खुदरा व्यापार, मोटर वाहन मरम्मत	1.734
5	पशुपालन	0.814
6	परिवहन और भंडारण	0.802
7	शिक्षा	0.605
8	आवास और खाद्य सेवाएँ	0.365
9	अन्य सेवाएँ	0.320
10	स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य	0.199

एक सवाल यह भी उठता है, कि चूँकि फसल की खेती का क्षेत्र पहले से ही असामान्य है, तो यह 1.9 करोड़ अन्य श्रमिकों को कैसे अवशोषित कर सकता है? विवरण बाद में दिया गया है, लेकिन मुख्य बात यह है, कि पहले के कुछ वर्षों में अतिरिक्त श्रमिक मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों - जल, जंगल, जमीन का विकास कर रहे हैं, जो कृषि के लिए उत्पादक आधार हैं। उसके बाद, जल जंगल, जमीन की बढ़ी हुई उत्पादकता अतिरिक्त श्रमिकों को आजीविका देने में सक्षम होगी।

4 सबके लिए सतत रोज़गार - चार प्रमुख रणनीतियां

इस खंड में, हम आने वाले दशक में भारत में आजीविका के लिये चुनौती को संबोधित करने के लिए चार प्रमुख रणनीतियों का सुझाव देते हैं, जो बड़ी संख्या में नए रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। ये

भारत की हरियाली, भारत के जल, जंगल, जमीं को पुनर्जीवित करके : अर्थशास्त्र और पर्यावरण दोनों के संदर्भ में कृषि को एक स्थायी मॉडल में बदलना; विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना और अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करना।

विकास क्षेत्रों में उच्च में नए कुशल नौकरियों के अवसर : कृषि सेवा, कृषि-प्रसंस्करण, निर्माण, एवं छोटे उद्यमों के क्षेत्र में विनिर्माण के साथ-साथ बड़े उद्योगों और अनुमानित सेवाओं में भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा।

डिजिटल सेवाएँ, छोटे शहरों से निकल कर महानगरों में और उनसे भी आगे और डिजिटल रूप से कुशल श्रमिकों के एक समूह द्वारा पेश की जा रही हैं : विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं और विकलांगों द्वारा।

समर्थ जिले - छोटे जिलों और रोज़गार सृजन के केंद्र के रूप में शिल्प समूहों के साथ सक्षम जिले : ताकि महानगरों के बजाय लोग छोटे शहरों में आने के बाद भी गैर-कृषि क्षेत्र की नौकरियाँ उन्हें अपने गाँव में आजीविका कमा सकें।

4.1 देश को पुनः हरियाली पूर्वक करने से सतत आजीविका का संवर्धन होगा



भारत के जल, जंगल, और जमीन को पुनर्जीवित करने से बड़ी संख्या में रोज़गार उत्पन्न हो सकते हैं; अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों की दृष्टि से कृषि को एक स्थायी मॉडल में बदलना और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, और अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण से।

आइए पहले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को देखें। जिनमें कृषि एक सबसे बड़ा नियोक्ता है, लेकिन कम और अनिश्चित आय के कारण लाखों श्रमिक और किसानों से इससे किनारा कर लिया है। फिर भी यदि कृषि, जल, भूजल, और भूजल जलभृत, खेती योग्य भूमि, जिनकी मिट्टी अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों, ज्यादा सिंचाई या मिट्टी के कटाव के कारण खराब हो गई है आदि, सहित यदि प्राकृतिक संसाधनों के पुनः जीवन के लिए इनमें निवेश किया जाता है, तो इस पलायन के तूफान को रोकना संभव हो सकता है।

4.1.1 जल, जंगल, और जमीन, जीवन और आजीविका के उत्थान का सुरक्षित आधार हैं

10 करोड़ हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि को पुनर्जनन की आवश्यकता है, 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि में व्यापक मिट्टी और जल संरक्षण की आवश्यकता है, 0.75 करोड़ हेक्टेयर झीलों, तालाबों और जलाशयों / टैंकों की मरम्मत की आवश्यकता है, और भूजल पुनर्भरण के लिए आवश्यक उपायों को करने की आवश्यकता है, इन सभी कार्यों का पुनर्जनन कराने में लाखों लोगों को रोजगार मिलना संभव हो सकता है।

हालाँकि BAIF (नीचे आयत 5 देखें) जैसे गैर सरकारी संगठनों ने यह समझाने (दिखाने) की कोशिश की है, कि बेकार पड़े हुए प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जा सकता है, और कैसे इसके लाभ-लागत अनुपात को साबित किया जा सकता है, सरकार को इसके लिए एक बड़ा हिस्सा निवेश करना होगा, क्योंकि ये सामान्य संपत्ति संसाधन हैं। इस प्रकार जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, वंचित वनभूमि का वनीकरण, बंजर भूमि का विकास, मिट्टी का नवीनीकरण, चारागाह और चराई भूमि पुनर्जीवन के लिए आवंटन, सभी में सार्वजनिक धन का उपयोग करने की आवश्यकता है।

आयत 5: भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन द्वारा प्राकृतिक संसाधन पुनर्निर्माण

भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन (BAIF) और पुणे की DHURVA परियोजना। गुजरात - मध्य प्रदेश की सीमा पर आदिवासी जिले धरमपुर और वलसाड ऐसे जिले थे, जिनमें कभी घने जंगल पाये जाते थे। परन्तु 1980 के दशक के मध्य तक, इन जंगलों को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया था, जिस कारण हर साल कुछ महीनों के लिए आदिवासियों को आजीविका कमाने के लिये सूरत जैसे पश्चिमी जिलों में पलायन करना पड़ता था। बीएआईएफ ने छोटे-छोटे बगीचे बनाने की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिनको कि बाड़ी कहा जाता है। आदिवासियों को प्रशिक्षित किया गया, और उन्हें अपनी एक एकड़ भूमि में आम और काजू उगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरह करीब दस वर्षों में, BAIF- और DHURVA ने मिलकर लगभग 30,000 एकड़ जंगल में बगीचे लगाने को बढ़ावा दिया। जब तक पेड़ छोटे थे, तब तक आदिवासियों को इन बगीचों में अनाज, चारा और सब्जी की फसल उगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जिसके कारण लगभग 10 वर्षों में, आम और काजू के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण स्तर पर संग्रह और प्रसंस्करण इकाइयों और बहुत सारी सब्जी और डेयरी उत्पादन और बिक्री के साथ क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल गई है। और इससे सूरत में काम की तलाश के लिये जाने वाले प्रवासियों का पलायन पूरी तरह से रुक गया। बीएआईएफ ने सात राज्यों में 1,50,000 से अधिक किसानों के साथ इस बगीचा मॉडल की प्रतिकृति बनाई। और बाद में नाबार्ड ने भी 2302 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5,52,755 आदिवासी परिवारों की सहायता की, इसमें ज्यादातर अन्नदान, बाड़ी (घर के बगीचे) परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2020 तक दिया गया था।

सितम्बर 2020 में, नाबार्ड ने प्राकृतिक संसाधनों के उत्थान के लिए परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 15000 करोड़ रुपये की ग्रामीण अवसंरचना सहायता राशि की घोषणा की है। यह कोष इस कार्य के लिए राज्यों को उ1पलब्ध संसाधनों का पूरक होगा।

यद्यपि भूमि, जल और वन संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जैसी कई अन्य योजनाएँ हैं, फिर भी प्राकृतिक रूप से पतित संसाधनों को पुनः उत्पन्न करने के लिए एक नए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वर्तमान में MGNREGS सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जो इस कार्यक्रम के तहत पंजीकृत मजदूरों को 100 दिनों तक काम (मजदूरी अर्जित) करने के अवसर प्रदान करती है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है, कि रोज़गार के औसत दिन प्रति परिवार 50 दिनों से भी कम है। COVID महामारी के बाद, MNREGS के काम की माँग बढ़ी है हालाँकि सरकार ने काम में वृद्धि की माँग में धन और कार्यों की आपूर्ति को दूर किया है।

प्राकृतिक संसाधनों के उत्थान के लिए MGNREGS आवंटन का उपयोग करके इनमें से बहुत कुछ किया जा सकता है, और क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) से धन के साथ पूरक किया जा सकता है। जिसमें 2018 तक 54,685 करोड़ रुपये और 2020 के अंत तक 43,271 करोड़ रुपये का प्रावधान डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन (DMF) के द्वारा किया गया था।

ग्रीन इंडिया मिशन (GIM), नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है। इसे 2014 में NAPCC में शामिल किया गया था। इस योजना को 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह उद्देश्य-अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन द्वारा भारत के कम होते वन आवरण को बहाल करना और जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देना है। इस मिशन के तहत वन और भूमि को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य रखा गया है।

मिशन का उद्देश्य	लक्ष्य
वन / वृक्षों का आवरण बढ़ाएँ: पर्यावरण की बहाली, वनीकरण, झाड़ी, खारे पानी या अर्ध-खारे पानी में पाए जाने वाले वृक्ष, ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र 1.8 mha वन और वृक्ष आवरण के तहत शहरी / पेरी-शहरी भूमि लाना : 0.20 mha कृषि- वानिकी / सामाजिक वानिकी : 3.00 mha	5 mha
वन / वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार : वन आवरण और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार : मध्यम घने जंगल : 1.5 mha खुला नीचा जंगल : 3.0 mha नीचा घास का मैदान : 0.4 mha गीली जमीन : 0.1 mha	5 mha
वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि :	3 करोड़ परिवार

ग्रीन इंडिया मिशन एनएपीसीसी के अन्य उप मिशनों और संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और मिशनों के साथ अभिसरण करना चाहता है। भारत सरकार ने हाल ही में इस मिशन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के साथ परिवर्तित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 10 माह के लिये वन भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिये महत्वाकांक्षी लक्ष्य के मुकाबले, जीआईएम की प्रगति अब तक बहुत निराशाजनक रही है। मिशन के लिए वित्तीय संवितरण 2015-16 में शुरू हुआ और 2017-18 में केवल रु 144 करोड़ खर्च हुए थे। 5 माह के वन भूमि की गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य के खिलाफ, मिशन 0.043 हजारों हेक्टेयर में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है।

COVID महामारी के दौरान, आजीविका की तलाश में प्राकृतिक संसाधनों के उत्थान पर आधारित आजीविका बनाने के प्रयासों के कई सूक्ष्म उदाहरण सामने आए। कुछ वापसी करने वाले प्रवासियों, जब वे अपने पैतृक गाँवों में वापस आए, तो अपने गाँव के प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीवन यापन करने की आशा के साथ काम करना शुरू कर दिया। (आयत 6 देखें)

आयत 6: अपने गाँव में लौटे प्रवासी मज़दूरों का अपनी ज़मीन और जल संसाधनों को फिर से वापस जुटाना

30 जुलाई 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने एक वक्तव्य में बताया : कि “कंधमाल जिले के पहाड़ी इलाकों में ऊँची पहाड़ियों और घने जंगलों के कारण बहुत कम सिंचाई हो पाती है, हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा कि प्रवासियों ने नौकरियों के लिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर पलायन किया। जिले के 15,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक जो अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में विचार से परेशान थे। एक स्थानीय एनजीओ “कंधमाल” जिला साबुजा, में बैद्य संगठन ने प्रवासियों को अपने खेतों में सिंचाई करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया.. महामारी के प्रकोप के कारण हुई तबाही के मद्देनजर, 300 से अधिक प्रवासियों ने उन सैकड़ों किसानों की जयकार की, और पहाड़ी इलाकों में पके हुए खेत तक पानी पहुँचाने के लिए लगभग 8 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई की।”

2018 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के एक अनुमान के मुताबिक, भारत में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से 2014-15 में देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5 प्रतिशत की लागत में गिरावट आई। 2018 में टीईआरआई के अध्ययन में पाँच प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए तुच्छ भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए जल का क्षरण, वायु का क्षरण, वनों का क्षरण, जल भराव और लवणता आदि, के आवश्यक निवेश का अनुमान है। (2014-15) में सर्विसेस अकाउंटिंग कानूनों अहमदाबाद के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 9.453 करोड़ हेक्टेयर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए लगभग 3 ट्रिलियन (लाख करोड़) रुपये निवेश की आवश्यकता है। तब से लागत में वृद्धि को देखते हुए, इस तुच्छ भूमि संसाधनों के उत्थान के लिए 4 ट्रिलियन (लाख करोड़) रुपये या 2019-20 के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है।

जल और वन संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए समान मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अगले कुछ वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ, भारत अपने जल, जंगल यामीन को फिर से विकसित कर सकता है। इसका रोजगार पर प्रभाव चार साल तक प्रत्येक वर्ष लगभग 5 करोड़ लोगों के लिए 300 दिनों तक

काम का उत्पादन होगा, इसके अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार के बाद से MGNREGS के धन का 40 प्रतिशत सामग्री और प्रशासन पर खर्च किया जाता है। परिणामस्वरूप, लगभग एक करोड़ लोग अतिरिक्त रूप से कृषि, डेयरी, वानिकी, मत्स्य (मछली पालन) इत्यादि में लगे रह सकते हैं।

4.1.2 किसान के लिए कृषि और पर्यावरण को स्थायी और लाभदायक बनाना

तुच्छ प्राकृतिक संसाधनों - पानी, जंगल और भूमि (मिट्टी) के उत्थान पर काम करना, कृषि में जीवन शक्ति वापस लाने का एक मुख्य आधार है। किसानों और कृषि श्रमिकों के लिये कृषि को अधिक उपजाऊ और टिकाऊ बनाने के लिए कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे, पर्यावरण के दृष्टिकोण, से और साथ ही कृषि आजीविका के वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से। यह देखते हुए कि भारत में कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, 14,145 करोड़ हेक्टेयर परिचालन जोत वाली भूमि है, जिसमें 14.1 करोड़ हेक्टेयर के शुद्ध बुवाई वाला क्षेत्र है। हम देख सकते हैं कि औसत जोत का आकार मुश्किल से 0.96 हेक्टेयर (2.4 एकड़) था।

जैसा कि 2012-13 में 9.0 करोड़ किसान परिवारों का अनुमान था, हम देख सकते हैं कि औसतन एक किसान परिवार के पास बहुत कम जमीन थी और यहाँ तक कि कई ऑपरेशनल जोत में भी थे, ज्यादातर किसान परिवार के पास जमीन का एक बहुत छोटा हिस्सा, कुछ इतना छोटा कि एक जोड़ी बैल नहीं चल सकते।

हमें जो आवश्यकता है जिसमें एकत्रिकरण, उत्पादकता वृद्धि, लागत बचत, जोखिम शमन, उत्पादन का विविधीकरण, और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना, जहाँ किसानों को उपभोक्ता तक संपूर्ण मूल्य शृंखला में जोड़े गए मूल्य का हिस्सा मिले। इस प्रकार सरकार को व्यक्तिगत शीर्षकों के अलगाव के बिना खेत जोतों के समेकन (एकत्रिकरण) को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है। मुल्लाथिनेई इको फार्म प्रोड्यूसर कंपनी (www.mullaithinnececofarm.com) द्वारा द हिंदू में प्रकाशित एक विज्ञापन के अनुसार 3,50,000 रुपये की एक एकड़ जमीन की वित्तीय भागीदारी की माँग करते हुए, तमिलनाडु में पहले से ही इस तरह का उदाहरण है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत सारी कृषि भूमि गैर-किसानों के पास है, जो शहरों में रहते हैं, और उनके पास इस तरह की ज़मीन और पूँजी है, लेकिन वे न तो श्रम कर सकते हैं और न ही कृषि के बारे में कुछ जान सकते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण निवासियों के पास कृषि का श्रम और ज्ञान है। परन्तु उनके पास भूमि नहीं है इस प्रकार यह दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है।

उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, चकबंदी के अलावा, हमें मिट्टी और जल संरक्षण की आवश्यकता है, और कई मामलों में उत्थान की। (MNREGS) फंड का उपयोग निजी भूमि पर मिट्टी और जल संरक्षण कार्य करने के लिए किया जा सकता है, ताकि एक वाटरशेड का पूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। यदि हम जलवायु लचीला किस्मों, और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं, तो नई सुधारों को अपनाने के लिए बहुत अच्छी क्षेत्रीय विस्तार सेवाओं के साथ मिलकर उपज में सुधार और स्थायीकरण में मदद मिलेगी। चूँकि भविष्य में मुख्य फसलों में सब्जियों, फलों, फूलों, जड़ी-बूटियों, सुगंधित और औषधीय पौधों जैसी फसलों की पैदावार नहीं हो सकती है। विशेषज्ञों ने पंजाब और हरियाणा के बड़े किसानों के लिए इस रणनीति के बारे में बात की है, जो धान और गेहूँ चक्र में फंस गए हैं, यह कई अन्य राज्यों में छोटे किसानों के लिए भी है। (सिराज हुसैन 2020)। अन्य कृषि विशेषज्ञों ने प्रस्ताव दिया है, कि रासायनिक खादों को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। (नीचे आयत 7 देखें)

आयत 7: आंध्र और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

जीरो-बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF), श्री सुभाष पालेकर, महाराष्ट्र के विदर्भ में एक कृषि वैज्ञानिक द्वारा प्रचारित उदाहरण, उच्च लागत वाले रासायनिक मुक्त आधारित कृषि के वर्तमान प्रारूप के लिए एक समग्र विकल्प है। यह जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं को दूर करने में बहुत प्रभावी है।

आंध्र प्रदेश में, जीरो-बजट प्राकृतिक खेती (APZBNF) प्रोग्राम को 2015-16 में रायथु साधिकारा संस्था (RySS बिना लाभ की संस्था) के माध्यम से लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम में किसानों के कल्याण, और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई उद्देश्य हैं। पर्यावरण के संरक्षण में 500,000 से अधिक किसानों को शामिल किया गया है। <http://apzbnf.in/> पर और देखें

इसकी सफलता से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2018 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (PK3Y) शुरू की। यह शेड के निर्माण, बुनियादी उपकरण, और पशुधन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) केंद्र द्वारा 90,000 से अधिक किसानों ने कृषि विश्वविद्यालयों से प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। परिणामस्वरूप, राज्य में 5000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र को रासायनिक मुक्त कृषि में बदल दिया गया है।

रेशे से परे भोजन में विविधीकरण के साथ संबद्ध क्षेत्रों में, विशेष रूप से डेयरी फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म, सुअर पालन, भेड़ और बकरी पालन, बत्ख पालन, मत्स्य और वानर (मधुमक्खी पालन) में काफी आजीविकाएँ संभव हैं। (नीचे आयत 8 देखें)। यह पहले से ही डेयरी क्षेत्र में हुआ है। भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले 20 वर्षों में 4.5 प्रतिशत के सीएजीआर (सालाना चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की दर) से बढ़ रहा है, जिससे भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। 2018-19 में भारत का दुग्ध उत्पादन 18.8 करोड़ मीट्रिक टन था, जो विश्व के दूध उत्पादन का लगभग 21 प्रतिशत था। डेयरी में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये या कृषि जीडीपी का 28 प्रतिशत हिस्सा था। दुग्ध उत्पादन का मूल्य सभी दालों और अनाज के कुल मूल्य से अधिक था -

आयत 8: लघु उत्पादकों का समर्थन करने के लिए कृषि विविधीकरण में सरकार के प्रयास

1970 में डॉ कुरियन के नेतृत्व में राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड द्वारा मुफ्त दूध पाउडर और मक्खन दूध के रचनात्मक उपयोग के साथ डेयरी में बड़े पैमाने पर सहायता के रूप में प्राप्त किया गया था, पोल्ट्री क्षेत्र में कई निजी उद्यमों द्वारा एक अलग तरीके से किया गया था। इनमें डॉ बीवी राव और सुगुना फूड्स की अगुवाई वाले वेंकटेश्वर हैचरीज ग्रुप में बी सुंदरराजन और उनके भाई जीबी सुंदरराजन शामिल थे। 2020 में सुगुना का टर्नओवर 9000 करोड़ रुपये से अधिक था। गैर सरकारी संस्था प्रदान ने मध्य भारत के सबसे बड़े मुर्गी पालन उत्पादकों के समूह को बढ़ावा दिया, जिसे अब नेशनल स्मॉल होल्डर पोल्ट्री डेवलपमेंट ट्रस्ट (NSPDT) का समर्थन प्राप्त है, जो ग्रामीण भारत में गरीब महिलाओं को सफल मुर्गी पालन शुरू करने और चलाने में सहयोग करता है। 25 से अधिक ऐसे मुर्गी पालक सहकारी संस्थाओं ने मिलकर 500 करोड़ रुपये का कारोबार किया। बकरी पालन में, बकरी ट्रस्ट छोटे बकरी पालनकर्ताओं के लिए उत्पादकता बढ़ाने और आय में वृद्धि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

निर्माण करके जोखिम पूर्ण-खेती में निवेश करना है। (लगभग 7 मीटर x 7 मीटर x 2 मीटर गहरे खेतों तालाबों में किसानों को लंबे समय तक सूखे के खतरे से बचाएंगे) ऐसे खेत तालाब की औसत लागत 25,000 रुपये है। इस प्रकार हम भारत के अधिकांश 6 करोड़ फार्म जो कि वर्षा वाले क्षेत्रों में हैं, को 1,50,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है।

जैसा कि पहले सुझाव दिया गया था, यह MGNREGS फंड का उपयोग करके किया जा सकता है, बशर्ते MGNREGS को आवंटन बढ़ाया जाए, जैसा कि 2020-21 में महामारी के बाद किया गया था। उस गति को अगले तीन से चार वर्षों तक बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा, खेत-विशिष्ट, नई पीढ़ी के समाधान जैसे कि मौसम जोखिम प्रबंधन सेवाओं द्वारा पेश किए गए SecuFarm (एक प्रकार का फ़ल) का उपयोग शमन और बीमा के संयोजन का उपयोग करके जोखिम के कवर को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

फिर भी, उत्पादकता बढ़ाने, लागत बचत, जोखिम को कम करने या उत्पादन विविधीकरण की कोई भी राशि उन्हें कृषि वस्तु मूल्य शृंखला के लाभ-साझाकरण भागीदार बनाने की तुलना में किसानों की आय पर प्रभाव से मेल नहीं खा सकती है। यह एएमयूएल (अमूल) के पैटर्न सहकारी समितियों द्वारा डेयरी क्षेत्र में और महाराष्ट्र में गन्ना क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध रूप से किया गया है।

किसानों की निर्माता कंपनियों (FPCs) को स्थापित करने का सरकार का प्रयास जो कि कंपनी अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के अलावा कुछ भी नहीं है, उस दिशा में पहला कदम है। हालाँकि, चूँकि (एफपीसी) किसान शेयरधारकों से पूँजी जुटा सकते हैं, इसलिये ये स्थायी रूप से पूँजी के लिए विवश हैं। अब तक के 8000 विषम एफपीसी में से अधिकांश के पास इतनी पूँजी भी नहीं है, कि वे उपज के सामूहिक बाजार में शामिल हो सकें, केवल मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश करना छोड़ दें। एएमयूएल (अमूल) के मामले में, यह समस्या यूरोपीय संघ और अमेरिका से सहायता के रूप में प्राप्त मुफ्त दूध पाउडर की आय के सूक्ष्म उपयोग से दूर हो गई। गन्ना के मामले में, राजनीतिक नेताओं के एक समूह द्वारा जो मूल रूप से इसमें शामिल थे, और गन्ना सहकारी समिति के सदस्य बने रहे।

हालाँकि, खंड के बाद खंड में इसे दोहराया नहीं जा सकता। इसलिए, दीर्घकालिक समाधान कृषि पूँजी शृंखलाओं के लिए निजी पूँजी को आकर्षित करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को मूल्य शृंखलाओं से लाभ का उचित हिस्सा मिलता है। किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करते हुए, वर्तमान में घोषित कानून के प्रयासों के अनुसार निजी पूँजी के साथ राज्य की पूँजी को प्रतिस्थापित करना था। फिर भी, ये कानून कई ऐसे प्रावधान यह धारणा देते हैं, कि किसान पूँजीगत स्वामित्व वाली मूल्य शृंखलाओं के लिए प्राथमिक वस्तुओं के केवल अनुबंधित आपूर्तिकर्ता बन जाएंगे।

4.1.3 विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

ऊर्जा उत्पादन, विशेष रूप से सौर-ऊर्जा और बायोमास / बायोगैस आधारित एक नया अवसर है। भारत में प्राप्त सौर प्रसारण की औसत तीव्रता 200 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर है। 32.87 करोड़ हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र के साथ यह 65.74 करोड़ मेगावाट है। इसमें से आज की प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भले ही 1 प्रतिशत का उपयोग किया जा सकता है, यह 2019 में 360,000 मेगावाट स्थापित क्षमता का लगभग 1000 गुना होगा। इस अवसर का हिस्सा पहले से ही सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आयत 9 नीचे देखें।

आयत 9: दुनिया का पहला सहकारी सौर ऊर्जा

धुंडी सौर ऊर्जा उत्पादकों के सहकारी समिति की स्थापना गुजरात के खेड़ा जिले में, प्रोफेसर तुषार शाह के नेत्रत्व में आनंद में अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की भारतीय शाखा के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। छह किसानों ने सोलर पैनल लगाए थे, जिनकी कुल क्षमता 56.4 किलोवाट थी। किसान सदस्यों ने अपने सात एकड़ भूमि में पानी भरने के लिए कुल 40,000 इकाइयों का इस्तेमाल किया और शेष 45,000 इकाइयों को ग्रिड में शामिल किया, जिससे सौर ऊर्जा की बिक्री से 3 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ (परांजोथी टी और एच.के. मिश्रा, 2017) की रिपोर्ट पर आधारित।

अधिकांश राज्यों में ग्रिड को अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचने के लिए उपलब्ध प्रावधान के साथ, यह किसानों और अन्य लोगों के लिए एक आय पैदा करने वाला प्रस्ताव भी हो सकता है, जिन किसानों के पास अकूत भूमि है। जून 2020 में राजस्थान सरकार ने किसानों को ग्रिड में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और बेचने की अनुमति दी थी। किसानों के लिए उपलब्ध अन्य अक्षय ऊर्जा संसाधन के रूप में काऊडंग (गोबर) बेचना भी है। (नीचे आयत 10 देखें)

आयत 10: बायोगैस के उत्पादन के लिए काऊडंग (गोबर) बेचकर छोटे किसानों को सक्षम बनाना

2014 के ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) के एक अध्ययन में दावा किया गया था, कि भारत वर्तमान में 0.15-0.30 / रुपये प्रति किलोग्राम से 1.50-2.00 / रुपये प्रति किग्रा तक गोबर (गोबर) का मूल्य बढ़ाकर लाखों ग्रामीण रोजगार पैदा कर सकता है। इससे लाखों छोटे डेयरी किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है, जो वर्तमान में गोबर से बहुत कम प्राप्त करते हैं। (शाह, टी 2020)। की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2020 में खाद बनाने के लिए गोबर खरीदने की योजना (गोधन न्याय योजना) शुरू की थी। यह अपनी तरह की पहली योजना थी, जिसके तहत सरकार किसानों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है। गोबर का उपयोग बायोगैस उत्पादन के लिए किया जाता है और घोल का उपयोग खेत की खाद, या ग्रामीण स्तर के मवेशियों के आश्रय स्थलों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिनमें से छत्तीसगढ़ में पहले से ही 2000 से अधिक आश्रय स्थल हैं। भारत सरकार ने काफ़ी मात्रा में बेकार उत्पादक द्वारा प्रबंधित सामुदायिक पैमाने के बायोगैस संयंत्रों को 50, 75, और 100, प्रतिशत पूंजीगत लागत सब्सिडी प्रदान करने के लिए गोबर-धन की शुरुआत की। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), और ग्राम पंचायतों के सहयोग से।

4.1.4 पुनर्प्रसंस्करण रोजगार के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है

“शहरों में लोग सालाना 6.2 करोड़ टन कचरा पैदा करते हैं, और यह भविष्यवाणी की गई है, कि यह 2030 में 16.5 करोड़ टन तक पहुँच जाएगा। 4.3 करोड़ टन ठोस कचरा नगरपालिका सालाना एकत्र किया जाता है, जिसमें से 3.1 करोड़ टन लैंडफिल (गड़बड़े वाले स्थानों) साइटों में डंप कर दिया जाता है, और सिर्फ 1.19 करोड़ टन का ही उचित उपयोग किया जाता है।”

इंदौर जैसे कई शहरों, जिन्हें भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नंबर 1 स्थान दिया गया है, ने न केवल प्लास्टिक, बल्कि रबर, विभिन्न प्रकार के धातु, काँच और यहाँ तक कि निर्माण मलबे को भी इस तरह के कचरे से निपटने के लिए सुविधा प्रदान की है। अन्य शहरों ने ऊर्जा उत्पादन के लिए कुछ कचरे का उपयोग जलाशय के माध्यम से करना शुरू भी कर दिया है, और अन्य लोगों ने सड़क निर्माण आदि के लिए पुनर्प्रसंस्करण सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया है। नीचे दिए गए दो अध्ययन दिये गये हैं। कृपया (आयत 11 और आयत 12 देखें)।

आयत 11: आयातित प्लास्टिक कचरे के पुनर्प्रसंस्करण में आजीविका

धोराजी, गुजरात में करीब 400 इकाइयाँ पूरे भारत से एकत्र किए गए कचरे की छँटाई कर रही हैं। यहाँ हर दिन लगभग 10 से 12 ट्रक कचरे का लोड होते हैं। कचरे को एचडीपीई, (उच्च घनत्व पॉलिएथिलीन) एलडीपीई, (कम घनत्व पॉलिएथिलीन) पीवीसी, (उच्च शक्ति थर्मोप्लास्टिक सामग्री) एबीएस (एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) आदि के बंडलों में अलग किया जाता है। इसे नियंत्रित स्थितियों में गर्म किया जाता है ताकि इसको घुमावदार यर किसी भी स्थिति में उपयोग के लिए एक समान प्रक्रिया में तैयार किया जा सके। पुनर्प्रसंस्करण उत्पादों की कीमत आम तौर पर स्वाभाविक उत्पादों का आधा स्तर है। प्लास्टिक को मिलाने की तकनीक, क्योंकि हीटिंग और एक्सट्रूज़न के लिए भी मशीनरी पूरी तरह से स्वदेशी है। धोराजी की सफलता के पीछे भूमि और मानव संसाधनों के साथ पटेल समुदाय है। उनके पास कोई बाहरी समर्थन, सब्सिडी या ऋण नहीं है। वास्तव में, वे केवल विपरीत शुल्क संरचना के माध्यम से समस्याएँ प्राप्त करते हैं। वे उत्पादन की प्रसंस्करण लागत में केवल 15 रुपये प्रति किलोग्राम के शेयर से प्राप्त कागज के कम लाभ (मार्जिन) पर काम करते हैं। सामग्री और परिवहन लागत सहित कुल लागत लगभग 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। कंदला मुक्त व्यापार क्षेत्र में आयातित प्लास्टिक स्क्रेप एक महत्वपूर्ण कच्चा माल स्रोत है। (अरुण गोयल, दीक्षित, 2019)

चूँकि भारत में लगभग आधा ठोस कचरा जैव नष्ट होने योग्य है, इसलिए खाद का निर्माण एक अन्य प्रमुख अवसर है। नीचे दिए गए एक सामाजिक उद्यम का एक केस स्टडी है जो ठीक सात साल से अधिक समय से ऐसा कर रहे हैं।

आयत 12: बेंगलूर नगर-निगम में बेकार वस्तुओं के पुनर्प्रसंस्करण द्वारा आजीविका निर्माण

बेंगलूर शहर के नगर निगम और विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों ने जैविक खाद, पुनर्प्रसंस्करण प्लास्टिक और अक्रिय सामग्रियों में कचरे के संग्रह, पृथक्करण और वितरण के लिए टेरा फार्मा बायोटेक्नोलोजीज़ लिमिटेड को लगाया है। टेरा फार्मा प्रति दिन 1,500 टन MSW (मिश्रित ठोस अपशिष्ट) की क्षमता के साथ, भौतिक पुनर्प्राप्ति संयंत्रों का मालिक और संचालित करता है। यह उर्वरक कंपनियों और उनके नेटवर्क वितरकों के साथ उनकी खाद बनाने और बेचने के लिए भी साझेदारी करता है। लगभग 4 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के साथ, टेरा फार्मा ने 215 श्रमिकों को रोजगार दिया और 2015 में 22,000 टन खाद का उत्पादन किया। टेरा फार्मा की गतिविधियों ने बेंगलूर शहर के अपशिष्ट प्रबंधन की लागत को कम करने, अनुपचारित कचरे के मानव जोखिम को कम करने और रोजगार सृजन के माध्यम से स्थानीय समुदाय की आजीविका में योगदान करने में मदद की है।

4.2 तीव्र विकास आर्थिक उपक्षेत्रों में नए कौशल वाले रोज़गार अवसर



यदि हम श्रम (कार्य) के लिए सभी नए प्रवेशकों के रोज़गार में एक नीतिगत सफलता के उद्देश्य से कार्य कर हैं, तो हमें कृषि सेवाओं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिल्प और रचनात्मक उद्यमों, सूक्ष्म और लघु विनिर्माण और मरम्मत आदि उद्यमों में बड़ी संख्या में आजीविका के अवसर बनाने की पहल करने आवश्यकता है। आवास और छोटे बुनियादी ढाँचा निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और वितरण और समीपवर्ती सेवा क्षेत्र में ऐसा किया जा सकता है।

4.2.1 कृषि सेवाएँ

चूँकि कृषि केंद्रित, - उत्पादन, सब्सिडी पर निर्भर है, रासायनिक प्रखर मॉडल को 1960 के दशक में भोजन की कमी के दिनों में, माँग-आधारित, निजी निवेश वित्त पोषित, पर्यावरणीय रूप से स्थायी मॉडल के रूप में अपनाया गया था, इसलिए फसल की खेती में रोज़गार (नौकरियाँ) कम हो सकती हैं।

कृषि सेवाओं में भूमि सर्वेक्षण, और रिकॉर्ड रखरखाव से लेकर मिट्टी और जल परीक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार, आदि जैसे कई और नए रोज़गार पैदा होंगे। विभिन्न चयन और बीज खरीद में नई नौकरियाँ पैदा होंगी, उचित कृषि अभ्यास में किसानों का मार्गदर्शन करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए किसानों को लचीला अभ्यास के लिए तैयार करना, खाद, जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों की तैयारी और बिक्री माइक्रो-ड्रिप (सूक्ष्म बूँद) सिंचाई उपकरण, ग्रीनहाउस / पॉलीहाउस की स्थापना और रखरखाव में काफी मात्रा में रोज़गार उत्पन्न होंगे। फसल कटाई के बाद के चरण में, कृषि उपज के लिए छंटाई, ग्रेडिंग, सुखाने के स्थान, लेखांकन, गुणवत्ता मूल्यांकन, सहित खरीद संचालन, ट्रेसबिलिटी (खोज-बीन करना), कोल्ड स्टोरेज, और नियमित भंडारग्रह में कुशल रोज़गार पैदा होंगे।

सबसे अच्छी कीमत पर उपज बेचने के लिए व्यापारियों, ठेके पर खेती के समकक्षों, और कृषि- वैज्ञानिकों के साथ गोदाम, वित्त की व्यवस्था करने में अंतिम नहीं बल्कि कम से कम कुछ तो नौकरियाँ पैदा होंगी। किसान समूहों के मामलों के प्रबंधन के साथ-साथ हजारों सहकारी समितियों और 8000 किसानों के उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में कई नौकरियाँ पैदा होंगी जो कि पहले से ही हैं एवं इस क्षेत्र में 10,000 से अधिक नौकरियाँ और आ रही हैं ।

4.2.2 कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

गैर-कृषि क्षेत्र में, कृषि उत्पादक क्षेत्रों के आसपास कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में रोज़गार का सृजन किया जाना है। गायाँ और भैंसों को पालने के अलावा, डेयरी क्षेत्र में काफ़ी नौकरियाँ हैं। हर गांव में दूध की खरीद, और शहर में जाकर दूध बेचकर आने का काम करने वाले लोग हैं। और दुग्ध उत्पाद जैसे दही, छाछ, स्वादिष्ट दूध, बटर, घी, मिल्क पाउडर, पैकेज्ड लिक्विड मिल्क, चॉकलेट और चीज़ का उत्पादन करने वाली और डेयरी संयंत्रों और परिवहन वाहनों के संचालन और रखरखाव में भी काफ़ी नौकरियाँ हैं।

इसे अन्य क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। इन कृषि प्रसंस्करण इकाइयों का 100 प्रतिशत स्वामित्व किसानों की निर्माता कंपनियों द्वारा होना चाहिए, और पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। शुरुआत के वर्षों में, जैसा कि वे राष्ट्रव्यापी ब्रांड निर्माण और वितरण में निवेश करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिये वे कॉर्पोरेट्स के साथ मार्केटिंग टाई-अप कर सकते हैं (जैसा कि शुरुआती वर्षों में अमूल और वोल्टास ने किया था)। अंततः उन्हें पूर्ण मूल्य शृंखला का मालिक होना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे किसानों को हिस्सा मिलेगा।

4.2.3 छोटे शहरों में आवास और छोटे बुनियादी ढाँचों में निर्माण

निर्माण के क्षेत्र में, - आवास के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे में बड़ी संख्या में रोज़गार उत्पन्न होने संभव हैं। २ करोड़ से अधिक आवास इकाइयों की महत्वपूर्ण कमी, और मौजूदा आवास स्टॉक को अपग्रेड करने की आवश्यकता के साथ-साथ, बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से हाउसिंग फाइनेंस की उपलब्धता, के साथ, इस क्षेत्र को एक नीति बनाने की आवश्यकता है, न कि राजकोषीय बढ़ावा करने की। इसके अलावा, लगभग 1000 शहरों में बुनियादी ढाँचे को बनाने और सुधारने की आवश्यकता के साथ, बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए श्रम की भारी माँग होगी, जैसे कि सड़क, पुल और सार्वजनिक भवन, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पुलिस थाना, और अस्पताल आदि में असंख्य रोज़गार संभव हैं।

निर्माण के क्षेत्र में रोज़गार का 80 प्रतिशत से अधिक कार्यबल कार्य करता है, जबकि कुशल कर्मचारियों की संख्या 9 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, और शेष लिपिक, तकनीशियनों और इंजीनियरों जैसे कार्य वर्ग हैं। लेकिन निर्माण क्षेत्र में नौकरियाँ अकुशल से अर्ध-कुशल और फिर कुशल नौकरियों तक ले जा रही हैं। मचान निर्माताओं के रूप में, मोल्ड तैयार करने के लिए फॉर्म- वर्कर, कंक्रीट की शटरिंग, स्टील की छत, कंक्रीट के पिंजरो बनाना, बार बेंडर्स, मिक्स कंक्रीट तैयार करने के लिए कॉन्सर्ट, कंक्रीट स्लैब, बीम और कॉलम सेट करना और ईंटों, प्लास्टर्स को ठीक करना, चित्रकार, ब्लॉक परतों और पत्थर के राजमिस्त्री, भूस्खलन, फ़र्श और सरफेसिंग, छतों – छत की टाईल्स और बढ़ई और एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर-कंडीशनिंग) आदि श्रमिकों के रूप में ढेरों नौकरियाँ हैं।

भारत में दूसरे सबसे बड़े रोज़गार के क्षेत्र के रूप में, समस्या संख्या की नहीं है बल्कि कौशल की है। निर्माण उद्योग व्यवसाय, सरकार के बजाय नए निर्माण कौशल में लाखों श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए आगे आया है। उदाहरण के लिए, निर्माण क्षेत्र में प्रमुख कम्पनी, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) भारत भर में अपने निर्माण कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (सीएसटीआई) के माध्यम से उद्योग-संचालित प्रशिक्षण में लगे हुए हैं। कैटरपिलर पृथ्वी पर चलने वाले उपकरणों के ऑपरेटरों को प्रशिक्षित कर रहा है। एशियन पेंट्स चित्रकारों को प्रशिक्षित कर रहा है। यह आजीविका प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले श्रमिकों के साथ-साथ प्रशिक्षण देने वाली कंपनी के लिए एक जीत की स्थिति है।

4.2.4 अतिलघु उद्यम बनाम स्वरोज़गार

हमने शुरुआती खंड में उल्लेख किया है, कि भारत में कुछ क्षेत्रों में रोज़गार में वृद्धि हुई है, और कुछ क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान भी हुआ है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विनिर्माण क्षेत्र। PLFS (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार, केवल 12 प्रतिशत कार्य बल या 3.8 करोड़ श्रमिक विनिर्माण के क्षेत्र में लगे हुए थे। हमें 2030 तक इसे 6 करोड़ या कार्यबल के लगभग 13.5 प्रतिशत तक ले जाने के लिए 2.2 करोड़ श्रमिकों को रोज़गार देने की आवश्यकता है।

इन विनिर्माण नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा छोटे उद्यम क्षेत्र में होना चाहिए। जिसके लिये सरकार ने एक बूस्टर के रूप में पीएमएमवाई (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) का डिजाइन तैयार किया था। एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) क्षेत्र के सबसे निचले (जमीनी पायदान) छोर में स्वरोज़गार के लिए बूस्टर है, यही वजह है, कि सबसे छोटा, शिशुपाल 50,000 रुपये तक का ऋण देता है, 86.5 प्रतिशत आवेदकों के ऋणों की संख्या का 46.7 प्रतिशत तक राशि से देता है। शिशु ऋण की औसत ऋण राशि केवल 27143 रुपये थी, इसलिए इसमें अतिरिक्त आय सीमित है और अतिरिक्त रोज़गार भी थोड़ा कम था। PMMY (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) केवल 20.8 फीसदी ऋण महिलाओं के लिए और केवल 3.5 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए देता है। और प्रत्येक 12 ऋणों में से केवल एक नए उद्यमों के लिए होता है, इसलिए पीएमएमवाई मुख्य रूप से मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों को ही कार्यशील पूँजी दे रहा था, जिनमें से अधिकांश उद्यम खुदरा व्यापार में लगे हुए थे, या सेवा के उद्यमों में लगे हुए थे, और कुछ समूहों में विनिर्माण को छोड़कर हथकरघा, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी होता है।

स्वयं-उद्यम केवल, कुछ परिवार के सदस्यों के लिए स्वरोज़गार पैदा करते हैं। उद्यमों में नौकरियों के लिए, हमें पीएमएमवाई (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) शब्दावली का उपयोग करने के लिए किशोर और तरुण श्रेणी के उद्यमों को बढ़ावा देना होगा। इससे पहले हमने देखा था, कि PMMY के तहत काम करने के लिए बैंक ऋण के रूप में लगभग 5 लाख रुपये लिए गए थे। अगर हम यह मान लें कि यह ऋण उद्यमियों की अपनी पूँजी का दोगुना था, तो 2015-17 की अवधि में एक नया काम करने के लिए 7.5 लाख रुपये सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में PMMY के तहत लिया गया। इसे 2021-30 दशक तक के लिए मानते हुए, हम (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) MSME क्षेत्र में प्रति कार्य 10 लाख रुपये के निवेश का अनुमान लगा सकते हैं।

इसका अर्थ है कि छोटे उद्यमों में 6 करोड़ नए रोज़गार सृजित करने के लिये, 2021-30 के दशक में कम से कम 60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। यह संख्या 2019 में भारत की जीडीपी का लगभग 30 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में, जीडीपी के लगभग 3 प्रतिशत को सूक्ष्म उद्यमों के

माध्यम से नए रोज़गार सृजन में निवेश करना होगा। यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि सरकार से इसकी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें से एक तिहाई उद्यमी स्वयं की बचत, पारिवारिक योगदान, और सामाजिक एकत्रीकरण जैसे स्वयं सहायता समूह और एसएचजी फेडरेशन से अन्य दो-तिहाई बैंक ऋण के रूप में आएँगे।

खुद को आश्वस्त करने के बाद कि फंडिंग आएगी, हमें दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता प्रोग्राम (एसवीईपी) जैसी योजनाओं से सबक लेकर आजीविका विकास कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने की जरूरत है। ग्रामीण घरों की मदद करें, जिसमें उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं को भी शामिल किया जाए। 2017-18 से शुरू होकर, अब तक 23 राज्यों में कुल 1,00,000 से अधिक उद्यमों को बढ़ावा दिया गया था। एक हालिया स्वतंत्र मूल्यांकन (QCI, 2019) ने (SVEP) स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता प्रोग्राम में बहुत अनुकूल परिणाम दिखाए हैं। जिससे आकांक्षी सूक्ष्म उद्यमी बैंकों से बहुत अधिक वित्तीय सहायता के बिना भी अपने उद्यम शुरू करने में सक्षम हुए थे। लापता घटक उद्यमशीलता की प्रेरणा थी। यह समय है जब हमने डेविड मैकलेलैंड के 1960 के दशक में SIET संस्थान (अब MIMSME) हैदराबाद और काकीनाडा में किए गए कार्यों को फिर से किया और इसे समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास का एक अभिन्न अंग बनाया।

4.2.5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बड़े उद्योगों में उच्च कौशल रोज़गार

विनिर्माण क्षेत्र के उच्चम स्तर के लिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनिवार्य है। इसकी ओर, 2020 में, भारत सरकार की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 10 प्रमुख क्षेत्रों में भारत सरकार ने पाँच वर्षों में 145,980 करोड़ रुपये (1.45 ट्रिलियन) के परिव्यय के साथ प्रोडक्शन-लिंकड इंसटिव (PLI) योजना की शुरुआत की थी। यह विश्व स्तर पर दस सेक्टरों के प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में अधिक विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों को जोड़ेगा।

उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना क्षेत्र	रुपये में परिव्यय करोड़ में
एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेल (एसीसी) बैटरी	18100
इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद सहित सेमीकंडक्टर फैब / अर्धचालक प्रदर्शित फैब लैपटॉप / नोटबुक सर्वर इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स डिवाइस निर्दिष्ट कंप्यूटर हार्डवेयर	5000

ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक / पुर्जे	57042
औषधीय दवाएँ	15000
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	12195
कपड़ा उत्पाद : वस्त्र और तकनीकी एमएमएफ खंड	10683
खाद्य उत्पाद / पदार्थ	10900
उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स	4500
सफेद सामान (एसी और एलईडी)	6238
स्टील की विशेषता	6322

चूँकि इन क्षेत्रों में प्रति रोज़गार निवेश केवल 2-3 करोड़ रुपये हैं, इसलिये इसमें केवल लगभग 300,000 नौकरियाँ ही मिल पायेंगी। इस तरह सरकार द्वारा निवेश के समान स्तर के लिए सौ गुना, यानि तीन करोड़ लोगों को MNREGS के तहत 100 दिनों का काम मिल सकता है। भारत में आजीविका की स्थिति पर इन क्षेत्रों के प्रभाव के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम इस बात से सहमत हैं, कि ऐसी नौकरियों का सृजन किया जाना चाहिए, और ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें सभी निवेश निजी क्षेत्र से आने चाहिए, और कोई सरकारी सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) या अन्य साधनों के रूप में।

4.2.6 सभी क्षेत्रों में अनुमानित सेवाएँ - ग्रामीण और शहरी

समीपवर्ती सेवाएँ वे सेवाएँ हैं, जिन्हें केवल तभी वितरित किया जा सकता है जब ग्राहक - उपयोगकर्ता सेवा देने वाले के पास हो। एक स्पष्ट उदाहरण है, जैसे - बाल काटना, लेकिन यहाँ तक कि अधिकांश खुदरा व्यापार, भंडारण, परिवहन, होटल और खाने-पीने के स्थान आदि समीपवर्ती सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। ये टेली-सेवाओं या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम सेवाओं से अलग हैं, जिन्हें आमतौर पर इंटरनेट का उपयोग करके दूरी पर भी वितरित किया जा सकता है।

कई सेवाएँ - शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक प्रशासन, जो समीपवर्ती सेवाएँ COVID महामारी के दौरान IT- सक्षम टेली-सेवाओं में बदल गईं। वित्तीय, शिक्षा और मनोरंजन सेवाएँ काफी हद तक दूरस्थ वितरण में बदल गई हैं और निकटवर्ती मोड में महत्वपूर्ण रूप से वापस आने की संभावना नहीं है। अभी भी, बड़ी संख्या में समीपवर्ती सेवाएँ बनी हुई हैं और ये आजीविका का प्रमुख स्रोत होंगे।

खुदरा व्यापार में आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए, आजीविका का संरक्षण और फुटपाथ पर बिक्री का विनियमन अधिनियम, 2014 को स्वभाव में लागू करने की आवश्यकता है। वेंडिंग का नया रूप ई-कॉमर्स डिलीवरी है और इस व्यवसाय में नौकरियों में तेजी देखी जाएगी।

पर्यटन के क्षेत्र में काफी नौकरियाँ संभव हैं, जोकि एक समग्र सेवा का क्षेत्र है, जिसमें परिवहन, होटल, और रेस्तराँ, मनोरंजन और व्यवसाय सेवाएँ शामिल हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों के धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों, और वन्यजीवों, के लिए नए पर्यटन स्थलों को विकसित करके जिम्मेदार पर्यटन में नई नौकरियों का सृजन किया जा सकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ, व्यवसाय और वित्तीय सेवाएँ, प्रमुख नियोक्ता हो सकते हैं, यदि सरकार निजी भागीदारी को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ बनाती है तो।



4.3 डिजिटल सेवाओं में युवाओं व और महिलाओं के लिए आजीविका



आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएँ पहले से ही एक बढ़ते क्षेत्र थे, और COVID महामारी के बाद इनकी माँग में और तेजी का अनुभव किया गया है। व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएँ, जिसमें कॉल सेंटर, अकाउंटिंग बैक ऑफिस, अनुलेखन, और दस्तावेज़ कैप्चरिंग सेंटर आदि शामिल हैं, ये सभी प्रमुख रोज़गार के वृद्धि क्षेत्र हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी के साथ आईटी सेवाओं के विकास के लिए (ए) उदारकृत विदेशी निवेश नीति की आवश्यकता है जो आईटी सेवा आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और वृद्धि के अनुरूप हो।

ये सेवाएँ रोज़गार के अधिक न्यायसंगत प्रसार के लिए एक महान अवसर प्रदान करती हैं - युवाओं के लिए, जिनके पास बेरोजगारी की उच्च दर है, और उन महिलाओं के लिए, जिनके पास शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और ऋण की कमी के कारण श्रम बल की भागीदारी दर कम है, जैसा कि इस खंड में 'लिंग पर' अध्याय में स्मिता प्रेमचंदर आदि द्वारा प्रकाश डाला गया है।

4.3.1 महानगरों की बनिस्बत छोटे शहरों में आईटी सर्विसेज में रोज़गार

उचित बुनियादी ढाँचे का विकास - विदेशी ग्राहकों के लिए टेली-कनेक्टिविटी, टियर II और टियर III, शहरों में निर्बाध बिजली और कार्यक्षेत्र, देश में अधिक आईटी समूहों के विकास की सुविधा प्रदान करेंगे। हालाँकि बेंगलूर, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और कोलकाता प्रमुख आईटी केंद्रों के रूप में उभरे हैं। हम एक दशक में, बेंगलूर को “धमाकेदार” साबित कर सकते हैं। क्योंकि भुवनेश्वर, गंगटोक, गुवाहाटी (नीचे आयत 13 देखें), आइजोल, रांची, श्रीनगर या लेह की तुलना में इसकी लागत बहुत अधिक है। COVID महामारी के लिए धन्यवाद, उन शहरों में रहने वाली प्रतिभाएँ घर से काम करने का खर्च उठा सकती हैं।

आयत 14: इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन विश्लेषण पटल (eTaal) पोर्टल

दिसंबर 2020 में, 1.51 बिलियन से अधिक मोबाइल फोन नंबर उपयोग में थे और 44.8 करोड़ इंटरनेट मोबाइल स्मार्टफोन उपयोगकर्ता थे। 2020 में ई-ताल पोर्टल के अनुसार 3995 प्रकार की सेवाओं के लिये 71 बिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन हुए। ये कृषि, भूमि रिकॉर्ड, ई-कोर्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन), बिजली, पानी और गैस बिल भुगतान, आयकर और जीएसटी और निजी व्यवसाय आम सेवा केंद्रों (सीएससी) द्वारा दी जाने वाली नागरिक सेवाओं के लिए कवर किए गए हैं। [Http://etaal.gov.in](http://etaal.gov.in) पर अधिक देखें

इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है, कि आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं ने जनता के जीवन में काफ़ी बदलाव किया है। व्यापक रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, कि आईटी और आईटी सक्षम सेवाएँ केवल श्रम बाजार के उच्च स्तर के इंजीनियरों और ऐसे लोगों के लिए रोज़गार वृद्धि के लिए हैं - हालाँकि, कई स्व-शिक्षित ऐप डेवलपर हैं। और ऐप आधारित व्यवसाय (जैसे कि टिक टोक कलाकार) जिन्होंने उच्च शिक्षा नहीं ली है। (नीचे आयत 15 देखें)। और इस प्रकार, कुलीन वर्ग के लिए आईटी आजीविका एक मिथक है। बस (सीएससी) सामान्य सेवा केंद्र (आईटी सेवा कियोस्क) ऑपरेटरों को कुछ राज्यों में ई-मित्र के रूप में जाना जाता है, जोकि ढाई लाख से अधिक हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश युवा शिक्षित नहीं हैं।

आयत 15: नव गुरुकुल - पिरामिड के आधार पर डिजिटल प्रतिभा का पोषण करने का प्रयास

यह संगठन 2016 में स्थापित किया गया था, और यह बहुत कम आय वाली पृष्ठभूमि के युवाओं को पहचानने और उन्हें प्रशिक्षण देने में माहिर है। अक्सर स्कूली शिक्षा पूरी किए बिना एक साल के आवासीय प्रशिक्षण के साथ नव गुरुकुल उन्हें विशेषज्ञ प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में ढालता है। इन्हीं में से अधिकांश आईटी फर्मों में रखे जाते हैं, क्योंकि वे एक साल का कार्यक्रम पूरा कर चुके होते हैं, और ये प्रति माह 30,000 रुपये से 40,000 रुपये तक कमाते हैं। ऐसे ही एक युवा सुनील परचा, जिनके पिता उत्तरी दिल्ली नगर निगम में एक कार्यकर्ता थे, ने COVID के दौरान जीवनयापन किया, लेखक जैसे- शौकिया शिक्षार्थियों को पायथन प्रोग्रामिंग सिखाई। [Https://navgurukul.org/](https://navgurukul.org/) पर और देखें

4.4 आजीविका के स्थानिक पुनर्वितरण - विकास केंद्र के रूप में जिले

हमें अनियंत्रित प्रवास को कम करने के लिए जहाँ आबादी रहती है, वहाँ यथासंभव रोज़गार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। केवल ग्रामीण-शहरी वितरण के बजाय, हमें रोज़गार के तीन तरह से स्थानिक वितरण के बारे में सोचना चाहिए।

- **ग्रामीण:** - 5000 से कम आबादी वाले लगभग 6 लाख गाँव - जहाँ नेचुरल रिसोर्स रिजनरेशन (प्राकृतिक संसाधन उत्थान) का काम शुरू में और बाद में विविधतापूर्ण, टिकाऊ कृषि और कृषि सेवाओं पर केंद्रित होगा, जिसे किसान निर्माता कंपनियों के आसपास आयोजित किया गया है।

● **जिला मुख्यालय और विनिर्माण क्षेत्रों सहित छोटे शहर :-** जो 2020 तक लगभग 5000 होने की उम्मीद है, परन्तु हम यहाँ पर केवल शीर्ष 1000 पर ध्यान देने की सलाह देंगे

● **बड़े शहर और महानगर:-** ये महानगरीय और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर जो लगभग 100 तक हैं, और कुछ अन्य हैं। ये पहले से ही आजीविका के मुख्य स्थान हैं, विशेष रूप से निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में। हालाँकि, हमें इस दशक में, 100 स्मार्ट शहरों के लिए काउंटर-मैग्नेट की जरूरत है।

ग्रामीण क्षेत्र से बड़े शहरों में प्रवास कम करने के लिए - हमें दो तरीकों से काम करने की आवश्यकता है - ग्रामीण और छोटे शहरों के रोजगार को और बड़ा बनाना, और अधिक आकर्षक बनाना। इसके लिए स्थानीय, जिला स्तर पर आजीविका की आवश्यकता होती है। स्मार्ट शहरों से पहले या इसके बजाय, हमें समर्थ जिलों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त आजीविका पैदा करने में सक्षम हैं। समर्थ जिला 'सक्षम जिला' के रूप में अनुवाद करता है, अर्थात्, एक ऐसा जिला जो अपनी जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा करने में सक्षम है - भोजन, वस्त्र, आश्रय, आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आदि।

ग्रामीण बनाम शहरी विकास के प्रचलित प्रारूपों ने पूर्वी या दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में अपने समकक्षों के मुकाबले विकास के स्तर को प्राप्त करने में भारत के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में लोगों की मदद नहीं की है, जो स्वतंत्रता के बाद समान स्तर पर थे। समर्थ जिला अवधारणा का उद्देश्य स्थानिक रूप से एकांगी विकास को संबोधित करना है, जिसमें प्रत्येक राज्य के कुछ शहरों का तेजी से विकास हुआ है। ये शहर राज्य के भीतर और अन्य विकसित राज्यों से कम विकसित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो व्यवहार्य आजीविका विकल्प प्रदान करने में विफल होते हैं। जिलों के भीतर, उत्पाद विशेषज्ञता के साथ सूक्ष्म जीवों के समूहों को विकसित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने पहले से ही एक जिले, एक उत्पाद के इस ढाँचे को अपनाया हुआ है। समूह ऑब्जर्वेशन के अनुसार, एमएसएमई समूह के लिए फाउंडेशन की एक परियोजना, भारत में 5600 से अधिक समूह संचालित हैं। हस्तशिल्प में सबसे ज्यादा संख्या है।

तालिका 9: भारत में क्लस्टर (समूह)

समूह की श्रेणी:	संख्या:	समूह की श्रेणी:	संख्या:
औद्योगिक समूह	1416	हस्तशिल्प	3403
सूक्ष्म-उद्यम मिश्रित	154	हथकरघा	608

स्रोत: UNIDO <http://laghu-udyog.gov.in/clusters/clus/ovrclus.htm>

इन समूह शहरों (जैसे पीतल के काम के लिए मुरादाबाद और होजरी के लिए तिरुपुर) में विनिर्माण में नौकरियाँ बढ़ सकती हैं, हाँ यदि यहाँ एसएमई (स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़) को अधिक उत्पादक और निर्यात उन्मुख बनाया जाता है। कई छोटे ऐसे समूह हैं, जिनमें से कुछ ने माँग की स्थितियों में बदलाव के कारण अपनी जीवन शक्ति (मार्मिकता) खो दी है। लेकिन इस तरह के समूहों में उद्यमों का समर्थन करने के लिए क्लस्टरिंग एक आवश्यक रणनीति बनी हुई है। जैसा कि श्रेया मोजुमदार ने लिखा है, सूक्ष्म / लघु उद्यमों के क्लस्टरिंग की सुविधा के लिए उनके आवेदन और पात्रता को पूरक वित्त पोषण के लिए सक्षम बनाना (उदाहरण, अनुदान और धन).....

एक ही अध्याय में कई उदाहरण हैं, कि पारंपरिक शिल्प क्षेत्र अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, ऑर्डर बुक करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए इंटरनेट जैसी नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है और साथ ही ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर रहा है। अन्य लोग पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, ताकि उनके शिल्प उत्पादों को दूर के स्थानों पर भेज दिया जा सके, जिसमें निर्यात स्थल भी शामिल हैं। नई पीढ़ी की क्षमता निर्माण का एक अन्य उदाहरण दा हैंडलूम स्कूल, महेश्वर, एमपी में है, जिसका युवा हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यक्रम "सर्टिफिकेट इन डिज़ाइन एंड एंटरप्राइज मैनेजमेंट (सीडीईएम)" है। विपणन के लिए, फ़ैब इंडिया, और अनेकों जैसे खुदरा स्टोर शृंखलाएँ हैं, साथ ही साथ डिल हाट जैसे आउटलेट भी हैं, जहाँ शिल्पकला वाले व्यक्ति अपनी उपज का विपणन कर सकते हैं। हैंडलूम और हस्तशिल्प में विशेषज्ञता वाली बड़ी संख्या में ई-कॉमर्स साइट सामने आई हैं। ये सभी विकास शिल्प उद्यमों में अधिक पारिश्रमिक आजीविका के विकास के लिए अच्छी तरह से विकसित होते हैं।

इसके साथ, हम आने वाले दशक में भारत की आजीविका चुनौती को संबोधित करने के लिए चार प्रमुख रणनीतियों पर अनुभाग को समाप्त करते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मुड़ते हैं कि इन रणनीतियों, और प्रक्रियाओं, संसाधनों और संस्थानों को कैसे लागू किया जाए। हम इसे अष्टसूत्रीय मार्ग कहते हैं।



5 2030 तक सभी के लिए सतत आजीविका के लिए अष्टसूत्रीय मार्ग

अशोक पार्थसारथी की विज्ञान नीति के विचारक स्वर्गीय अशोक पार्थसारथी ने 1970 के दशक में एक प्रसिद्ध टिप्पणी की, जब "आत्मनिर्भरता" को अक्सर भारत के विकास के लिए स्वयंसिद्ध वांछनीय रणनीति के रूप में पेश किया जाता था। उन्होंने पूछा, "आत्मनिर्भरता जवाब है। प्रश्न क्या है? "। आज आत्मनिर्भरता को एक बार फिर से राष्ट्रीय एकता अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय रणनीति में बदल दिया गया है।

क्या आने वाले दशक में हमारे लिए और 12 करोड़ नई आत्मनिर्भर आजीविका बनाने का लक्ष्य है? इसका उत्तर हाँ है, लेकिन इसके लिए सभी लोगों - जनता, सरकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र, ज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों और हमारे बैंकों और वित्तीय संस्थानों, की मानसिकता एवं सोच में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने की आवश्यकता होगी।

हमें अपनी सरकारी निर्भरता, पूँजी एवं प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के प्रति सन्देहास्पद दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि युवा बाहुल्य जन संख्या एक निराशा न बन जाए। हमें उन मानव संसाधनों को महत्व देने की आवश्यकता है, जो आज जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र और विकलांगता के आधार पर हाशिए पर या बहिष्कृत हैं। हमें पर्यावरण को महत्व देने की आवश्यकता है, और पुनः उपयोग करने और पुनःसंस्करण के मंत्र को अपनाना चाहिए। अतः हम मानसिकता एवं सोच में परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। इसके आठ आयाम हैं।

5.1 कृषि को निर्वाह मात्र से सतत रोज़गार बनाना आवश्यक है



भारतीय छोटे और सीमांत किसान पहले से ही “आत्म नर्भर” हैं। 2013 में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के 70 वें दौर के अनुसार, 48 प्रतिशत फार्म हाउसों पर कोई भी उधार नहीं था। और 42 प्रतिशत को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कोई बीमा कवरेज नहीं मिला। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ लगभग 94 प्रतिशत (कुछ का कहना है कि 80%) को नहीं मिला। और इस तथ्य के बावजूद कि भारत के लगभग दो-तिहाई फार्म हाउसों की आय में कमी है, 43 प्रतिशत के पास रियायती खादन्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड नहीं थे, और 56 प्रतिशत के पास कोई मनरेगा जॉब कार्ड नहीं था। बेशक, 2013 से 2020 के बीच, इनमें से प्रत्येक पहलू में सुधार हुआ है, लेकिन तथ्य यह भी है, कि भारत के किसान परिवार कहीं भी स्थायी नहीं हैं, न तो आर्थिक रूप से और न ही पर्यावरणीय के रूप से।

हमने पहले से ही तुच्छ प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्जनन की सिफारिश की है - जैसे कि सिल्ट जल निकायों, सूखने वाली नदियों, प्रदूषित नदियों, मिट्टी का खर्च, घटती हुई भूमि और खंडित जंगलों, जोकि सभी छोटी अवधि में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करेंगे। यह पुनर्जनन तब कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, और वानिकी क्षेत्र में पुनरुत्थान के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। भारत को न्यूनतम प्राकृतिक संसाधनों - जल, जंगल, जमीन के उत्थान के लिए 4 ट्रिलियन या 2019-20 के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है। नतीजतन, लगभग एक करोड़ लोग इसके अलावा कृषि, डेयरी, वानिकी, मत्स्य पालन आदि में निरंतर रूप से लगे रह सकते हैं।

इसके लिये अतिरिक्त उत्पादन को संसाधित करने की आवश्यकता होगी। कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों की निर्माता कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत स्वामित्व दिया जाना चाहिए, और पेशेवरों को प्रबंधित किया जाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है, तभी किसानों को शृंखला में जोड़े गए मूल्य का एक हिस्सा मिलेगा।

जैसा कि शिवाकुमार ने इस खंड में कृषि पर अध्याय में लिखा है, "सामान्य जागरूकता में सुधार और आय के स्तर में भी वृद्धि के साथ, आज के उपभोक्ता भोजन में अधिक विविधता की तलाश कर रहे हैं, साथ ही साथ बेहतर गुणवत्ता की भी। यह कृषि उत्पादन को सब्जियों, फलों, पोषक तत्वों-अनाजों (बाजरा), दालों और दूध और मांस जैसे उत्पन्न उत्पादों की तरह अधिक उत्पादन वाली फसलों में विविधता लाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।

इसके अलावा, भारत का कृषि निर्यात, जो कि लगभग 40 बिलियन अमरीकी डालर है, और भारत के उत्पादन का मात्र 7 प्रतिशत है। इसका प्रमुख हिस्सा उपयोगी वस्तु एक्सपोर्ट है, जिसमें केवल 15 प्रतिशत वैल्यू एडेड प्रोसेस किया जाता है। हालाँकि, मौजूदा वैश्विक बाजार में महज 2.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, भारत के पास विकास के लिए भारी बढ़त है। इस क्षमता को फसल की मूल्य शृंखलाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करके महसूस किया जा सकता है जो वैश्विक माँग से जुड़ी हुई हैं, और जिसमें भारत का पहले से ही तुलनात्मक लाभ है। इस तरह की मूल्य शृंखलाओं में झींगा, मसाले, फल और सब्जियाँ शामिल हैं, इसके अलावा चावल जैसी पारंपरिक फसलें भी शामिल हैं।

इन दोनों अवसरों से लाभ पाने के लिए, किसानों को फसल प्रबंधन में नए ज्ञान और इनपुट और आउटपुट (उत्पादक सामाग्री / उपज) बाजारों के लिए कुशल संपर्क साधनों की आवश्यकता है। इसका मतलब है, कि सरकार के नेतृत्व में उत्पादन-संचालित आपूर्ति शृंखलाओं से प्रणाली का एक मूलभूत परिवर्तन, उपभोक्ता-उन्मुख बाजार के खिलाड़ियों द्वारा माँग की जाने वाली मूल्य-उत्तरदायी मूल्य शृंखलाओं के लिए। ”

कृषि में उपरोक्त अवसरों के बावजूद, इसमें लगे लोगों की अधिकता के कारण, हमें कृषि से गैर-कृषि गतिविधियों से बाहर निकलने में अधिक लोगों की मदद करनी होगी। इसे इस दशक के लिए एक रणनीति के रूप में अपनाया जाना

चाहिए, जैसा कि चीन द्वारा किया गया था - जब 1979 से 1989 के बीच 10 करोड़ लोगों को कृषि से छोटे शहरों और गाँव के उद्यमों में स्थानांतरित किया गया था। हमारी अलग राजनीतिक प्रणाली को देखते हुए, हम कम से कम 2 करोड़ लोगों को कृषि से गैर-कृषि गतिविधियों में स्थानांतरित करने का लक्ष्य बना सकते हैं। इसके लिए स्किलिंग, छोटे शहर के बुनियादी ढाँचे और बाजार लिंकेज में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

5.2 देश को पुनः हरियाली पूर्वक करने के लिए तीन कदम



पुनर्जनन ने प्राकृतिक संसाधनों का हास किया है - जल, जंगल, जमीन - पर पहले ही बात की जा चुकी है। यद्धपि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, और वानिकी में श्रमिकों का अनुमानित प्रतिशत 2020 में 44.9 प्रतिशत से घटकर 2030 में 40.4 प्रतिशत रह जाएगा, लेकिन निरपेक्ष संख्या लगभग 2.9 करोड़ श्रमिकों तक जाएगी। इस प्रकार, कृषि, पशुपालन, मत्स्य और वानिकी गतिविधियों का समर्थन करने वाले प्राकृतिक संसाधन आधार में निवेश करने से कोई बचा नहीं है। न केवल संसाधन पुनर्जनन अगले तीन से पाँच वर्षों में और अधिक नौकरियाँ पैदा करेगा, बल्कि यह तब कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अधिक स्थायी आजीविका भी बनाएगा। इसके कारण होने वाली हरियाली के अलावा, हमें तीन और कदम उठाने की आवश्यकता है:

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण, सौर ऊर्जा, और साथ ही एक विकेन्द्रीकृत आधार पर बायोमास / बायोगैस, बढ़ती ऊर्जा लागत के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता के कारणों के साथ कृषि, विनिर्माण और सेवा उद्यमों की आर्थिक स्थिरता के लिए राष्ट्र के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण। जैविक - अपघटनीय और रिसाइकिल योग्य कचरे का पृथक्करण इसके लिए जरूरी है, और जैसे-जैसे यह प्रवृत्ति तेजी पकड़ रही है, इसलिये अगला तार्किक कदम संग्रह, प्रसंस्करण और पुनः उपयोग के लिए मूल्य शृंखलाओं को जोड़ना है।
- इसी तरह, शहरी क्षेत्रों से तरल अपशिष्ट - मुख्य रूप से सीवेज, मिट्टी के ह्यूमस में सुधार के लिए अक्षय ऊर्जा (गैस के रूप में) और जैविक खाद दोनों का स्रोत हो सकता है। दोनों प्रमुख रोजगार निर्माता हैं और पर्यावरण में सुधार करते हैं।

आजीविका पैदा करने के अलावा, ये तीन कदम - प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और कचरे का पुनर्चक्रण पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। पहला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का सीक्वेंस करेगा, जबकि बाद के दो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेंगे। इसके अलावा, विभिन्न प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को पुनर्जीवित करने से COVID जैसे जूनोटिक रोगों की संभावना कम हो जाएगी।

5.3 स्कूल शिक्षा, कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना



स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, पिछले दो दशकों में, समग्र नामांकन दर के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालयों में महिला नामांकन के मामले में बड़ी प्रगति हुई है। फिर भी, स्कूल छोड़ने की दर नामांकन से ज्यादा ऊँची है, यह उत्तरी राज्यों में लगभग 40 प्रतिशत है। वहीं सीखने के परिणामों के संदर्भ में भी, परिणाम निराशाजनक रहे हैं, शिक्षा की यह स्थिति, वार्षिक शिक्षा स्थिति (एएसईआर) की रिपोर्ट के अनुसार है। 2018 में, भारत में कक्षा 8 में नामांकित सभी बच्चों में से लगभग 73% कम से कम कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं और केवल कक्षा 8 के सभी बच्चों में से लगभग 44 प्रतिशत

बच्चे 3 अंकों की 1-अंकीय संख्यात्मक समस्या सही ढंग से हल कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता की पेशकश करना, हमारी सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा का एक मात्र राष्ट्रीय लक्ष्य है, और हमें इस दशक में इसे प्राप्त करना चाहिए।

कौशल के मामले में, 2013 में भारत में केवल 3 प्रतिशत छात्रों की तुलना में 47 प्रतिशत चीनी वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों ने व्यावसायिक स्ट्रीम में प्रवेश किया था। तब से, स्कूलों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क कार्यक्रम के रोलआउट के साथ, कुछ सुधार हुआ है लेकिन हमें स्कूल और उच्च स्तर पर कौशल विकास में गंभीर निवेश करने की आवश्यकता है। हमने आगामी दशक में रोज़गार में वृद्धि के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है।

- कृषि सेवाएँ और कृषि प्रसंस्करण
- निर्माण - आवास के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे के लिए
- विनिर्माण - उच्च और अंत दोनों छोटे स्तर पर
- समीपवर्ती सेवाएँ - खुदरा व्यापार, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और सामाजिक सेवाएँ।
- डिजिटल सेवाएँ

हमें कौशल विकास के लिए इको-सिस्टम में कई सुधार करने की आवश्यकता है, जो 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण और एक नाम निगम के नेतृत्व में बनाया गया था। हमें कौशल प्रशिक्षण को सरकार की छत्रछाया से बाहर निकालना होगा और इसे उद्योग का नेतृत्व करना होगा। हमें उद्यमिता और इसके आधार, उपलब्धि प्रेरणा में प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है।

5.4 समावेशी आजीविका संवर्धन के लिए एकाधिक वित्तीय स्रोतों का उपयोग



5.4.1 विभिन्न वित्त स्रोतों के साथ उपयोगों का मिलान

कुल निवेश 120 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जोकि 2021 में भारत की जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत होगा। इसके अलावा, इसे दस साल के अंत तक परिणाम दिखाने के लिए दशक के पहले छह वर्षों की अवधि में ध्यान केंद्रित करना होगा। इस प्रकार, सभी के लिए आजीविका में निवेश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष या अर्थव्यवस्था में मौजूदा वार्षिक निवेश का लगभग एक तिहाई पहले छह वर्षों के लिए है। इन सभी का सार नीचे तालिका 10 में दिया गया है :

प्राकृतिक संसाधनों के उत्थान का वित्तपोषण सरकारी बजट संसाधनों और संभवतः नाबार्ड जैसी एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। कृषि विविधीकरण का वित्तपोषण किसान परिवारों और बैंक ऋण के माध्यम से करना होगा। किसान स्वामित्व वाली कृषि मूल्य शृंखलाओं का वित्तपोषण किसान परिवारों, एफपीओ जैसे सामुदायिक सामूहिक, बैंक ऋण और कॉर्पोरेट वित्त द्वारा करना होगा।

तालिका 10: 2030 तक सभी के लिए आजीविका के लिए पूँजी की आवश्यकता और संभावित स्रोत

धन के स्रोत	2021-26 के दौरान करोड़ रुपये में निवेश की आवश्यकता	व्यक्तिगत हाउस-होल्ड	सामुदायिक संग्रह	कॉर्पोरेट सीएसआर	सरकारी बजट	बैंकों और फाइनेंस	कॉर्पोरेट निवेश
जल, जंगल, और जमीन का उत्थान	12,00,000	लघु	लघु	लघु	प्रमुख	लघु	लघु
कृषि गोताखोर-संशोधन और सामूहिक मूल्य शृंखला	8,00,000	लघु	मीडियम	लघु	लघु	मीडियम	मीडियम
छोटे शहरों में बुनियादी ढाँचा	20,00,000	लघु	लघु	लघु	प्रमुख	लघु	मीडियम
शिक्षा और कौशल विकास	20,00,000	मीडियम	मीडियम	लघु	प्रमुख	लघु	मीडियम
सूक्ष्म और लघु उद्यम	50,00,000	मीडियम	मीडियम	लघु	लघु	प्रमुख	मीडियम
गैर-महानगरों में डिजिटल सेवाएँ	10,00,000	मीडियम	मीडियम	लघु	लघु	प्रमुख	मीडियम
2021-26 में कुल निवेश करोड़ रुपये में	120,00,000	इस निवेश का केवल एक छोटा हिस्सा सरकार से अपेक्षित है। बाकी ऊपर सूचीबद्ध अन्य स्रोतों से आएँगे					

स्रोत : 2030 तक 12 करोड़ आजीविका के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों पर आधारित लेखक की गणना

छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों में छोटे बुनियादी ढाँचे के निर्माण का वित्तपोषण सरकार के बजट संसाधनों और संभवतः नाबार्ड आरआईडीएफ जैसी एजेंसियों को करना होगा। स्व-रोज़गार के लिए गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमों का वित्तपोषण बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों और पीएमएमवाई मुद्रा बैंक के बैंक ऋण के माध्यम से किया जाना होगा। डिजिटल सेवा उद्यमों का वित्तपोषण बड़े पैमाने पर इक्विटी (स्वयं के फंड), बैंक ऋण और कॉर्पोरेट वित्त के माध्यम से करना होगा।

5.4.2 इक्विटी वित्त के साथ स्टार्ट-अप, फिर बैंक ऋण यदि उद्यमी और आगे बढ़ते हैं

भारत के 90 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमी आत्म-निर्भर थे, क्योंकि वे ज्यादातर परिवार और दोस्तों के फंडों से और फिर स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के सहयोग से शुरू करते थे। लेकिन उनके आत्म निर्भरता की लागत कम आय, उच्च भेद्यता की स्थिति में फंसे रहना है। उससे कैसे निपटें? यह एक व्यापक धारणा है, कि उद्यम स्थापित करने में क्रेडिट मुख्य बाधा है। उद्यमों को शुरू करने के लिए दिए गए बैंक ऋण डिफॉल्ट रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि नए उद्यमों के लिए ऋण गलत वित्तीय उत्पाद है। ऋण वित्तपोषण में, उद्यमी को निश्चित किस्त चुकौती को बनाए रखना पड़ता है और इससे ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) बन जाता है। जिससे पुरानी किस्तों पर पकड़ मुश्किल हो जाती है।

जब यह अध्याय लिखा जा रहा था, तब भी हमने घोषणा की थी, कि उद्यमिता विकास में उत्कृष्टता के लिए पीएम उद्यम मित्रा (UMEED) योजना 1 अप्रैल 2021 को शुरू की जाएगी। ताकि 2025-26 तक उद्यमी बनने के लिए 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्हें ऋण प्रदान किया जा सके। हमें 3 लाख नहीं बल्कि सौ गुना, 3 करोड़ नए उद्यम स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए 18 ट्रिलियन निवेश की आवश्यकता होगी। इक्विटी पूँजी के इस स्तर के साथ, ऐसे उद्यम उद्यमी के लिए स्वरोज़गार पैदा करेंगे और 10 अन्य लोगों के लिए रोज़गार पैदा करेंगे।

यह देखते हुए कि सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट-अप कॉहर्ट्स के पास तीन में से केवल एक की सफलता दर है, बैंक ऋण के साथ नए उद्यमों के वित्तपोषण से बैंकों के लिए कई और एनपीए उत्पन्न होंगे और उद्यमियों को डिफाल्टर में बदल देंगे। इसके बजाय, हमें लघु उद्यम स्टार्ट-अप के लिए सूक्ष्म-इक्विटी (0.5 रुपये से 5 करोड़ के बीच) की पेशकश करनी चाहिए। केवल एक माइक्रो-इक्विटी फंड तंत्र ही इसे संभाल सकता है। जबकि इसके लिये कई उद्यमों के तहत जाना होगा, और मामूली लाभदायक होगा, जीवित और संपन्न उद्यमों से रिटर्न निवेश के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा।

माइक्रो-इक्विटी फंड्स को सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के साथ वैकल्पिक निवेश फंडों, एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) श्रेणी। के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, जो कि विशेष रूप से मालिकाना चिंताओं और निकास विकल्पों में निवेश करने के लिए कुछ प्रावधानों पर आधारित हैं। एक और मार्ग जिसका उपयोग किया जा सकता है वह है छोटे स्टार्ट-अप को वित्त करने के लिए प्रस्तावित सोशल स्टॉक एक्सचेंज।

यह इक्विटी सामाजिक उद्यमों के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। आने वाले दशक में, हम किसी भी उद्यम की घोषणा कर सकते हैं जो सामाजिक उद्यम के रूप में 10 गरिमामय सुरक्षित नौकरियाँ प्रदान करेगा।

5.5 अपने आप पर निर्भर, सरकार पर नहीं: स्वयं सहायता ही आत्म निर्भरता है



COVID महामारी का एक मुख्य सबक रहा है। मुसीबत में होने पर, अपनी स्वयं की मदद करें, या अपने परिवार, जाति बिरादरी, पेशेवर सर्कल समुदाय से मदद लें, चाहे कोई भी हो। महामारी के बीच में हमारे प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी, कि महामारी के प्रभावों को दूर करने के लिए, लोगों को आत्म-निर्भर होना पड़ेगा। यह ध्यान रखने वाली बात है। आत्म निर्भर होने का अर्थ "प्रत्येक अपने लिए" अपने के लिये हो सकता है। लेकिन कोई भी अकेले बहुत दूर नहीं जा सकता है हम दूसरों के साथ - हाथ पकड़ सकते हैं। हम तब भी आत्म निर्भर हो सकते हैं, जब हम सब आत्म निर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमेशा स्वयं का बचाव करते हुए, तत्काल परिवार, विस्तारित परिवार, जाति, बिरादरी, या स्वयं सहायता समूह से शुरू करते हुए परिचितों के संकेंद्रित हलकों तक पहुँच सकते हैं। नीचे आयत 16 देखें

आयत 16: बचत, ऋण और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए स्व-सहायता समूह आंदोलन

इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण स्व-सहायता समूह आंदोलन है। 1985 में 100 से कम समूहों के साथ शुरू हुआ, यह आंदोलन 35 वर्षों में बहुत बड़ा हो गया है। नाबार्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक भारत में लगभग एक करोड़ एसएचजी स्व-सहायता समूह थे। 23,324 करोड़ रुपये की राशि जमा करके 14 करोड़ परिवार इसमें शामिल थे। कुल जमा धनराशि 87,098 करोड़ रुपये में से 50 प्रतिशत राशि SHG ने ऋण के रूप प्राप्त किया था।

एसएचजी के बढ़ते हुए सशक्तीकरण प्रभाव को अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों जैसे- कि एक साइट पर निर्माण श्रमिकों या स्ट्रीट वेंडर समितियों के सामूहिक रूप में भी दोहराया जा सकता है। एस (एसएचजी) आंदोलन की भावना को किसान निर्माता कंपनियों में (एफपीसी) की तरह स्थापित किए जा रहे किसानों के समूहों में दोहराया जाना चाहिए।

5.6 संगठित हों - आत्म निर्भर होने का मतलब अकेले होना नहीं है



5.6.1 उत्पादक कंपनियों में किसानों को संगठित करना

भारत सरकार ने छोटे किसानों को संगठित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के विचार को अपनाया है। लगभग 8000 एफपीओ पहले से ही हैं और 10,000 और आने वाले हैं। पिछले दस वर्षों में गठित एफपीओ के अनुभव का एक बहु-राज्य अध्ययन में विश्लेषण (वेदप्रकाश सिंह, 2020) किया गया था। इससे पता चला कि सबसे बड़ी बाधाएँ पूँजी, क्षमता, समन्वय और अनुपालन हैं एफपीओ का उपयोग केवल खरीदारों को कृषि उत्पादों को एकत्र करने और बेचने के लिए करना है, उन्हें बाद के चरणों में मूल्यवर्धन का हिस्सा कभी नहीं मिलेगा।

यहाँ तक कि कुछ सबसे बड़े जैसे (MAHA-FPC) महाराष्ट्र किसान निर्माता कंपनी एक राज्य स्तरीय एफपीसी जो कि महाराष्ट्र में 240 एफपीसी कंपनियों का एक संघ है, जिसने 2020 में 500 करोड़ रुपये की दाल खरीदी और (GUJPRO) गुजरात निर्माता कंपनी लिमिटेड जिसने 200 करोड़ रुपये से अधिक की मूंगफली खरीदी, उन्होंने कोई मूल्यवर्धन गतिविधि नहीं की। महागुप ने ऐसा नहीं किया जोकि एक किसान निर्माता कम्पनी (एफपीसी) संघ है। इसके विपरीत, एक दशक बाद शुरू होने वाली एक नई निजी कंपनी ने महागुप का 20 गुना कारोबार पंजीकृत किया। (नीचे आयत 17 देखें)

आयत 17: अंगूर बिना डिस्टिल्ड (जूस) के खट्टा हो सकता है, महाग्राप्स बनाम सुला वाइन यार्ड्स

हमें सुला वाइन की कहानी से कुछ सीखने की आवश्यकता है, 1991 में स्थापित एक सहकारी साझेदारी फर्म, महाग्रेप्स, जिसमें महाराष्ट्र के सांगली, सोलापुर, पुणे और नासिक जिलों के लगभग 2500 किसानों की सदस्यता वाली 15 सहकारी समितियाँ हैं। इसका उच्चतम कारोबार 25 करोड़ रुपये था। इसके विपरीत, विदेश से लौटे एक युवा उद्यमी राजीव सामंत द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित सुला वाइनयार्ड में लगभग 500 करोड़ रुपये का कारोबार है और इसमें 1000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, इसके अलावा वितरण और विपणन क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से भी रोज़गार मिला है। सुला वाइनयार्ड के शेयरधारक कोई भी किसान नहीं हैं। हमें यह सोचना होगा, कि महाग्रेप किसानों को वाइनरी बनाने से क्यों रोकता है?

जैसा कि पहले कहा गया था, इन कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों की निर्माता कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत स्वामित्व दिया जाना चाहिए, और पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए।

5.6.2 अनौपचारिक क्षेत्र और प्रवासी श्रमिक

कानून के दो टुकड़े, अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (रोज़गार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, ये नियम कागज पर बने रहे। दोनों ने क्रमशः प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण का आह्वान किया, जो उन्हें लाभ और सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। हालाँकि, श्रम विभागों के पास इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कोई रूपरेखा नहीं थी। अब, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता, 2019 ने अंतरराज्यीय प्रवासियों के कानून को रद्द कर दिया है, जबकि सामाजिक सुरक्षा, 2019 के कानूनों ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कानूनों को कम कर दिया है। एक अधिनियम से दूसरे कानूनों तक केवल कानूनी प्रावधानों को लागू करने से कार्यान्वयन में सुधार सुनिश्चित नहीं होगा। जब तक कि भारत सरकार और राज्य सरकारें इन कानूनों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार विभागों को ज़िम्मेदार नहीं बनाती हैं, तब तक पहले जैसी उपेक्षा जारी रह सकती है। इसके अलावा, इन विभागों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ मीडिया और नागरिक समाज दोनों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

जवाबदेही सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका अनौपचारिक और प्रवासी श्रमिकों को व्यवस्थित करना है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, अनौपचारिक श्रमिकों के पास एक काश्तकारी संगठन महासंघ है, जिसमें कई स्थानीय संघों का मिलकर एक संघ है। एक प्रमुख ट्रेड यूनियन, सीटू, ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक प्रवासी श्रमिक संघ को पंजीकृत किया है। आजीविका ब्यूरो जो लगभग तीन दशकों से प्रवासी कामगारों के लिये काम कर रहा है, और नीति समर्थन, और कार्य के रूप में उनका समर्थन करने के लिए दोनों गतिविधियाँ करता है। इसी तरह, लबौरनेट "एक सामाजिक उद्यम है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित पुरुषों, महिलाओं और युवाओं के लिए स्थायी आजीविका को सक्षम बनाता है। [इसका] तीन-आयामी इंजन - शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता, में अंतर को कम करके सामाजिक और व्यावसायिक प्रभाव को एकीकृत करता है।"

हम मान्यता प्राप्त अनौपचारिक श्रमिक संघों (Informal Workers' Associations - IWA) के लिए और उनके गठन और क्षमता निर्माण का समर्थन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए नए श्रम संहिता में एक प्रावधान की सिफारिश करते हैं। यह सिद्धांत महिलाओं के एसएचजी और किसानों की एफपीओ के लिए पहले स्वीकार किया गया है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, NGO आजीविका ब्यूरो के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों के (IWA) अनौपचारिक श्रमिक संघों को मान्यता दी जा सकती है, जबकि श्रमिक नेट के साथ-साथ अनौपचारिक श्रमिकों के IWA को मान्यता दी जा सकती है।

5.7 स्मार्ट सिटी के साथ साथ समर्थ जिलें विकसित करना आवश्यक है



COVID महामारी के दौरान हमारे शहर कितने "स्मार्ट" हैं। यहाँ तक कि शहरों के सबसे गरीब निवासी भी बचकर भाग जाना चाहते थे, जो जिलों में या जिलों के आस-पास रहते थे। हम एक जिला को समर्थ जिला या सक्षम जिला के रूप में परिभाषित करते हैं, अगर यह (ए) अपने प्राकृतिक निवासियों के लिए पर्याप्त आजीविका पैदा करने में सक्षम है, (बी) स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, ऊर्जा, सड़क, परिवहन और दूरसंचार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है, (सी) बुनियादी सेवाएँ प्रदान करता है जैसे -कानून और व्यवस्था और नागरिकों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और संघ गतिविधियों में संलग्न होने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

समर्थ जिला फ्रेमवर्क विकास के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की निरंतरता को पहचानता है। यद्यपि नियोजन की इकाई, पड़ोसी जिलों के एक समूह, या एक नदी घाटी के रूप में बड़ी हो सकती है, समर्थ जिला फ्रेमवर्क जिला स्तर पर डेटा उपलब्धता के साथ-साथ सभी कार्यान्वयन तंत्रों के अस्तित्व के कारण एक जिले को विकास की इकाई बनाता है। जिसकी रूपरेखा एक शहर या एक गांव के बजाय पूरे जिले से संबंधित है, जो एक बड़ी एकीकृत योजना और कार्यान्वयन को सक्षम बनाती है।

अपने क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर यह ढाँचा, विकास के प्रयासों के बारे में सोचने के लिए एक सीमित तरीके से मुद्दों को संबोधित करने के लिए अलग-थलग किए गए हस्तक्षेप के खिलाफ प्रणाली को लागू करने का अवसर देता है। समर्थ जिला के भीतर, छोटे शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए आजीविका के लिए बेहतर स्थान प्रदान करते हैं और जिले के विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र प्राथमिक वस्तुओं के लिए संसाधन

आधार के रूप में काम करते हैं, और छोटे शहर, जिनमें शिल्प समूह शामिल हैं, जो ग्रामीण और शहरी माँग को पूरा करने के लिए उत्पादन आधार के रूप में कार्य करते हैं।

यह हमारा विश्वास है, कि जब तक भारत अपने 700+ जिलों की क्षमता बनाने में निवेश नहीं करता है, तब तक ग्रामीण आबादी और मेट्रो नौकरियों का भौगोलिक दायरा हमें परेशान करता रहेगा। 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधनों के लिए धन्यवाद, जो अनुच्छेद 243-2009 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के साथ हर जिले में एक जिला योजना समिति (डीपीसी) बनाने का प्रावधान करते हैं। DPC जिले के लिए स्थानिक योजना, पर्यावरण संरक्षण, आदि सहित विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए एक जनादेश लेती हैं और संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत करती हैं।

हम लगभग 700 जिला मुख्यालयों सहित लगभग 5000 छोटे शहरों के बुनियादी ढाँचे और आर्थिक आकर्षण के निर्माण में एक महत्वपूर्ण निवेश का सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि 100 स्मार्ट शहरों के बाद विकास (मैग्नेट) विशिष्ट जन का अगला पायदान है। समर्थ जिले प्रवास को कम करेंगे, और निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों / केंद्रों में रोजाना की यात्रा के साथ-साथ गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से सभ्य आजीविका विकल्प प्रदान करने और एक जिले के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सक्षम बनाने के लिए इसे प्रतिस्थापित करेंगे। समर्थ जिला समग्र मानव विकास के लिए अग्रणी जिले भर में सुविधाओं और सेवाओं के समान मानक प्रदान करेगा, और अंत में, अपने निवासियों को सभ्य आजीविका और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करेगा।

5.8 सभी के लिए आजीविका के लिए सहयोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ानी आवश्यक है

किसी भी एकल संगठन के लिए यह कार्य बहुत जटिल है, यह सब अपने दम पर करना है। यह हस्तक्षेप के लक्ष्य के रूप में बहुभुज क्षेत्र के केंद्र में समुदाय के साथ साझेदारी या सहयोगी बहुभुज क्षेत्र के लिए तर्क है। इसका उद्देश्य प्रकृति का दोहन किए बिना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाना है।



स्रोत : लेखक

उपरोक्त उदाहरण में, बहुभुज की परिकल्पना पंचमुखी समवाय के रूप में की गई है - संस्थानों के पाँच सेटों के बीच एक पंचकोणीय सहयोगी साझेदारी (1) सरकार; (2) कॉर्पोरेट सेक्टर और बाजार; (3) सिविल सोसायटी; (4) पूँजी बाजार और (5) ज्ञान संस्थान। फ्रेमवर्क इन पाँच खंडों द्वारा सहयोगात्मक कार्रवाई चाहता है। यह स्थायी आजीविका ढाँचे के कार्यान्वयन के लिए एक व्यावहारिक संरचना प्रदान करता है। यह पाँच प्रमुख हितधारकों के संवादात्मक समर्थन और कामकाज के लिए उचित संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता है।

यदि हम स्वयं आजीविका में निवेश करते हैं, तो रोजगार पैदा करने में न तो सरकार और न ही कॉर्पोरेट जगत सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। यह स्वयं किसान लोग हैं- सूक्ष्म उद्धमी और लघु सेवा क्षेत्र।

सरकार के पास विभिन्न क्षेत्रों, स्थानीय स्थानों और आबादी के कुछ क्षेत्रों के लाभ के लिए संसाधन आवंटन को नीति बनाने की शक्ति है। कॉर्पोरेट क्षेत्र लागत दक्षता और निवेश पर वापसी के साथ अपनी मूलभूत चिंता के कारण, आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने सहित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण आदि में भूमिका निभाता है।

सिविल सोसाइटी संस्थान (CSI), जिसमें गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं, को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, और लोगों को संगठित करने, काम करने के मानदंड विकसित करने, और आजीविका बहाली के पहलुओं को समझने के लिए, अवधारणाओं, सिद्धांत और तकनीकी ज्ञान को आकर्षित करने की आवश्यकता के कारण ज्ञान संगठन, जैसे थिंक टैंक, विश्वविद्यालय और अन्य अनुसंधान निकायों की आवश्यकता है।

अंत में, किसानों और सूक्ष्म उद्यमियों द्वारा बड़ी मात्रा में स्व-वित्तपोषण के बावजूद, हमें 12 करोड़ आजीविका पैदा करने के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। चूँकि सरकार के पास यह क्षमता नहीं है, इसलिए बैंकों और निवेशकों से मुख्य धारा की पूँजी की आवश्यकता होगी।

यह हमारा विश्वास है कि 2021-30 के दशक में 12 करोड़ आजीविका बनाने की चुनौती केवल तभी पूरी हो सकती है, जब सभी हितधारक एक सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनायें जिसमें सरकार सिर्फ केंद्रबिंदु है नहीं बल्कि कलाकारों में से एक है। इसका अर्थ है कि हमें नागरिकों के हाथों को पकड़ना होगा। बिना सरकार की सहायता और भरोसे के। तभी हम विनोबा के अमर निर्माण में प्रभावी - असरकारी हो सकते हैं।

6 आजीविका संवर्धन के लिए अंतिम पुकार

भारत को 2030 तक अपने 61 करोड़ श्रमिकों के लिए पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 2021-2030 के दशक में 12 करोड़ नई आजीविका उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें आने वाले दशक में, पिछले एक दशक में रोजगार विहीन विकास के प्रतिमान से दूर जाना होगा। हमें स्वरोजगार और हरे और डिजिटल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम जनसांख्यिकीय लाभान्श के अवसर को खत्म कर देंगे, जो एक राष्ट्र के जीवन में एक बार आता है। यदि हम केवल 2000-2020 की गति, लगभग 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त आजीविका उत्पन्न करते हैं, तो हम 2030 में 61 करोड़ की अनुमानित श्रम शक्ति में से लगभग 9 करोड़ से अधिक बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में तीसरे स्थान पर है, हम बेरोजगारों की इतनी बड़ी संख्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसके सभी प्रतिकूल सामाजिक परिणाम हैं।

और उसी समय, नौकरियों में वृद्धि की खोज में, हमें वित्तीय और पर्यावरण दोनों की स्थिरता पर भी ध्यान देना चाहिए। अन्यथा, हम विकास और नौकरियों की समस्या को कभी भी समाप्त नहीं कर पायेंगे। और इससे भी बदतर खराब टैक्स के आधार विज्ञापन से राजकोषीय घाटा, जो सरकार बनाने का अंत कर सकता है और एक अपमानित वातावरण COVID जैसी जलवायु परिवर्तन या जूनोटिक बीमारी से हमारी रक्षा करने में असमर्थ। तो ऐसे डायस्टोपिया (मनहूस) की ओर कौन बढ़ना चाहेगा। 1992 से 1994 के बीच मैंने 10 अन्य सहयोगियों के साथ भारत में ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसमें 8 राज्यों और 80 उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया। जब हमने चीन का उदाहरण दिया, जहाँ 10.0 करोड़ से अधिक लोग खेतों से टाउनशिप और ग्राम उद्यमों (टीवीई) में चले गए थे 1995 में जारी गैर-कृषि क्षेत्र के अध्ययन की हमारी रिपोर्ट ने तर्क दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए भारत को भी ऐसा करने की जरूरत है, ताकि बढ़ती ग्रामीण आबादी को काम मिले, और काम की तलाश में बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर प्रवास से बचा जा सके। फिर भी, 2001 से 2011 के बीच, 14 करोड़ से अधिक लोग भारत में प्रवासियों की श्रेणी में शामिल हुए।

2008 में मुझे भारत की पहली आजीविका परिस्थिति (SOIL) रिपोर्ट का अवलोकन अध्याय लिखने का सौभाग्य मिला, जो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली द्वारा लाया गया। अंतिम पंक्ति में, हमने लिखा था, "दशक की चुनौती तब केवल नई नौकरियाँ नहीं है, बल्कि मौजूदा आजीविका को और अधिक आय उत्पन्न करने के लिए, स्थिर और स्थायी तरीके से ऐसा करें।" हमने 2007 से 2012 के बीच 5.8 करोड़ नौकरियों के सृजन के ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की सराहना की है। इसके बजाय, 2012 तक वास्तव में 50 लाख से अधिक व्यक्तियों के रोजगार में गिरावट आई थी।

यह आजीविका संवर्धन के लिए अंतिम पुकार है। हमें इस दशक में 12 करोड़ स्थायी आजीविका उत्पन्न करने की आवश्यकता है। COVID महामारी से पहले, वाक्यांश 20/20 दृष्टि का मतलब एक "पूर्ण दृष्टि" था। महामारी के बाद, 20/20 का अर्थ "बुरी दृष्टि" में बदल गया है। हालाँकि, हमें इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। शायद इस संकट का सबसे अच्छा परिणाम हमें उस तरह के भविष्य के लिए एक आदर्श दृष्टि देना है, सचेत करना है जिसे हमें बनाने की जरूरत है। जिस तरह के भविष्य के लिए हमें निर्माण करने की जरूरत है। इसके बाद, जीडीपी का अर्थ है ग्रीन, डिजिटल और लोग या जे सी कुमारप्पा ने "स्थायी अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था" के रूप में कल्पना की थी।

7 उद्धरण

भारत की जनगणना, 2001, भारत एक नज़र में - व्यापक आयु समूहों द्वारा जनसंख्या

देवेंद्र सिंह (2019) ओपिनियन इंडिया का जनसांख्यिकीय लाभांश लंबे समय तक रहेगा

फिशर, थॉमस और विजय महाजन (1996) भूल गया सेक्टर - ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में रोज़गार और उद्यम

गोल्डहर, बिश्वनाथ (2009) भारत में विनिर्माण में रोज़गार सृजन पर व्यापार का प्रभाव। दिल्ली: आर्थिक विकास संस्थान

गोल्डिन, सी (1995): "आर्थिक विकास और आर्थिक इतिहास में यू-आकार की महिला श्रम शक्ति समारोह," महिलाओं की मानव पूँजी में निवेश, टी पी शुल्त्स (एड), शिकागो। शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2020), विश्व आर्थिक आउटलुक डेटाबेस। सटीक वेबलिंग के लिए एंडनोट देखें

कुमारप्पा, जेसी (1945) अर्थव्यवस्था की स्थायीता; सर्व सेवा संघ, वाराणसी, 1984 को पुनः प्रकाशित किया गया।

विजय महाजन, मोना दीक्षित और कौशिकी राव (2008) अवलोकन शंकर दत्त, और विपिन शर्मा (Eds) भारत की आजीविका परिस्थिति - 4P रिपोर्ट, नई दिल्ली, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज

विजय महाजन, प्रशांत रेजी और जगमीत सिंह (2020) संतोष मेहरोत्रा (एड) 2020 में जॉब क्रिएशन के लिए एक रणनीति रिवाइजिंग जॉब्स एन एजेंडा फॉर इंडियाज ग्रोथ, पेंगुइन रैंडम हाउस, इंडिया

मेमन के और सी पैक्ससन (2000): "महिला कार्य और आर्थिक विकास," सामान्य आर्थिक परिप्रेक्ष्य, वॉल्यूम 14, संख्या 4, पीपी 141-64

संतोष मेहरोत्रा, और शर्मिष्ठा सिन्हा (2017) "उच्च विकास अवधि के दौरान महिला रोज़गार में गिरावट आना" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक में एल ॥.39, पीपी। 54-62,

मोटोशाही के (2015) जापानी फर्मों के लिए भारत का नीमराना औद्योगिक पार्क ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी में स्प्रिंगर टेक्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स स्प्रिंगर, टोक्यो

(एनएसएसओ) नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (2005) किसानों का मूल्यांकन आकलन सर्वेक्षण, खेती के कुछ पहलू, राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 59 वाँ दौर, (जनवरी-दिसंबर 2003)

(NSSO) राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण संगठन (2013) भारत में रोज़गार और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतक, राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 68 वां दौर 2011-12

(NSSO) राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण संगठन (2015) 2013 में भारत में कृषि परिवारों के प्रमुख संकेतक, राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 70 वाँ दौर 2012-13

(MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2019) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) (जून 2017 - जून 2018)

परांजोथी टी और एच के मिश्रा (2017) धुंडी सोलर पंप इरिगेटर्स कोऑपरेटिव: एक प्रारंभिक अध्ययन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस, एशिया पैसिफिक

भारतीय गुणवत्ता परिषद (2019) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमवृत्ति कार्यक्रम मध्यावधि समीक्षा

प्रशांत रेजी, (2019) भारत में रोज़गार: संरचनात्मक समस्याएँ रोज़गार स्थिति का विश्लेषण और आगे का रास्ता। नीति देखो, अप्रैल 2019 राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली

संजीव कुमार और फाल्गुनी पट्टनायक (2020) भारतीय उद्योगों की रोज़गार तीव्रता में क्षेत्रीय विषमता: एक राज्य-स्तरीय विश्लेषण जर्नल ऑफ़ इमर्जिंग इकोनॉमी स्टडीज़ खंड 6, अंक 1. नई दिल्ली,
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2394901520907729>

तुषार शाह, (2020)। भारत के गोबर पिरामिड के निचले भाग में फॉर्च्यून को अनलॉक करना, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। 56, अंक संख्या 4, 23 जनवरी, 2021
<https://www.epw.in/journal/2021/4/special-articles/unlocking-fortune-bottom-indias-gobar-pyramid.html>

वेद प्रकाश सिंह, (2020) भारत में किसान उत्पादक कंपनी (FPC) कंसोर्टियम को समझना, नई दिल्ली, राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली

के दीवान वर्मा, सी भारद्वाज, पी भटनागर, ए पंत, ए सारा, एल एन तिवारी, (2017) नौकरियाँ हम बनाएँ: उद्यमिता की शक्ति। काम 4 प्रगति भारत, विकास विकल्प और ला कैक्सा फाउंडेशन

ज़ियाओलन फू और वी एन बालासुब्रमण्यम (2002), चीन में टाउनशिप और ग्राम उद्योग लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्कूल वर्किंग पेपर।

8 टिप्पणियां

एनएसएस (2001)। रिपोर्ट नंबर 455 (55/10/1) भारत में रोज़गार और बेरोजगारी 1999-2000 प्रमुख परिणाम http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/455_final.pdf

http://mospi.nic.in/sites/default/files/Statistical_year_book_india_chapters/Labor%26Employment.pdf

http://mospi.nic.in/sites/default/files/Statistical_year_book_india_chapters/Labor%26Employment.pdf

http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Annual_Report_PLFS_2018_19_HL.pdf

भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 7 जनवरी 2021 को उद्धृत किया गया

[https://www.thehindu.com/business/Economy/indias-real-gdp-estimated-to-contract-by-77-in-2020-21/article33521311.ece#:~:text=India's%20real%20GDP%20\(Gross%20Domestic,Office%20\(NSO\)%20on%20Thursday.](https://www.thehindu.com/business/Economy/indias-real-gdp-estimated-to-contract-by-77-in-2020-21/article33521311.ece#:~:text=India's%20real%20GDP%20(Gross%20Domestic,Office%20(NSO)%20on%20Thursday.)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=534,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PPPSH,PCPIPCH,&sy=1980&ey=2020&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1

<https://www.livemint.com/Opinion/zAculvXlzlML7N2Q10L2H/Employment-elasticity-almost-zero.html>

चक्रवर्ती (2018) रोज़गार में वृद्धि को भूल गए, भारत में रोज़गार वास्तव में 2014 से 2016 के बीच गिर गया

www.livemint.com/Politics/sYBQOalLczD2rlAqE0xoWL/Forget-job-growth-employment-in-India-fell-between-2014-and.html

(ILO) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन(1999) वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी के लिए काम का निर्णय: एक ILO परिप्रेक्ष्य

<https://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/1999/seattle.htm>

<https://www.worldometers.info/world-population/india-population/>

महाजन, आदि 2020

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/half-of-rural-india-still-doesnt-own-agricultural-land-secc-2011/articleshow/48062767.cms?from=mdr>

<http://statisticstimes.com/economy/india/indian-states-gdp-per-capita.php>

<https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/2-years-after-metoo-movement-poor-indian-women-fear-losing-their-jobs-over-workplace-harassment-complaintsormetoo-2-years-on-indian-women-in-informal-sector-rarely-report-workplace-harassment-over-fear-of-losing-job/articleshow/78680850.cms?from=mdr>

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/KI-68th-E%26U-PDF.pdf

भारतीय रिजर्व बैंक। 2012. "गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत"

<https://web.archive.org/web/20140407102043/http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15283>

मनरेगा पोर्टल http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard_new.aspx?Fin_Year=2020-2021&Digest=ueg/HtV54GGJ8ZQ6GUB2ew

यह जनसांख्यिकी, व्यावसायिक स्थिति, भूगोल और क्षेत्रीय प्रोत्साहन का एक संक्षिप्त रूप है
भारत की जनगणना, 2001, भारत एक नज़र में - व्यापक आयु समूहों द्वारा जनसंख्या
https://censusindia.gov.in/census_data_2001/india_at_glance/broad.aspx

ILRT (2020) भूमिहीन कृषि श्रमिकों और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका बहाल करने पर वेबिनार: चुनौतियाँ और रास्ता, 25 सितंबर 2020

देवेन्द्र सिंह(2019)

<https://www.livemint.com/Opinion/zgCdZ3GrDwtDpQWD95HenO/OpinionIndias-demographic-dividend-will-play-out-over-a.html>

<https://www.livemint.com/Politics/FL93KP1b9OtQmNnDOJeNxl/Why-PhDs-want-to-be-peons.html>

<https://www.livemint.com/politics/policy/2-40-crore-candidates-applies-for-jobs-in-1-4-lakh-vacancies-in-indian-railways-11603440686441.html>

MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कृषि -I भारत में असमान गैर(2017)
वें दौर 73 के प्रमुख संकेतक एनएसएस (निर्माण को छोड़कर) उद्यमों, 16-2015

भारत में असिंचित गैर के प्रमुख संकेतक (निर्माण को छोड़कर) कृषि उद्यमों'

http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/NSS_KI_73_2.34pdf

https://www.researchgate.net/publication/24083952_Township_and_Village_Enterprises_in_China

<https://www.prindia.org/theprsblog/migration-india-and-impact-lockdown-migrants>

<https://www.civilsocietyonline.com/interviews/basic-worker-protections-taken-away-under-new-labour-codes/>

ग्राइस सर्वे http://www.ice360.in/uploads/files/ice360-survey-2016-design-and-validation_1.pdf

श्रम ब्यूरो पर रिपोर्ट। चंडीगढ़। श्रम 2018 सर्वेक्षण (पीएमएमवाई) प्रधानमंत्री योजना (2018)
औररोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

http://labourbureaunew.gov.in/UserContent/PMMY_2018.pdf?pr_id=tYh3584B20A%3D

2003-04 और 2014-15 के लिए नैस्कॉम आईटी-बीपीएम अवलोकन और निर्यात

(UNCTAD) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन(2008) भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कैसे प्रभावित हैं: एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण https://unctad.org/system/files/official-document/ditctnecd2010d7_en.pdf

गोल्डार (2009) <http://iegindia.org/upload/pdf/wp297.pdf>

<https://www.census2011.co.in/transgender.php>

यह भारत की हरियाली, उच्च विकास क्षेत्रों में नई कुशल नौकरियों के अवसर, डिजिटल सेवाओं और छोटे शहरों और शिल्प समूहों के साथ समर्थ जिले का एक संक्षिप्त रूप है।

http://www.baifwadi.org/download/BAIF_case_study.pdf

नाबार्ड आदिवासी विकास निधि <https://www.nabard.org/about-departments.aspx?id=5&cid=470>

<https://factly.in/explainer-what-are-campa-funds/>

https://mitra.ibm.gov.in/pmkkkky/Pages/National_Dashboard.aspx

<http://moef.gov.in/division/forest-divisions-2/green-india-mission-gim/about-the-mission/>

http://164.100.47.193/lsscommittee/Estimates/16_Estimates_30.pdf

<https://www.hindustantimes.com/india-news/over-300-migrant-workers-in-kandhamal-dig-canal-through-hills-to-bring-water-to-their-land/story-mXJHFifapX4fkjVQMSkKSL.html>

[https://www.teriin.org/sites/default/files/2018-04/Vol per cent20 per cent20- per cent20Macroeconomic per cent20assessment per cent20of per cent20the per cent20costs per cent20of per cent20land per cent20degradation per cent20in per cent20India_0.pdf](https://www.teriin.org/sites/default/files/2018-04/Vol%20per%20cent%20Macroeconomic%20assessment%20of%20the%20costs%20of%20land%20degradation%20in%20India_0.pdf)

सिराज हुसैन (2020) पंजाब के कृषि क्षेत्र के अतीत के गौरव पर विश्राम नहीं कर सकते

<https://thewire.in/agriculture/punjab-farmers-production-past-glory>

<https://www.financialexpress.com/opinion/how-dairy-cooperatives-have-showcased-a-model-for-realisation-of-atmanirbhar-bharat-in-post-covid-19-era/2024142/>

<https://wrmsglobal.com/secufarm/index.html>

[http://www.iwmi.cgiar.org/iwmi-tata/PDFs/dhundi solar energy producers cooperative society-tri-annual report-2015-18.pdf](http://www.iwmi.cgiar.org/iwmi-tata/PDFs/dhundi_solar_energy_producers_cooperative_society-tri-annual_report-2015-18.pdf)

<https://www.icaap.coop/icanews/dhundi-solar-pump-irrigators-cooperative>

<https://www.nationalheraldindia.com/india/rajasthan-farmers-can-now-produce-solar-power-on-their-non-arable-land>

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/first-of-its-kind-godhan-nyay-yojana-launched-in-chhattisgarh/articleshow/77063907.cms>

<https://www.recycling-magazine.com/2020/05/06/waste-management-crisis-in-india/#:~:text=Urban%20India%20generates%2062%20million,just%2011.9%20million%20is%20treated>

मोना दीक्षित, (2019) भारत-चीन व्यापार और निवेश कार्य पत्र 2, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर

कंटेनररी स्टडीज, नई दिल्ली <https://www.rgics.org/wp-content/uploads/RGICS-Working-Paper-2-India-China-Trade-and-Investment-May-2019.pdf>

<http://terrafirmabiotech.com/About-us.html>

<resource-recovery-from-waste-brief-12-large-scale-composting-for-revenue-generation.pdf>

QCI - भारत की गुणवत्ता परिषद, (2019) <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1651525>

उद्यमशीलता के आधार के रूप में डेविड मैकेलैंड की उपलब्धि और उपलब्धि पर काम

<https://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/motivation-entrepreneurship/achievement-motivation-kakinada-experiment/40677>

मौमिता देब चौधरी (2019) <https://www.crn.in/news/gu/Guwahati-the-emerging-tech-hub-of-north-east/>

<https://www.thehindu.com/business/staff-preference-is-for-small-rural-offices/article32364264.ece> और **नंदिका त्रिपाठी, फोर्ब्स (जून 2020) श्रीधर वेम्बु की दृष्टि से गांव** <https://www.forbesindia.com/article/big-bet/cover-story-sridhar-vembu-vision-from-the-village/59833/1>

<https://government.economictimes.indiatimes.com/tag/dalberg>

<http://img.asercentre.org/docs/ASER%202018/Release%20Material/aser2018nationalfindings.pdf>

https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/NABARD%20SMFT%202019-20_compressed.pdf

<https://m.dailyhunt.in/news/nepal/marathi/max+maharashtra-epaper->

[maxmar/1700+garajuvant+kutumbanch+pot+bharanara+kashtakari+sangharsh+mahasangh-newsid-n179294654](https://m.dailyhunt.in/news/nepal/marathi/max+maharashtra-epaper-maxmar/1700+garajuvant+kutumbanch+pot+bharanara+kashtakari+sangharsh+mahasangh-newsid-n179294654)

<https://www.newsclick.in/exclusive-trade-unions-for-migrant-workers-across-country>

महाजन, आदि (2008) <https://livelihoods-india.org/publications/all-page-soil-reb.html>

कुमारप्पा, जेसी (1945) <https://www.mkgandhi.org/ebks/economy-of-perman.pdf>





RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies

Jawahar Bhawan,
Dr Rajendra Prasad Road,
New Delhi 110 001
India

Please visit us at:

web: www.rgics.org



<https://www.facebook.com/rgics/>



<https://www.youtube.com/user/RGICSIndia>